www.dhyeyaias.com

मार्च 2020 | अंक 02

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

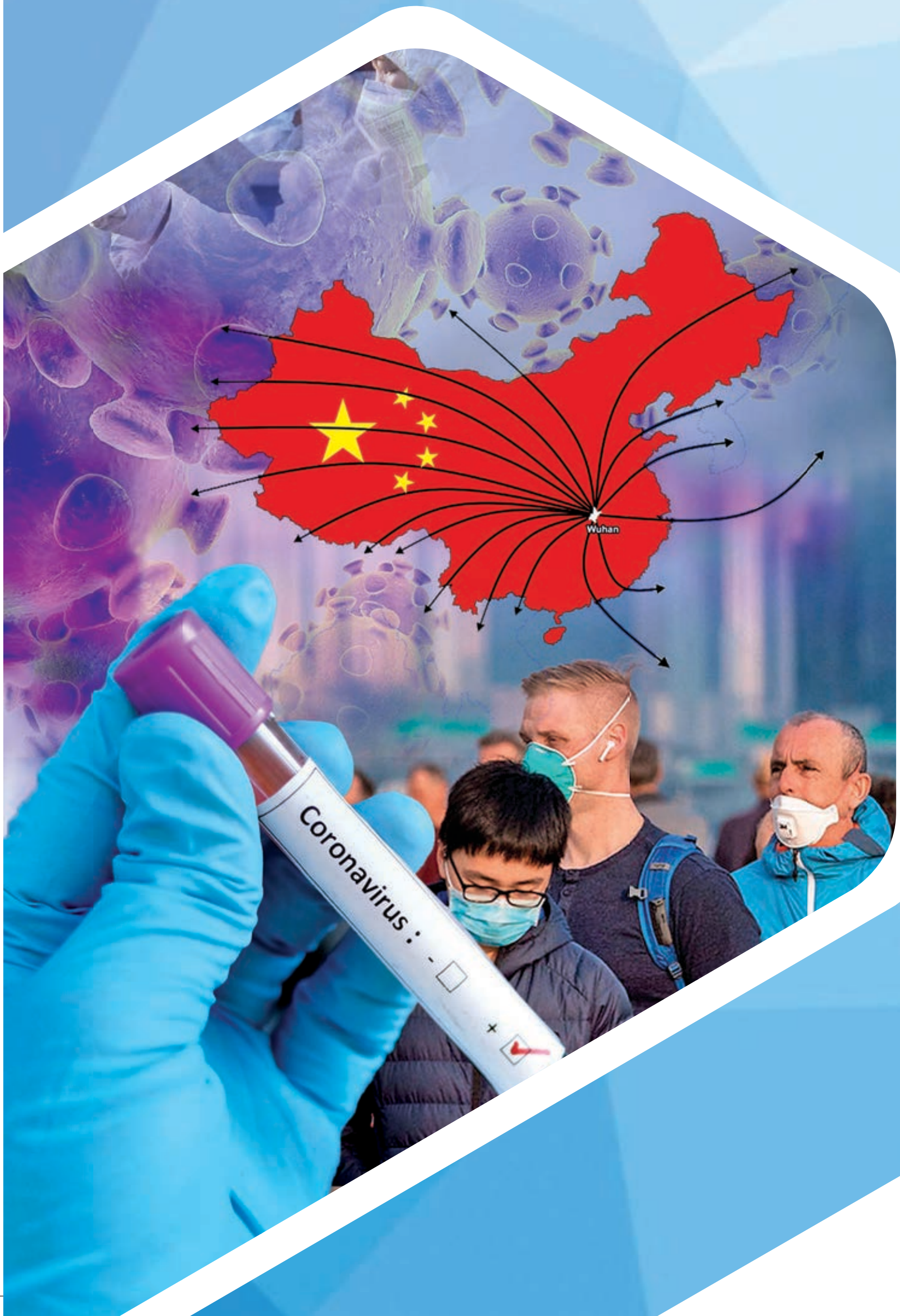

1 वैश्विक जगत के लिए बड़ा सबक
कोरोना वायरस

2 सामुदायिक रेडियो: ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना का सशक्त माध्यम

3 बच्चों के स्वस्थ जीवन और भविष्य पर लांसेट की रिपोर्ट

4 शहरों की बुनियादी ढाँचों में आधुनिकीकरण की आवश्यकता

5 भारत और अमेरिका के संबंधों में नयी ऊर्जा का संचार

6 प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन 2020: एक अवलोकन

7 कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में पश्चिमी घाट की भूमिका

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ध्येय IAS®

most trusted since 2003

सामान्य अध्ययन

भारतीय राजव्यवस्था

द्वारा

विनय सिंह

23 MARCH

11:30 AM

MUKHERJEE NAGAR DELHI

011-49274400

ध्येय IAS
एक परिचय

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सीईओ
ध्येय IAS

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक
ध्येय IAS

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

'PERFECT 7' के इस नवीन एवं रंगीन संस्करण की शुरुआत के साथ आप सभी को ध्येय IAS की ओर से होली की रंगों और उमंगों भरी शुभकामनाएँ।

PERFECT7
एक परिचय

कुरबान अली
प्रधान संपादक
ध्येय IAS

मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि **'PERFECT 7'** का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय टीम को मेरी शुभकामनाएँ। शुरूआत से ही **ध्येय IAS** द्वारा प्रकाशित **'PERFECT 7'** को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है। इसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

ताज़ा तरीन जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.dhyeyaias.com और यूट्यूब चैनल देखें।

आशुतोष सिंह
प्रबंध सम्पादक
ध्येय IAS

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम **'PERFECT 7'** रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें **'PERFECT 7'** के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर **'PERFECT 7'** को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षित रूप में आपके सामने लाया जाता है।

गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है, हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब **'PERFECT 7'** अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

आपके द्वारा दिये गए सुझाव और माँग को ध्यान मे रखते हुए हम रंगों के इस त्यौहार होली के सुअवसर पर **'PERFECT 7'** के रंगीन संस्करण की शुरुआत कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि इस नवीन संस्करण से आप सभी छात्रों में नवीन ऊर्जा का संचार हो, साथ ही **ध्येय IAS** से आपका प्रेम एवं स्नेह सदैव बना रहे।

प्रस्तावना

हमने **'PERFECT 7'** पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर **'PERFECT 7'** में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन **'PERFECT 7'** को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। **'PERFECT 7'** के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। **'PERFECT 7'** के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्रा सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए **'PERFECT 7'** पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय **IAS**

संघ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने **'PERFECT 7'** पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। **'PERFECT 7'** पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका,फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। **'PERFECT 7'** के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। **'PERFECT 7'** के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त **'PERFECT 7'** पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय **IAS**

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

ध्येय टीम

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.	•विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	•क्यू.एच.खान
मुख्य संपादक	•कुरबान अली
प्रबंध संपादक	•आशुतोष सिंह
संपादक	•जीत सिंह •ओमवीर सिंह चौधरी •रजत झिंगन •शशिधर मिश्रा
संपादकीय सहयोग	•प्रो. आर. कुमार •बाघेन्द्र प्रताप सिंह
मुख्य लेखक	•अजय सिंह •अहमद अली •गिर्राज सिंह तोमर •धर्मेन्द्र मिश्रा •रमा शंकर निषाद
लेखक	•अशरफ अली •विवेक शुक्ला •स्वाति यादव •हरिओम •अंशु •सौम्या उपाध्याय
मुख्य समीक्षक	•रंजीत सिंह •रामयश अग्निहोत्री •राजहंस सिंह
त्रुटि सुधारक	•संजन गौतम
विज्ञापन एवं प्रोन्नति	•गुफरान खान •राहुल कुमार
प्रारूपक	•विपिन सिंह •रमेश कुमार, •कृष्णा कुमार •निखिल कुमार
टंकण	•कृष्णकान्त मण्डल
लेख सहयोग	•मृत्युंजय त्रिपाठी •बाघेन्द्र प्रताप सिंह •स्नेहा तिवारी
कार्यालय सहायक	•हरीराम •संदीप •राजू यादव •शुभम •अरुण त्रिपाठी •चंदन

Content Office

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House
Near Chawla Restaurants
Dr. Mukherjee Nagar
Delhi-110009

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

मार्च 2020 | अंक ➲ 02

विषय सूची

7 महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर 01-22

- कोरोना वायरस: वैश्विक जगत के लिए बड़ा सबक
- सामुदायिक रेडियो: ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना का सशक्त माध्यम
- बच्चों के स्वस्थ जीवन और भविष्य पर लांसेट की रिपोर्ट
- शहरों की बुनियादी ढाँचों में आधुनिकीकरण की आवश्यकता
- भारत और अमेरिका के संबंधों में नयी ऊर्जा का संचार
- प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन 2020: एक अवलोकन
- कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में पश्चिमी घाट की भूमिका

✳ 7 ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 23-31

✳ 7 महत्वपूर्ण तथ्य 32

✳ 7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न 33

✳ 7 महत्वपूर्ण खबरें 34-36

✳ 7 महत्वपूर्ण बिंदु: साभार पीआईबी 37-40

✳ 7 महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ: ग्राफिक्स के माध्यम से 41-44

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English
Current Affairs
Monthly News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

7 महत्वपूर्ण मुद्दे

(परीक्षा हेतु)

01 कोरोना वायरस: वैश्विक जगत के लिए बड़ा सबक

चर्चा का कारण

चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान (Wuhan) से शुरू होने वाला कोरोना वायरस धीरे-धीरे पूरी दुनिया में फैल गया है। अमेरिकन रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुसार, अगर कोरोना वायरस एक महामारी का रूप लेता है तो समूचा विश्व आर्थिक मंदी की स्थिति में जा सकता है। इसके अतिरिक्त बैंक ऑफ अमेरिका के अर्थशास्त्रियों के अनुसार, कोरोना वायरस की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर 2.4 फीसदी रहने का अनुमान है।

परिचय

31 दिसंबर, 2019 को चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर में निमोनिया के कई मामले पाए जाने पर यह विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के संज्ञान में आया। जाँच के दौरान वर्तमान वायरस का किसी भी ज्ञात वायरस से मेल नहीं हुआ। इसने एक गंभीर समस्या को जन्म दिया क्योंकि जब कोई वायरस नया होता है तो उसके बारे में यह जानकारी नहीं होती कि यह लोगों को कैसे प्रभावित करेगा। लगभग एक सप्ताह बाद 7 जनवरी को चीनी अधिकारियों ने पुष्टि की कि उन्होंने एक नए वायरस की पहचान की है। इस नए वायरस को कोरोना वायरस नाम दिया गया जो SARS (Sever acute respiratory syndrome) और MERS (Middle East Respiratory Syndrome) जैसे वायरस के समान है। इस नए वायरस को डब्ल्यूएचओ द्वारा 'COVID-2019' नाम दिया गया।

ऐसे स्थान जहाँ मनुष्यों और जानवरों में अनियमित रक्त और अन्य शारीरिक संपर्क जैसा संबंध स्थापित होता है, वहाँ पर इस वायरस का अधिक प्रसार होता है। चीन के पशु बाजार ऐसे ही स्थलों के उदाहरण हैं जहाँ जानवरों से मनुष्यों में वायरस के संचरण की अधिक संभावना है। चीन के बाजारों में जानवरों का माँस बिकने के कारण ये बाजार मानव में वायरस की प्रतिक्रिया को बढ़ावा देते हैं। जब एक, बड़ा मानव समुदाय इस वायरस के संचरण श्रृंखला में शामिल हो जाता है तो उत्परिवर्तन (Mutation) की स्थिति उत्पन्न होती है जो कि मानव समुदाय के लिये घातक सिद्ध होती है। ज्ञातव्य है कि चीन में 1.4 बिलियन पशुधन हैं जो उसकी आबादी के 50% हैं।

कोरोना वायरस क्या है

डब्ल्यूएचओ (WHO) के अनुसार कोरोना वायरस सी-फूड से जुड़ा एक विशिष्ट वायरस फैमिली से संबंधित है। कोरोना वायरस की सतह पर क्राउन (Crown) जैसे कई उभार होते हैं, इन्हें माइक्रोस्कोप में देखने पर सौर कोरोना जैसे दिखते हैं। इसलिये इसका नाम 'कोरोना वायरस' है। यह वायरस ऊंट, बिल्ली और चमगादड़ सहित कई पशुओं में भी पाया जाता है।

कोरोना वायरस के लक्षण

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, इस वायरस के सामान्य लक्षणों में बुखार, खाँसी और साँस की तकलीफ जैसी शारीरिक समस्याएँ शामिल हैं। वहीं गंभीर संक्रमण में निमोनिया, किडनी का फेल होना शामिल है जिससे मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है।

डब्ल्यूएचओ द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव

अल्कोहल-आधारित साबुन और पानी का उपयोग करके हाथ साफ करना चाहिए। खाँसते या छींकते समय मुँह और नाक को ढ़कना चाहिए। तथा बुखार और खाँसी से प्रभावित किसी भी व्यक्ति के निकट संपर्क से बचना चाहिए। यदि बुखार, खांसी और साँस लेने में कठिनाई हो रही है तो जल्द से जल्द चिकित्सिक से संपर्क कर जानकारी साझा करना चाहिए। बाजार में भ्रमण करते समय वर्तमान में कोरोनोवायरस के मामलों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिये जानवरों के संपर्क से बचना चाहिए। कच्चे या अधपके पशु उत्पादों के सेवन से भी बचने की सलाह डब्ल्यूएचओ द्वारा दी गई है।

कोरोना वायरस का विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव

अर्थव्यवस्था पर प्रभावः चीन से फैले कोरोना वायरस की चपेट में दुनिया भर के कई देशों के आने से वैश्विक कारोबार में गिरावट देखी गई है। कोरोना की वजह से दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन और अमेरिका के कारोबार में सुस्ती देखी जा रही है। रिसर्च एवं रेटिंग एजेंसी मूडीज एनालिटिक्स की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर में कोरोना की वजह से 0.4 प्रतिशत की गिरावट हो सकती है। ज्ञातव्य है कि पहले वर्ष 2020 के लिए वैश्विक विकास दर में 2.8 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया था जिसे वर्तमान में घटाकर अब 2.4 प्रतिशत कर दिया है।

- मूडीज एनालिटिक्स की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की विकास दर में 0.2 फीसदी की गिरावट के साथ 1.7 फीसदी रहने का अनुमान है।
- चीन विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक एवं दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। चीन का विश्व निर्यात में लगभग 13 प्रतिशत तथा आयात में लगभग 11 प्रतिशत हिस्सा है। लॉकडाउन (Lockdown) की वजह से चीन में 500 मिलियन लोगों पर असर पड़ा है, जिससे वस्तुओं की खपत बुरी तरह प्रभावित हुई है। कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण चीन की तेल खपत में 30 प्रतिशत गिरावट का अनुमान है। वहीं चीन के जीडीपी विकास की बात की जाए तो यह 2020 के प्रथम तिमाही में 4.5 प्रतिशत रहेगी जो गत वर्ष के अंतिम तिमाही में 6% थी।
- वैश्विक रेटिंग एजेंसियों के अनुसार, यदि कोरोना वायरस एक महामारी का रूप लेता हे तो इससे वैश्विक आय में 1.1 मिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है।

स्वास्थ्य पर प्रभावः चीन में कोरोना वायरस से लोगों की मौत का सिलसिला जारी है, इस बीमारी से अब तक चीन में लगभग 3000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इस विषाणु के कारण सर्वाधिक मौतें अकेले हुबेई प्रान्त में हुई जो इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है। चीन में इससे प्रभावित लोगों की संख्या लगभग 80,000 है। दुनिया के अन्य हिस्सों में अब तक 100 से अधिक मौतें हो चुकी हैं, जिनमें-दक्षिण कोरिया, डायमंड प्रिंसेज क्रूज (जापान), इटली, ईरान, जापान, हॉन्गकॉन्ग, ताइवान, फ्रांस, फिलीपीन्स जैसे देश हैं।

पर्यटन पर प्रभावः मूडीज एनालिटेक्स की रिपोर्ट के अनुसार, चीन का पर्यटन कारोबार पूरी तरह से ठप्प है। विदेशी एयरलाइंस चीन नहीं जा रहे हैं और क्रूज यात्रा भी रद्द हैं। चीन के प्रभावित होने से विश्वभर में पर्यटन प्रभावित हो रहा है। विदित हो कि अकेले चीन से लगभग 30 लाख लोग अमेरिका तथा यूरोपीय देशों में घूमने जाते हैं। वहीं इटली में कोरोना वायरस के फैलने से पर्यटक अब यूरोप जाने से भी कतराने लगे हैं। इस प्रकार यूरोपीय पर्यटन भी प्रभावित हुआ है। इसी सिलसिले में विभिन्न देशों ने पर्यटकों के साथ-साथ धार्मिक यात्राओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।

विमानन उद्योगः इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) के अनुसार कोरोना वायरस से विमानन उद्योग को लगभग 30 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। IATA के अनुसार सिंतबर, 2001 को अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के बाद विमानन उद्योग को हुए नुकसान (19.6 अरब डॉलर) से यह कहीं ज्यादा है।

वैश्विक खेलों पर प्रभावः भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (NRAI) के अनुसार, कोरोना वायरस के डर से इस बीमारी के केन्द्र सहित छह देशों ने चीन में होने वाले निशानेबाजी विश्वकप से हटने का फैसला किया है। ज्ञातव्य है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 पर भी कोरोना वायरस का साया मंडरा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के अनुसार मई आखिर तक अगर कोरोना वायरस पर काबू नहीं पाया जाता है तो ओलंपिक खेल रद्द किए जा सकते हैं। इस प्रकार अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल भी प्रभावित हो सकते हैं।

संसेक्स पर प्रभावः कोरोना वायरस ने दुनिया के शेयर बाजारों को भी ज्यादा प्रभावित किया है। हाल ही में डाऊ जोंस में 1200 अंकों की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई अन्य संसेक्सों की बात की जाए तो नैस्डैक में 400 अंकों, SGX (सिंगापुर) लगभग 2% तथा वैश्विक बाजार में 250 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। विदेशी बाजारों का असर भारतीय संसेक्स पर भी दिखाई दिया। ज्ञातव्य है कि भारतीय संसेक्स में 1000 से अधिक अंकों की गिरावट देखने को मिली। गिरावट का बड़ा कारण निवेशकों द्वारा बाजार से पैसा निकालने को माना जा रहा है।

भारत पर कोरोना वायरस का प्रभाव

- अर्थशास्त्रियों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोरोना का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव पड़ सकता है। आपूर्ति चेनशृंखला प्रभावित होने से कई चीजों के लिए कच्चे माल की कमी हो सकती है तो कई चीजें सस्ती भी हो सकती है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशंस के अनुसार- कच्चे माल की कमी और उत्पादन लागत बढ़ने की सूरत में आयात बिल भी बढ़ सकता है।
- कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते चीन में संचालित भारतीय कंपनियों को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन कंपनियों का राजस्व घट रहा है और अनियोजित खर्च बढ़ रहा है। साथ ही जानलेवा वायरस से डरे कर्मचारियों को बनाए रखने की भी एक बड़ी चुनौती है जो भारतीय कंपनियां चीन से अपना कच्चा माल आयात करती हैं, उनके लिए भी अपनी जरूरतों को पूरा करना कठिन हो रहा है।
- कंफेडेरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) ने 'नोवल कोरोना वायरस इन इंडिया एन इंपेक्ट एनालिसिस' शीर्षक से एक सर्वे रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि चीन में 130 भारतीय कंपनियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती कर्मचारियों को रोकने और उनकी भर्ती करने की है, क्योंकि अधिकतर लोग अपने घर के पास ही काम करना चाहते हैं और ज्यादा दूर तक यात्रा करने से डर रहे हैं। सर्वे में बताया गया है कि छुट्टियों के विस्तार से उत्पादकता घट गई है, जिसका सीधा असर

राजस्व और विकास दर पर पड़ा है। चीन में कई जगहों पर व्यापार पिछले दो-तीन महीनें से बंद है। चीन में भारतीय कंपनियां इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, आईटी एंड बीपीओ, लॉजिस्टिक्स, केमिकल, एयरलाइन और टूरिज्म जैसे सेक्टर्स से जुड़ी हैं। कंपनियों का अनुमान है कि पहली और दूसरी तिमाही में उनके राजस्व में 15 से 20 फीसद की गिरावट आ सकती है।

- कोरोना वायरस के प्रभाव को लेकर अपनी रिपोर्ट में सीआईआई ने आगे कहा, वे भारतीय कंपनियां जो चीन से उत्पाद मंगाती हैं या भारत से चीन सामान निर्यात करती हैं, उनके सामने अपने दायित्व पूरा नहीं कर पाने का खतरा है। भारत आयात के मामले में चीन पर काफी हद तक निर्भर है। भारत के कुल इलेक्ट्रॉनिक आयात का 45 फीसद हिस्सा चीन से आता है। मशीनरी का एक तिहाई और ऑर्गेनिक केमिकल्स का करीब 2/5 हिस्सा चीन से आयात होता है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल पार्ट्स और ऊर्वरक जैसे दूसरे उत्पादों का 25 फीसद से ज्यादा आयात चीन से ही होता है। साथ ही भारत की 65-70 फीसद दवा सामग्री और करीब 90 फीसद मोबाइल फोन पार्ट्स का स्रोत चीन ही है। वहीं, निर्यात की बात करें, तो इस मामले में पांच फीसद हिस्से के साथ चीन भारत का तीसरा बड़ा साझेदार है। कोरोना वायरस के चलते ऑर्गेनिक केमिकल्स, प्लास्टिक्स, फिश प्रोडक्ट्स, कॉटन और अयस्क जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर असर पड़ा है।
- जेनेरिक दवाएं बनाने और उनके निर्यात में भारत अव्वल देश है। साल 2019 में भारत ने 201 देशों को जेनेरिक दवाएं निर्यात की हैं और उससे अरबों रुपए कमाए हैं। लेकिन आज भी भारत इन दवाओं को बनाने के लिए चीन पर निर्भर है। भारत दवाओं के उत्पादन के लिए चीन से एक्टिव फार्मास्यूटिकल इनग्रेडिएंट्स (API) आयात करता है। ये दवाईयां बनाने का कच्चा माल होता है। एपीआई का आयात ना हो पाने की वजह से कई कंपनियों के दवाओं के उत्पादन में कमी आ रही है, जिसका असर आने वाले वक्त में दवाओं की वैश्विक आपूर्ति पर दिख सकता है।
- वहीं दूसरी ओर भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्ती के कारण भारतीय ऑटो सेक्टर पहले से ही संघर्ष कर रहा है। ऊपर से भारत स्टेज-VI उत्सर्जन मानक भी लागू करने करने वाला है। ज्ञातव्य है कि चीन से भारत लगभग 10-30% ऑटोमोबाइल घटकों का आयात करता है। इस तरह से इस क्षेत्र पर और संकट गहरा सकता है।
- इसके अलावा चीन में निर्माण गतिविधि ठप्प होने से स्टील, एल्युमीनियम और ताँबे जैसी वस्तुओं की कीमतों में उछाल आ सकता है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती है।
- चीन वैश्विक स्तर पर विभिन्न जींसो (वस्तुओं) का सबसे बड़ा खरीदार है लेकिन चीन की तरफ से माँग में कमी के कारण विश्व स्तर पर कच्चे तेल, कॉपर, सोयाबीन व पोर्क जैसी चीजें सस्ती हो सकती हैं। इस स्थिति का भारत लाभ उठा सकता है।

आगे की राह

- विश्व में नित नए-नए स्वास्थ्य संबंधित प्रकोपों के उभरने की संभावना को ध्यान में रखते हुए विभिन्न देशों को तत्काल चार प्रकार के कदम उठाने की आवश्यकता है-रोगों की प्रारंभिक पहचान और रोकथाम, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में बेहतर सहयोग, स्वास्थ्य प्रणालियों, परिणामों और शिक्षा में अधिक निवेश व पर्यावरण और जैव विविधता की बेहतर देखभाल, जो लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा को सीधे प्रभावित करती हैं।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में पाया गया है कि कोई भी देश किसी भी बड़े संक्रामक रोग से निपटने के लिए तैयार नहीं है। ज्ञातव्य है कि भारत जैसे विकासशील देश तो स्वास्थ्य के मामले में काफी पीछे हैं, तथा इससे निपटने के लिए तैयार भी नहीं हैं। इसलिए विकासशील देशों (जैसे-भारत) को अपने घरेलू दवाइयों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर दवाइयों की पहुँच बाधित न हो।
- इसके अलावा वैश्विक सहयोग को भी मजबूत करने की आवश्यकता है क्योंकि द्विपक्षीय तकरार की वजह से ऐसी बहुत सारी आवश्यक वस्तुओं (जैसे-दवाईयाँ, प्रोफेशनल डॉक्टर्स आदि) की आपूर्ति अकसर बाधित हो जाती है।
- विभिन्न देशों को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, वैश्विक डिजिटल लेन-देन के साथ-साथ रोबोटिक्स को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे यह लाभ होगा कि रोबोटिक्स के माध्यम से विश्व में किसी भी स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को बनाए रखा जा सकेगा। साथ ही दवाईयों की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा सकेगी।
- रोग की रोकथाम व उसका जल्दी पता लगाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में निवेश के मामले में एशियाई देशों को थाईलैण्ड से सबक लेने की आवश्यकता है।
- भारत जैसे- देश के लिए आवश्यक है कि वह स्वास्थ्य व्यय जो जीडीपी का 1.5% से कम है, को बढ़ाए क्योंकि यह मध्यम आय वाले देशों के लिए पर्याप्त नहीं है।
- इसके अलावा भारत में त्वरित निदान के लिए उपकरणों की उपलब्धता, बीमारियों को फैलने से रोकने के उपाय, और सार्वजनिक सूचना अभियान को आधुनिक और तीव्र बनाए जाने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

02 सामुदायिक रेडियोः ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना का सशक्त माध्यम

चर्चा का कारण

हाल ही में केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पूरे देश में 120 सामुदायिक रेडियो को खोजने की स्वीकृति प्रदान की है। विदित हो कि केन्द्र सरकार की योजना देश भर में 700 जिलों में सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोलने की है। इसके लिए सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थाओं, स्वयं सेवी संस्थाओं तथा कृषि विज्ञान केन्द्र को लाइसेंस दिया जाएगा।

परिचय

सामुदायिक रेडियो (Community Radio) एक प्रकार की रेडियो सेवा होती है जो एक निश्चित क्षेत्र के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रसारण सामग्री प्रेषित करती है। इसमें सामान्य विकास के मुद्दे और चिंताएँ प्रेषित की जाती हैं, जो स्थानीयकृत होने के बावजूद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विकास लक्ष्यों से जुड़ी होती हैं।

गौरतलब है कि इसका प्रसारण छोटे से भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित होता है। सामुदायिक रेडियो की स्थापना की लागत भी कम आती है साथ ही इसका संचालन भी सहज होता है। इसे लोगों की सहभागिता से चलाया जाता है। इसके लिए ज्यादा पढ़े-लिखे लोगों की आवश्यकता नहीं होती। या यूँ कहिए कि औपचारिक शिक्षा की जरूरत नहीं होती। इसकी स्थापना के लिए लाइसेंस शुल्क रहित मिल जाता है, जो शुरुआती दौर में पाँच वर्षों के लिये होता है, जिसे बाद में उपयोगिता के आधार बढ़ाया जा सकता है।

सामुदायिक रेडियो महत्वपूर्ण क्यों

सूचना किसी भी देश का विकास करती है तथा देश की संस्कृति को दूसरे देशों तक पहुँचाने का कार्य करती है। भारत में बड़े स्तर पर यह कार्य आकाशवाणी के माध्यम से होता रहा है, पर जब हम बहुत सारे लोगों की बात कहते हैं तो कई लोग छूट जाते हैं। ऐसे में किसी समुदाय को लेकर चला जाय तो सहभागिता आसान हो जाती है। इस संदर्भ में सामुदायिक रेडियो की

अहमियत को निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है-

- स्थानीय लोगों द्वारा आसानी से समझे जाने वाले शब्द और जुमलों का प्रयोग कर समुदायों से स्थानीय भाषाओं में बात करने में, यह सक्षम बनाता है।
- श्रवण (लिसनिंग) क्लब, कॉल-इन-शो तथा विचारों के अन्य प्रकार के आदान-प्रदान के जरिये दोतरफा संवाद के साथ सामाजिक शिक्षण-प्रदान करता है।
- नीति, अनुसंधान एवं अन्य समुदायों को जानकारी देने के लिए स्थानीय ज्ञान जरूरतों एवं मांगों को समुदायों से बाहर तक पहुंचाने का कार्य करता है।
- जिन समुदायों के पास जानकारी एवं ज्ञान के प्रसार के अन्य तरीकें नहीं हैं, उनके लिए इकलौता माध्यम उपलब्ध कराता है।
- आजीविका, सामुदायिक नेताओं, संगठनों एवं प्रशासन जैसे एक-दूसरे से अलग थलग रहने वाले हितधारक समूहों को एक साथ लाने का कार्य करता है।
- आपदा के प्रत्येक चरण आपदा रोकने, उसकी तैयारी करने, आरंभिक सूचना देने, प्रतिक्रिया देने, स्थिति बहाल करने और पुनरुद्धार में निवासियों के बीच जानकारी साझा करने तथा संवाद करने और समुदाय की स्वशासन की क्षमताएं बढ़ाने में सामुदायिक रेडियो की उपस्थिति बहुत जरूरी हो जाती है।
- आधुनिक दिनों के सामुदायिक रेडियो स्टेशन अकसर अपने श्रोताओं के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री भी पेश किया करते हैं, जो कि आवश्यक रूप से वाणिज्यिक रेडियो स्टेशनों द्वारा प्रदान नहीं की जाती है।
- ग्रामीण परिवेश में सबसे बड़ी समस्या युवाओं में कैरियर से सम्बन्धित जानकरी की होती है। उन्हें विभिन्न आयामों की जानकारी देना साथ ही कैरियर से सम्बन्धित कार्यक्रमों में कैरियर काउन्सलर/एक्सपर्ट से मुलाकात और उनकी जिज्ञासाओं का जो पत्र या फोन के माध्यम से आते हैं उसका समाधान सामुदायिक रेडियो के द्वारा किया जा रहा है।
- सामुदायिक रेडियो का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इससे समाज में फैली कुरीतियों के विषय में जानकारी तथा पुरानी रूढ़ियाँ एवं भ्रांतियों के कारण होने वाली समस्याओं पर रोशनी डालना एवं जागरुकता की मुहिम (जैसे रक्तदान, नेत्रदान, महामारी की जानकारी, एच. आई. वी. से बचाव) चलाना सहज हो जाता है।
- सामुदायिक रेडियो का एक अन्य महत्व यह भी है कि वे प्रभावित समुदायों पर केन्द्रित होते हैं और स्थानीय भाषा में सामग्री प्रसारित करते हैं। इससे विशेष भाषा के स्टेशनों द्वारा बचाव अभियान की जानकारी प्रसारित करने में मदद मिल सकती है। चूंकि जानकारी स्थानीय भाषा या बोली में होती है, इसलिए किसी तरह का भ्रम नहीं होता। जोखिम में पड़े जिन इलाकों में फौरन बचाव अभियान की जरूरत है, उनसे जुड़ी जानकारी एवं घोषणाएँ प्रसारित की जा सकती हैं और समुदाय के सदस्यों को सुरक्षित आश्रय स्थलों की सूचना दी जा सकती है, जहां उन्हें सहायता एवं बचाव सुविधा मिल सकती हैं। इस प्रकार स्थानीय लोग प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे घटनाक्रम की एकदम सटीक सूचना प्रदान कर सकते हैं।
- इसके अलावा सामुदायिक रेडियो कृषकों की भागीदारी बढ़ाने के साथ कृषि से सम्बन्धित जानकारी वैज्ञानिकों से दिलवाने तथा उनके बीच में सेतु का कार्य करते हुए उन्हें एक दूसरे से मिलाने का कार्य करती

है ताकि उनके बीच कृषि की तकनीकों का आदान प्रदान हो सके।

- सामुदायिक रेडियो का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योकि इसके माध्यम से महिलाओं के लिये हर प्रकार के विशेष कार्यक्रम जिसमें उनके अधिकारों की जानकारी के साथ-साथ कानूनी मुद्दों पर चर्चा, उनके अस्तित्व के लिये पारिवारिक एवं सामाजिक संरचना में उनका योगदान तथा उन्हें, अपने पैरों पर खड़ा करने संबंधित मुद्दों को कार्यक्रमों का हिस्सा बना के हर विषय में उनके विचारों को सम्मिलित कर महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य किया जा सकता है।
- सामुदायिक रेडियो के माध्यम से ग्रामीणों को शहरों से, एवं शहरी लोगों को ग्रामीण परिवेश से परिचित कराया जा सकता है।
- इसके अतिरिक्त सामुदायिक रेडियो देश के सभी मतदाताओं तक पहुंचने के लिए एक अच्छा माध्यम है। सामुदायिक रेडियो स्थानीय भाषा में जानकारी विकसित कर मतदाता जागरूकता की प्रक्रिया को तथा लोकतंत्र को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- सीआरएस कृषि संबंधी सूचनाओं, मौसम का पूर्वानुमान और फसल संबंधी जानकारियों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। इसके जरिये स्थानीय भाषाओं के माध्यम से कम से कम 50 कार्यक्रमों का प्रसारण कर सकते हैं।
- वहीं दूरस्थ अंचलों में रहने वाले जनजातीय वर्ग के लोगों को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी इन सामुदायिक रेडियो केंद्रों के माध्यम से दी जा सकती है। इस प्रकार के रेडियो केंद्र जनजातीय वर्ग और शासन के बीच सेतु का कार्य भी करेंगे।

भारत में सामुदायिक रेडियो

गौरतलब है कि इस समय भारत में 276 सामुदायिक रेडियो स्टेशन सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इन 276 स्टेशनों में 129 को शिक्षण संस्थान, 132 को समुदाय आधारित संगठन और 15 को कृषि विज्ञान केन्द्र अथवा राज्य कृषि संस्थाएँ चलाती हैं। देश में अभी 78 सीमावर्ती जिले हैं लेकिन सभी सीमावर्ती जिलों में सक्रिय सामुदायिक रेडियो स्टेशन नहीं हैं। 26 जिलों में 51 सामुदायिक रेडियो स्टेशन काम कर रहे हैं। विदित हो कि नेपाल, बांग्लादेश और फिलीपींस में भी ग्रामीण विकास के लिए सामुदायिक रेडियो का प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता है। यही नहीं कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में तो यह काफी लोकप्रिय हैं।

सरकारी प्रयास

- भारत में सामुदायिक रेडियो की आधारशिला सर्वोच्च न्यायालय ने 1995 में रखी जब उसने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह कहा कि रेडियो तरंगे लोक सम्पति हैं।
- इस दिशा में दिसंबर 2002 में सरकार ने एक नीति जारी कर सुस्थापित शिक्षण संस्थानों को सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने की इजाजत दी। कालांतर में विकास और सामाजिक परिवर्तनों को बढ़ावा देने के लिए नवंबर 2006 में सरकार ने एक नया सामुदायिक रेडियो दिशानिर्देश लागू कर गैर लाभकारी संगठनों को भी सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोलने तथा चलाने की अनुमति दे दी। नई नीति ने सामुदायिक रेडियो के लिए विकास, सामाजिक परिवर्तन एवं संबंधित समुदाय की आवाज का मंच बनने के दरवाजे खोल दिए।
- एक गैर-सरकारी संगठन को मिले लाइसेंस से पहला समुदाय आधारित रेडियो स्टेशन 15 अक्टूबर 2008 को उस समय आरंभ हुआ जब आंध्र प्रदेश राज्य के मेडक जिले के पस्तापुर गांव का 'संगम रेडियो' शुरू किया गया।
- ज्ञातव्य है कि हाल ही में एक नई पहल के रूप में भारत के चुनाव आयोग ने भी मतदाताओं को शिक्षित करने और उन तक सूचनाएँ पहुँचाने के लिये देश भर में 150 से अधिक सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (Community Radio Stations) तक पहुँच बनाई है।
- गौरतलब है कि भारत में सामुदायिक रेडियो पर समाचार कार्यक्रम प्रतिबंधित हैं लेकिन सरकार ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि खबर की कुछ श्रेणियों को रेडियो पर प्रसारित करने की अनुमति है, जिनमें खेल समाचार और टिप्पणियां, यातायात और मौसम की स्थिति के बारे में जानकारी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और त्यौहारों के कवरेज, शैक्षिक घटनाओं के बारे में जानकारी, सार्वजनिक बिजली और पानी की आपूर्ति जैसी उपयोगिताओं से संबंधित घोषणाएं, आपदा चेतावनी और स्वास्थ्य सूचना शामिल हैं।
- उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार की मौजूदा योजनाओं के अनुसार सामुदायिक रेडियो आरंभ करने पर 7.5 लाख की सीमा तक 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है।
- समूचे भारत में मध्यप्रदेश इकलौता राज्य है, जहाँ राज्य शासन द्वारा नौ सामुदायिक रेडियो का संचालन किया जा रहा है। आठ रेडियो स्टेशन मध्यप्रदेश के आदिवासी जिलों में स्थापित हैं, तो देश का पहला स्वाधीनता संग्राम पर केंद्रित रेडियो आजाद हिंद भोपाल से संचालित होता है।

चुनौतियाँ

सामुदायिक रेडियो पहल अपने आप में एक नवाचार है जिसका आगामी भविष्य में विशेष महत्त्व है। इस दिशा में सरकार और व्यक्तिगत स्तर पर किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं, बावजूद इसके इस मार्ग में कई चुनौतियाँ हैं, जिसका जिक्र निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत किया जा सकता है-

- सामुदायिक रेडियों संबंधित एक चुनौती पत्रकारिता और तकनीकी कौशल में कमी तथा इससे संबंधित प्रशिक्षण का अभाव है।
- सामुदायिक रेडियो सामुदायिक भागीदारी से ताकत और लोकप्रियता प्राप्त करता है। व्यावहारिक रूप से ऐसा लगता है कि यह कठिन है क्योंकि यह श्रम प्रधान कार्य है। इसके लिए सही दृष्टिकोण, कौशल और उन्नत मोबाइल उपकरणों की आवश्यकता होगी।
- उचित कौशल प्रबंधन के साथ-साथ वित्तीय प्रबंधन का कुशलतम रूप से न होना भी एक चुनौती है।
- मूलभूत बुनियादी सुविधाओं का अभाव जैसे कि बिजली का सभी जगह नहीं पहुंच पाना, स्पष्ट नियामक ढाँचे की अनुपस्थिति आदि भी एक चिंता का विषय है।
- एक दशक बीत जाने के बावजूद हम 500 सामुदायिक रेडियो स्टेशन का आंकड़ा नहीं

पार कर पाये हैं, दरअसल इसकी वजह एक स्पष्ट नियामक ढांचे की अनुपस्थिति जिसमें सामुदायिक रेडियो संचालित होता है।

आगे की राह

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सामुदायिक रेडियो लाभ कमाने के लिए नहीं होते बल्कि यह व्यक्ति विशेष, समूह और समुदायों की अपनी विविध कहानियों को कहने, अनुभवों को बांटने की प्रक्रिया को सुगम बनाते हैं। बावजूद इसकी उपलब्धि अभी भी बहुत कम है। ऐसे में इसको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है इसके लिए निम्न सुझावों को अमल में लाया जा सकता है-

- कम्युनिटी रेडियो फैसिलिटेशन सेंटर को जागरूकता कार्यशाला चलाना चाहिए ताकि लोग सामुदायिक रेडियो के महत्व को समझ सकें।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को अपनी जागरूकता कार्यशालाओं के लिए उन जिलों को चुनना चाहिए जहाँ सामुदायिक रेडियो स्टेशन नहीं हैं।
- सूचना और तकनीकी के इस युग में सामुदायिक रेडियो के बारे में जागरूकता के लिए कुछ नए तरीको को भी अपनाया जाना चाहिए जिससे अच्छे परिणाम सामने आ सकें।
- सरकार को सामुदायिक रेडियो स्थापित करने के लिए आधारभूत संरचनाओं का विकास तेज गति से करना चाहिए जिससे कि इसका फैलाव व्यापक पैमाने पर हो सके।
- सामुदायिक रेडियो से होने वाले फायदे के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए। साथ ही इस प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का और अधिक विस्तार करना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग -गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका।

03 बच्चों के स्वस्थ जीवन और भविष्य पर लांसेट की रिपोर्ट

चर्चा का कारण

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) , यूनिसेफ (United Nations Children's Education Fund) और लांसेट मेडिकल जर्नल द्वारा "द फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड चिल्ड्रेन" नामक रिपोर्ट जारी की गयी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अपने बच्चों के पालन-पोषण तथा खुशहाली से संबंधित सूचकांक (Flourishing Index) में 180 देशों की सूची में 131वें स्थान पर है। इसके अलावा संवहनीयता सूचकांक (Sustanability Index) के मामले में भारत 77वें स्थान पर है।

परिचय

संवहनीयता सूचकांक प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन से जुड़ा है जबकि खुशहाली सूचकांक का संबंध पालन-पोषण माता एवं पांच साल से कम आयु के बच्चों की उत्तर जीविता, आत्महत्या दर, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुविधा, बुनियादी साफ-सफाई और भीषण गरीबी से मुक्ति तथा बच्चे का फलना-फूलना आदि से है। इसमे कहा गया है कि विश्व की संवहनीयता बच्चे के फलने-फूलने की क्षमता पर निर्भर करती है लेकिन दुनिया का कोई भी देश बच्चों को स्थायी भविष्य प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहा है। साथ ही 2015 में निर्धारित 17 सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development

Goals) में देशों द्वारा की गयी प्रगति व निर्धारित वर्ष 2030 में 2% कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को भी रिपोर्ट में उजागर किया गया है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

- इस रिपोर्ट के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि विश्व के नीति निर्माण कर्त्ता भी बच्चों व युवाओं के स्वास्थ्य को सुरक्षित करने, उनके अधिकारों को सुरक्षित करने तथा हमारी पृथ्वी, हमारे पर्यावरण की रक्षा करने में असफल रहे हैं।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि यह सभी देशों के लिए एक 'वैकअप कॉल' (चुनौती) है, इसके लिए वे अपने बच्चों व युवाओं के स्वास्थ्य व भविष्य पर निवेश करें, साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि प्रत्येक बच्चों की आवाज सुनी जाए, उनके अधिकार सुरक्षित किये जायें तथा एक सुरक्षित व बेहतर भविष्य की तरफ उनका मार्ग प्रशस्त हो।
- बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य व भलाई को केन्द्र में रखकर 180 देशों में उच्चतर रैंकिंग प्राप्त करने वाले देशों में नार्वे, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, नीदरलैण्ड हैं। खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में सेंट्रल अफ्रीका, चाड, सोमालिया, नाइजर, माली अंतिम स्थान पर हैं।
- जो देश 2030 तक 2% CO_2 उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब होंगे वे देश हैं-अल्बानिया, आर्मीनिया, ग्रेनेडा, जॉर्डन, ट्यूनीशिया, मोलदोवा, श्रीलंका, वियतनाम तथा उरुग्वे।
- रिपोर्ट में पारिस्थितिकी क्षरण, जलवायु परिवर्तन, शोषणकारी विपणन को भी मुख्य मुद्दा माना गया।
- रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी क्षरण से हो रहे बदलाव से 2100 ई० तक तापमान में 4°C वृद्धि का अनुमान है। इससे जल स्तर में वृद्धि के साथ-साथ बीमारियाँ मुख्यतः विषाणुजनित रोगों में वृद्धि, कुपोषण के कारण विनाशकारी स्वास्थ्य परिणाम भविष्य में विकराल रूप ले सकते हैं।
- इन सभी कारणों से बच्चों व युवाओं के बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त करने के मार्ग में बाधा आयेगी जिसका निदान पाना आवश्यक है।

भारत की स्थिति

- डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ तथा लांसेट द्वारा प्रदर्शित रिपोर्ट में भारत को सतत् स्थिरता सूचकांक में 180 देशों में से 77वां रैंक दी गयी है।
- इसके अलावा अस्तित्व व कल्याण के सर्वोत्तम अवसर पर्याप्त उत्कर्ष सूचकांक में 180 देशों में से 131वीं रैंक दी गयी।
- इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि बच्चों उत्तरजीविता (जीवित रहने के सर्वोत्तम अवसर) व भलाई के लिए बेहतर अवसर हो सकता है जिसके लिए भारत सरकार को और प्रयास करने होंगे।
- रिपोर्ट में कहा गया कि हालांकि भारत में स्वास्थ्य व स्वच्छता में सुधार हुआ है, परंतु भारत को स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च को बढ़ाना होगा।
- हाल ही में नीति आयोग द्वारा एसडीजी सूचकांक 2.0 जारी किया गया था, जिसमें कहा गया कि भारत समग्र प्राप्तांक में सुधार करके 2019 में 60 पर पहुँचा जो 2018 में 57 था।
- सतत विकास लक्ष्य के 6वें लक्ष्य स्वच्छ जल व सफाई में अच्छी सफलता हासिल हुई है। भारत में स्वच्छता व बिजली के क्षेत्र में वृद्धि हुई है जिससे बच्चों व युवाओं के शारीरिक विकास व मानसिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। परंतु अभी भी पोषण व लैंगिग असमानता भारत के लिए एक समस्या बनी हुई है।

भारत सरकार के प्रयास

- हाल ही में फूड सेफ्टी एंड स्टैण्डर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) द्वारा ईट राइट इंडिया मूवमेंट (Eat Right India Movement) शुरू किया गया जिसका उद्देश्य शहरों के साथ-साथ गाँवों में भी भोजन व स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना है। यह अभियान सरकार के प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे-पोषण मिशन, एनीमिया-मुक्त भारत, आयुष्मान भारत योजना व स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ा हुआ है। इसके साथ इस अभियान का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में नमक, चीनी तथा तेल की खपत को 30% तक कम करने का है जो मोटापे व शारीरिक अक्षमता का कारण बनता है, जिससे बच्चे 5 वर्ष से कम की उम्र में ही मोटापे से ग्रसित हो जाते हैं। यूनिसेफ के अनुसार भारत में 80% से अधिक किशोर छिपी हुई भूख से पीड़ित हैं, जो एक प्रकार का कुपोषण है।
- यूनिसेफ की रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में लगभग सभी किशोर किसी न किसी रूप में अस्वस्थ्य या खराब आहार का सेवन कर रहे हैं जिससे कुपोषण की समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं।
- इसी को ध्यान में रखकर FSSAI ने "खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन व स्वस्थ आहार) विनियम, 2019" बनाया है। इसके द्वारा स्कूली बच्चों में जंक फूड की खपत को कम करने के लिए कहा गया है।
- नियमों के तहत स्कूल कैंटीन, मेस हॉस्टल किचेन या स्कूल कैंपस के 50 मी० के दायरे में प्री पैकेज्ड फूड की बिक्री पर रोक लगाई गयी है।
- इसके साथ केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना समेकित बाल विकास योजना (Integrated Child development Scheme) जो कि महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा निष्पादित की जा रही है का मुख्य उद्देश्य बच्चों के विकास व उनके पोषण को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम विश्व के बच्चों के संदर्भ में सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है। समेकित बाल विकास योजना, प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल व अनौपचारिक शिक्षा के साथ पूरक पोषण की सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है। इसमें 0-6 साल तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएँ, बच्चों के पालन-पोषण में जुटी माताओं के स्वास्थ्य देखभाल की जानकारी शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरूआत 1 जनवरी 2017 को देशभर में गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं के कल्याण हेतु शुरू की गयी थी।
- गौरतलब है कि भारत में केन्द्र सरकार द्वारा 1985 में आँगनबाड़ी योजना की शुरूआत की गई जिसे 2010 में राज्य सरकारों का भी सहयोग प्राप्त हुआ। वर्तमान में आँगनबाड़ी योजना के अंतर्गत 6 वर्ष की आयु के लगभग 7 करोड़ बच्चों को सम्मिलित किया गया है।

उपर्युक्त योजनाएँ उत्कर्ष सूचकांक में दिये गये आधार संपन्नता व उत्तरजीविता को मुख्य विषयों यथा शैक्षिक आधार, पोषण स्तर, मातृ अस्तित्व, 5 साल से छोटे बच्चों का जीवन-मृत्यु दर, बुनियादी स्वच्छता, स्वास्थ्य से संबंधित हैं, जिनपर ध्यान देकर तथा आमूलचूल परिवर्तन कर भारत आने वाले वर्षों में बच्चों व किशारों को बेहतर भविष्य प्रदान कर सकता है।

चुनौतियाँ

डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ तथा लांसेट मेडिकल पत्रिका द्वारा जारी रिपोर्ट में आने वाले भविष्य की चुनौतियों की तरफ बड़ी बारीकी से ध्यानाकर्षित किया गया है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण समस्या जो वैश्विक स्तर पर व्याप्त है, निम्नलिखित हैं-

- रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी भी देश द्वारा बच्चों के भविष्य उनके स्वास्थ्य व स्वच्छतापूर्ण पर्यावरण को पर्याप्त रूप से संरक्षण नहीं प्रदान किया गया है।
- सर्वे के मुताबिक एक साल के अन्दर एक देश में टेलीविजन पर 30,000 से अधिक शराब व तंबाकू के विज्ञापन प्रसारित किये जाते हैं। इन विज्ञापनों से बच्चों के मस्तिष्क तथा स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है।
- अमेरिका में दो वर्षों के अन्दर बच्चों द्वारा ई-सिगरेट विज्ञापनों को देखने का दर 250% तक बढ़ गया है।
- इसके अलावा वैश्विक स्तर पर मोटापे के शिकार बच्चों व युवाओं की संख्या में 11 गुणा इजाफा हुआ है। 1975 में मोटापे से ग्रसित बच्चों की संख्या 11 मिलियन थी जो 2016 में बढ़कर 124 मिलियन तक हो गयी है।
- इसका कारण शोषणकारी विपणन शैलियाँ हैं, जिसमें जंक फूड, शुगर ड्रिंग्स का बढ़ चढ़ कर व्यवसाय किया जाता है।
- रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि वैश्विक स्तर पर 250 मिलियन से ज्यादा बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, वे बौनेपन का शिकार हो रहे हैं, जिसका कारण गरीबी से लड़ने के उचित उपायों

को अनदेखा करना है साथ ही इसका प्रभाव यह भी पड़ता है कि बच्चे व युवा अपने विकास की क्षमता को पार ही नहीं कर पाते हैं।

- रिपोर्ट में कार्बन के उत्सर्जन के कारण जलवायु परिवर्तन पर भी चिंता व्यक्त की गई है, जिसमें कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन दूरगामी अच्छे परिणाम नहीं देगी जिसका बुरा प्रभाव बच्चों व युवाओं पर पड़ेगा।

आगे की राह

- बेहतर भविष्य के लिए कार्बन का उत्सर्जन कम करना होगा तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों को इस धरती पर बेहतर भविष्य प्राप्त हो सके।
- सतत् विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बच्चें के विकास व भलाई को केन्द्र में रखकर ही कार्य करना होगा।
- स्थानीय, राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर पर विशेष बदलाव की आवश्यकता है, अर्थात बहुक्षेत्रीय सहयोग पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
- वाणिज्यिक विपणन में शासन के सहयोग से विनियमन की आवश्यकता है।
- ऐसे समुदायों व एजेंसियों की आवश्यकता है जो मौलिक रूप से उनके काम करने की तरीकों को बदलने को तैयार हों।
- उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखकर, बच्चों व किशोरों के भविष्य व उनके वर्तमान की रक्षा के लिए स्थिरता लानी होगी जिससे बच्चों व युवाओं के भविष्य में संपन्नता व उत्तरजीविता को बढ़ावा जा सके। साथ ही वैश्विक विरादरी को हानिकारक वाणिज्यिक विपणन प्रथाओं का विनियमन करने की आवश्यकता है, ताकि स्वास्थ्य को संरक्षित करने के लिए इस क्षेत्र में निवेश किया जा सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

04 शहरों की बुनियादी ढाँचों में आधुनिकीकरण की आवश्यकता

संदर्भ

भारत 21वीं सदी के तीसरे दशक में प्रवेश कर चुका है। दूसरे दशक के दौरान शहरी भारत के लिए कई कार्यक्रमों और योजनाओं की शुरूआत हुई तथा उन्हें लागू किया गया। इस दौरान कई योजनाओं ने तो बेहतर प्रदर्शन किया लेकिन कई योजनायें आज भी प्रगति और बेहतरी की राह खोज रहीं हैं। विदित हो कि शहरों के विकास की राह इन योजनाओं के रास्तों से ही होकर गुजरता है, अतः 2020 का वर्ष इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा।

शहरों का स्थिति

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा समय में दुनिया की आधी आबादी शहरों में रह रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2050 तक भारत की आधी आबादी महानगरों और शहरों में रहने लगेगी और तब तक विश्व की आबादी का सत्तर फीसद हिस्सा शहरों में रह रहा होगा। संयुक्त राष्ट्र के ही एक अन्य आंकड़े के मुताबिक साल 2018 से 2050 के बीच बढ़ने वाली आबादी में 35 फीसद हिस्सेदारी भारत, चीन और नाइजीरिया की होगी।

ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के एक स्टडी के मुताबिक साल 2019 और 2035 के बीच सबसे तेजी से बढ़ने वाले सभी शीर्ष 10 शहर भारत में हैं। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक, भारत

की जनसंख्या का 31.16 फीसद हिस्सा शहरों में रहता है। भारत की शहरी आबादी का लगभग 17.4% झुग्गी-झोपड़ी में रहता है। जनगणना 2011 के अनुसार 2.9% शहरी घर टूटे-फूटे हालत में हैं। शहरी क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 70% का योगदान करते हैं लेकिन भूमि आधार पर मात्र 4% का हक रखते हैं।

विदित हो कि अगले बीस सालों में 180 मिलियन नौजवान देश की सेवा कार्य बल में शामिल हो जाएंगे और यह जनसमूह भी देश की शहरी जनता में तब्दील हो जाएगा। शहरों की बढ़ती संख्या और शहरीकरण की तेज रफ्तार के बावजूद देश के शहर अभी मूलभूत गुणवत्ता की जिंदगी प्रदान करने में असमर्थ हैं।

भारतीय शहरों में बुनियादी सुविधाओं का अवलोकन

- विशेषज्ञों का कहना है कि देश के शहरों में जलापूर्ति मात्र 105 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, जबकि जरूरत कम से कम 150 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन की है और आदर्श आपूर्ति मात्रा 220 लीटर प्रतिदिन होनी चाहिए। इसके अलावा पाइप से आपूर्ति होने वाला पानी केवल 74 प्रतिशत शहरी जनसंख्या तक पहुँच पाता है।
- वर्तमान में शहर के सीवेज और सेप्टिक टैंक कवरेज का फायदा केवल 63 प्रतिशत शहरी जनसंख्या को मिल रहा है। शहर में बने सीवेज में संसाधित सीवेज केवल तीस प्रतिशत हैं, जबकि 100 प्रतिशत की जरूरत है। संपूर्ण जमा अपशिष्ट कचरे में केवल 72 प्रतिशत ठोस अपशिष्ट जमा किया जाता है। साथ ही बारिश या बाढ़ इत्यादि से शहर में घुसे पानी को हटाने के लिए सड़कों पर केवल 20 फीसद नालियाँ ही काम कर रही हैं।
- उल्लेखनीय है कि सार्वजनकि यातायात के लिए मास पब्लिक ट्रांजिट का इस्तेमाल 30 प्रतिशत लोग ही कर पाते हैं, जबकि यह कम से कम 50 प्रतिशत लोगों को उपलब्ध होना चाहिए और आदर्श मानकों में 82 प्रतिशत होना चाहिए। शहर में वाहन संकुलन प्रति लेन 170 किलोमीटर है, जबकि ट्रैफिक की समस्या से बचने के लिए यह 112 और आदर्श स्थिति में 85

होना चाहिए। प्रति 1000 लोगों पर केवल दो हॉस्पिटल बेड हैं, जबकि सामान्यतः चार और आदर्श अवस्था में सात होने चाहिए।

- शहर में स्लम जनसंख्या 24 प्रतिशत है जबकि यह शून्य होनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में प्रति शिक्षक 48 विद्यार्थी हैं, जबकि सही शिक्षण व्यवस्था कायम करने के लिए प्रति 16 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए।
- माना जा रहा है कि 2030 में शहरी जनसंख्या की अनुमानित वृद्धि के हिसाब से जलापूर्ति की मांग 2.3 गुना बढ़कर189 मिलियन लीटर प्रतिदिन हो जाएगी। सीवेज का पानी भी 2.3 गुना बढ़ जाएगा यानी प्रतिदिन 151 मिलियन लीटर हो जाएगा।

सरकारी प्रयास

अगले कुछ दशकों में भारत में शहरीकरण में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना है। दुर्भाग्य से, शहरीकरण में, भारत विश्व औसत से नीचे है। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार शहरों को स्वच्छ व आधुनिक बनाने के लिए कई योजनाओं को चालू किया जिसे निम्नलिखित बिन्दुओं के तहत देख सकते हैं-

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन योजनाः जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना का शुभारंभ 3 दिसम्बर 2005 (JNNURM)भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इस योजना को पूरा करने का समय 7 साल था फिर इस योजना को 2 साल तक और बढ़ा दिया गया जिसे 31 मार्च 2014 तक खत्म करना था। लेकिन समुचित परिणाम न मिलने के कारण इस योजना को वर्ष 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि भारत में शहरों की उन्नति की गति को तीव्रता प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत भारत के शहरों व नगरों में सुविधाओं के विकास हेतु लक्ष्यों को लागू करने एवं उन्हें पूरा करने का प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत पिछड़े इलाकों एवं गरीब लोगों तक सुविधाओं को पहुँचाना है।

अमृत मिशनः अमृत मिशन को जून 2015 में लॉन्च किया गया था। अमृत मिशन का उद्देश्य देश के सभी शहरों में जलापूर्ति, साफ-सफाई और सीवेज कनेक्शन प्रदान करना है। वित्त वर्ष 2015 से पाँच साल के लिए अमृत मिशन पर 5000 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य रखा गया था। केंद्र सरकार ने देश के 500 शहरों का कायाकल्प करने के लिए शुरू की गयी अमृत मिशन के लक्ष्य को दो साल तक के लिए बढ़ा दिया है। अमृत मिशन में मार्च 2020 तक 77,640 करोड़ रुपये खर्च किये जाने हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजनाः प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) एक सरकारी होम लोन योजना है, जिसे जून 2015 में, भारत सरकार ने सस्ते घर प्रदान करने उद्देश्य से शुरू किया था। इसका उद्देश्य 31 मार्च, 2022 तक योग्य परिवारों / लाभार्थियों को पानी के कनेक्शन, शौचालय की सुविधा और 24 घंटे बिजली की आपूर्ति के साथ 2 करोड़ से अधिक पक्के मकान प्रदान करना है। निजी कंपनियों की मदद से सरकार का उद्देश्य झुग्गी में रहने वाले परिवारों को अपने लिए शहरों में घर लेने में मदद करना है। इसके अलावा, योजना एक नए घर के निर्माण या मरम्मत के लिए कमजोर और मध्यम आय वर्गों के लिए क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी यानी लोन प्रदान करती है।

स्मार्ट सिटी मिशनः स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रस्तावित परियोजनाओं में से 81 प्रतिशत को मंजूरी दे दी गई है, जबकि 25 प्रतिशत परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं। स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) के तहत आने वाले शहरों को 2,05,018 करोड़ रुपये प्रस्तावित किये गए थे। इसके तहत कुल 5,151 प्रोजेक्ट थे। इसका मकसद इन शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

मिशन में भाग लेने वाले शहरों ने कुल नियोजित परियोजनाओं का 25 प्रतिशत (1296) पूरा कर लिया है। इस मिशन में सार्वजनिक निजी भागीदारी (Public Private Partnership) के माध्यम से लगभग 20 प्रतिशत वित्त पोषण की भी योजना है। केंद्र सरकार ने 100 स्मार्ट सिटी विकसित करने के लिए जून 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन का शुभारंभ किया था। मिशन का उद्देश्य उन शहरों को बढ़ावा देना है जो कोर इन्फ्रॉस्ट्रक्चर प्रदान करते हैं, और लोगों को एक स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण प्रदान करते हैं।

हृदय योजनाः शहरों की विरासत को संभालने और उसको संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने 21 जनवरी 2015 को हृदय अर्थात् धरोहर शहर विकास और संवर्द्धन योजना (Heritage city development and Augmentation Yojana) योजना की शुरुआत की। हृदय योजना के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। इस योजना में देश के 12 शहर अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलंकन्नी और वारंगल शामिल किये गये हैं।

स्वच्छ भारत अभियानः स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ-सुथरा करना है। यह अभियान 02 अक्टूबर, 2014 को आरंभ किया गया।

स्वच्छ भारत का उद्देश्य व्यक्ति, क्लस्टर और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के माध्यम से खुले में शौच की समस्या को कम करना या समाप्त करना है। स्वच्छ भारत मिशन विसर्जन उपयोग की निगरानी के जवाबदेह तंत्र को स्थापित करने की भी एक पहल सरकार ने 2 अक्टूबर 2019, महात्मा गांधी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ पर किया ताकि ग्रामीण भारत में 1.96 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 1.2 करोड़ शौचालयों का निर्माण करके खुले में शौच मुक्त भारत (ओडीएफ) के लक्ष्य को हासिल किया जा सके।

चुनौतियाँ

भारत सरकार द्वारा शहरों के आधुनिकीकरण के लिए शुरू की गई इन योजनाओं के बावजूद भी कई समस्यायें अभी भी विद्यमान हैं, जिसे निम्नलिखित बिन्दुओं के तहत देखा जा सकता है-

जब हम भारत में शहरीकरण की पहले की चुनौतियों और इनका सामना करने वाले शहरी स्थानीय निकायों की प्रतिक्रियाओं को देखें, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि पिछले कई दशकों से बड़ी तेजी से हो रहे शहरीकरण ने शहरी स्थानीय निकायों को अपनी सीमित भौगोलिक सीमाओं के दायरे में रह कर ज्यादा आबादी की सेवा करने को मजबूर किया है। इस तथ्य का एक और अर्थ स्पष्ट है कि इन स्थानीय निकायों को नई संपत्तियां सृजित करने को मजबूर होना पड़ा है। उन्हें नई सड़कें बनानी ही होंगी, पानी की आपूर्ति बढ़ानी होगी। सीवेज सिस्टम को बेहतर बनाना होगा। सड़कों पर नई स्ट्रीट लाइटें लगानी होंगी और कचरा उठाने के ज्यादा इंतजाम करने

होंगे। लगभग इन सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए नई संपत्तियों के सृजन की जरूरत होती है। इसके अतिरिक्त सभी शहरों को, खास तौर से बड़े शहरों को भारत सरकार द्वारा लायी गई नई योजनाओं को लागू करने का बोझ भी उठाना पड़ा है। हर शहर ने अपने स्तर पर इन योजनाओं को ही तरजीह दी है। क्योंकि अब शहरों की गुणवत्ता का निर्णय इसी आधार पर हो रहा है कि उन्होंने भारत सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं को कितनी कुशलता से लागू किया है।

लेकिन, जमीनी स्तर पर ऐसी कुछ और चुनौतियाँ हैं, जिन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। नए सृजित किए गए संसाधनों का रख-रखाव करना पड़ता है। अगर वो अपनी मियाद पूरी कर चुके हैं, तो उन की जगह नए संसाधन तैयार करने होते हैं। इसका ये मतलब होता है कि शहरों के पास मौजूद संसाधनों के बंटवारे में ऐसा संतुलन बैठाना पड़ता है कि नई संपत्तियों का सृजन भी होता रहे और पुराने संसाधनों की मरम्मत और रख-रखाव भी समान रूप से हो। उसके संदर्भ में हम कई अन्य चुनौतियों को देख सकते हैं-

प्रदूषण: शहरीकरण की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण है। शहर में प्रदूषित हवाओं से लोगों को सिलोकोसिस और फेफड़ों के कैंसर जैसी बीमारियाँ हो रही हैं। भारत में प्रदूषण का स्तर विश्व सेहत संगठन से समझा जा सकता है। वर्ष 2016 में इस रिपोर्ट ने विश्व के 15 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों की लिस्ट पेश की थी जिसमें अकेले भारत के 14 शहरों के नाम शामिल थे।

पर्यावरण संबंधित मुद्देः यूएनडीपी के मुताबिक 70% भारतीय आबादी बाढ़ के खतरे और 60% भूकंप से प्रभावित है। घनत्व और अतिसंवेदनशीलता के कारण शहरी क्षेत्रों में जोखिम अधिक है। साल 2015 में चेन्नई में आई बाढ़ को भूला नहीं जा सकता। केरल इसका ताजा उदहारण है। केरल में आए बाढ़ ने पिछले 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिसमें 370 से अधिक लोगों की जाने गईं। यह अनियोजित शहरीकरण का ही परिणाम है।

बढ़ते अपराध: शहरों में बढ़ते अपराध राज्य सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। वर्ष 2019 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के मुताबिक दस लाख की आबादी से अधिक के 63 बड़े शहरों में अपराध बढ़े हैं। देश की राजधानी दिल्ली में 40 फीसदी अपराध दर्ज हुए। इसके बाद मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता तथा हैदराबाद का स्थान है। वहीं सबसे असुरक्षित शहरों की सूची में बिहार का पटना, राजस्थान का जोधपुर और केरल का कोल्लम भी शामिल है।

बढ़ती असमानता: शहरों की आबादी का लगभग एक तिहाई गरीबी रेखा से नीचे रहता है। एक अनुमान के अनुसार भारत की जनसंख्या का पांचवा भाग झुग्गी-झोंपड़ी में रहता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार बंगलुरू में 10 प्रतिशत, कानपुर में 17 प्रतिशत, मुंबई में 38 प्रतिशत तथा कोलकाता में 42 प्रतिशत लोगों के सामने आवास की कठिन समस्या है।

ट्रैफिक जाम: भारत में ऐसा कोई शहर नहीं, जहाँ लोग ट्रैफिक की समस्या से परेशान न हों। दिल्ली में यातायात की समस्या का अध्ययन (2004) बताता है कि सड़कों पर पहले ही लगभग 60 लाख वाहन हैं जो अगले मास्टर प्लान लागू होने पर 2021 तक लगभग दोगुना हो जाएगा, जबकि सड़क की लंबाई आनुपातिक रूप से नहीं बढ़ी है।

बढ़ती झुग्गी-झोपड़ियाँ: शहरीकरण के कारण नगरों में झुग्गी-झोपड़ियों का फैलाव भी बढ़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा 76 कस्बों की संख्या है जो झोपड़पट्टी की आबादी में सबसे अधिक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश (65), तमिलनाडु (63), महाराष्ट्र (62), पश्चिम बंगाल (51), मध्य प्रदेश (42) और कर्नाटक (35) हैं। मध्य मुंबई में धारावी झोपड़ियां एशिया में सबसे बड़ी है। यहाँ की सड़कें इतनी संकीर्ण हैं कि एक साइकिल भी पास नहीं हो सकती।

आगे की राह

उपर्युक्त चुनौतियों के बावजूद भी सरकार द्वारा इस दिशा में लगातार किये जा रहे कार्य सराहनीय हैं। शहरों की समस्याओं को सुलझाने के लिए निम्नलिखित सुझावों को अमल में लाया जा सकता है-

- शहरों की बुनियादी ढ़ाँचें की मरम्मत और आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने योजनाओं का निर्माण तो कर दिया है तथा उसपर कार्य भी हो रहा है। लेकिन इन योजनाओं को जिस तीव्र गति से आगे बढ़ना चाहिए वह उस गति से आगे नहीं बढ़ रहा है। शहरों की समस्यायें अभी भी विद्यमान हैं तथा उनके निवारण के लिए जो सही उपाय हो सकता है वह नहीं हो पा रहा है, इसलिए सरकार को चाहिए कि शहरों के विकास तथा मरम्मत के लिए जो योजनायें चलाई जा रहीं हैं उसका सही से क्रियान्वयन किया जाय।
- शहरों के बुनियादी ढ़ाँचें में सुधार के लिए एक बेहतर उपाय यह है कि जो पुराने शहर हैं, उन्हें नये तरीके से विकसित किया जाय अर्थात सड़कों का चौड़ीकरण, फ्लाईओवर का निर्माण, लाइटिंग की व्यवस्था अपशिष्ट प्रबंधन, ड्रेनेज प्रणाली आदि पर विशेष ध्यान दिया जाय। इसके साथ ही नये शहरों का निर्माण नियोजित तरीके से किया जाय। इससे भविष्य की समस्या को वर्तमान में खत्म किया जा सकता है।
- भ्रष्टाचार भारत में किसी भी योजना के क्रियान्वयन में सबसे बड़ा रोड़ा है, अतः शहरों का विकास समुचित तरीके से हो इसके लिए विभागीय भ्रष्टाचार को रोकना होगा और सभी कर्मचारियों को अपनी जिम्मेवारी तय करनी होगी।
- शहरों को स्वच्छ व सुंदर रखने के लिए जनसंख्या का दबाव भी कम करना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि गावों में भी शहरों की तरह सुविधायें प्रदान की जाये जिससे कि लोगों का शहरों की तरफ पलायन कम हो।
- कुल मिलाकर भारत विकसित राष्ट्र की तरफ तेज गति से आगे बढ़ रहा है तथा विकसित राष्ट्र की परिकल्पना में शहरों का अहम योगदान है। इसलिए केन्द्र तथा राज्य दोनों सरकारों को एक साथ मिलकर शहरों के आधुनिकीकरण के लिए कार्य करना चाहिए। इससे न सिर्फ भारत में शहरों की स्थिति सुधरेगी बल्कि विश्व स्तर पर भी भारत का नाम रौशन होगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

- महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं सम्बद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपचार।

05 भारत और अमेरिका के संबंधों में नयी ऊर्जा का संचार

चर्चा का कारण

हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की यात्रा की। यह उनकी, भारत की पहली यात्रा थी। भारत का दौरा करने वाले ट्रंप सातवें अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं।

परिचय

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के मायने हर किसी के लिए काफी खास रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच इस दौरे में सुरक्षा के क्षेत्र में अहम समझौते हुए हैं। इसके अलावा दोनों ही देशों ने व्यापारिक विवादों के बावजूद कई मुद्दों पर आगे बढ़ने की अपनी बात दोहराई है। ट्रंप के दौरे से दोनों देशों के बीच सामरिक-साझेदारी और अधिक मजबूत हुयी है। दोनों ही देशों के सामने भारत-प्रशांत क्षेत्र (Indio-pacific region) में चीन के बढ़ते कदमों को रोकना एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए अमेरिका को भारत का साथ चाहिए, जिससे इस क्षेत्र में शक्ति का संतुलन बनाकर रखा जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति की इस यात्रा में यह आशंका जताई जा रही थी कि अमेरिका और भारत के बीच डेयरी, पोल्ट्री व अन्य कृषि उत्पादों के आयात से संबंधित कोई समझौता हो सकता है किन्तु ऐसा नही हुआ।

भारत और अमेरिका आज 21वीं सदी के उस समय काल में हैं जब दोनों को अपने कई हित और चुनौतियां साझी लगती हैं। वैश्विक आतंकवाद पर निर्णयक प्रहार करने की बात हो, समुद्री और हिन्द प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा की बात हो, भारत के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती देने की बात हो, द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने की बात हो, इन सभी मामलों में दोनों देशों को एक दूसरे की आवश्यकता है।

हालिया समझौते के मुख्य बिन्दु

- तीन अरब डॉलर के रक्षा सौदे के तहत भारत एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट सिस्टम के साथ अपाचे और एमएच-60 रोमियो हेलीकॉप्टर अमेरिका से खरीदेगा। ट्रंप ने दुनिया के सबसे आधुनिक अमेरिकी हथियारों जिसमें

एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल, रॉकेट से लेकर, ड्रोन, नौसेनिक जहाज आदि को भारत को देने का भी ऐलान किया है।
- भारत, अमेरिकी कच्चे तेल का चौथा और एलएनजी का पांचवा सबसे बड़ा खरीददार बन गया है। भारत को एलएनजी के आयात में कोई परेशानी न आए, इसके लिए एक्सॉन मोबिल और इंडियन ऑयल के साथ एक करार भी हुआ है।
- दोनों देशों के बीच एक समझौता ज्ञापन मानसिक स्वास्थ्य पर हुआ है। जबकि दूसरा समझौता ज्ञापन चिकित्सा उत्पादों की सुरक्षा पर है।

समझौते का अवलोकन

- दोनों देशों के बीच कुल ऊर्जा व्यापार 20 बिलियन डॉलर रहा है। तीन वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में दोगुना बढ़ोत्तरी हुयी है। भारत, अमेरिका का बड़ा डिफेंस पार्टनर है। भारत और अमेरिका में जो हेलीकॉप्टरों की डील हुयी है उससे इंडो-पैसिफिक और दक्षिण-एशिया में स्थायित्व-शांति बनाए रखने में मदद मिलेगी। वहीं रोमियों हेलीकॉप्टरों से भारतीय फौजों की एंटी-सरफेस और एंटी-सबमरीन सुरक्षा क्षमता में इजाफा होगा।
- जानकारों का मानना है कि कि भारत-अमेरिका संबंध 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी में हैं और इसलिए दोनों देशों ने आपसी संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है। दोनों देशों के मध्य ड्रग तस्करी, नार्को-आतंकवाद ओर संगठित अपराध जैसी गंभीर समस्याओं बारे में एक नए मैकेनिजम पर भी सहमति हुयी है। कुछ ही समय पहले दोनों देशों के मध्य स्थापित स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप सुदृढ़ होती जा रही है और इस क्षेत्र में आपसी निवेश बढ़ा है। विदित हो कि अमेरिकी संसद ने पिछले वर्ष भारत को नाटो देशों के समान दर्जा देने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके चलते अब रक्षा संबंधों के मामले में अमेरिका भारत के साथ नाटो के अपने सहयोगी देशों, इजरायल और दक्षिण कोरिया की तर्ज पर ही डील करेगा। हालांकि दोनों पक्ष व्यापार के मामले में अपने मतभेद दूर नहीं कर पाए लेकिन दोनों देशों ने यह उम्मीद जताई है कि जल्द ही इसे लेकर एक बड़ा समझौता होगा।
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा से मेक इन इंडिया में जान फूंके जाने की उम्मीद बढ़ गई है। सरकार और उद्योगपतियों दोनों को इस यात्रा के बाद हुए करार और भविष्य की संभावनाओं से बड़े निवेश का अनुमान है। जानकारों का मानना है कि अमेरिकी निवेश आने वाले समय में भारत की तस्वीर बदल सकता है। अमेरिका का सहयोग कई मोर्चों पर दोनों देशों के लिए मददगार साबित होगा भारत के लिए अमेरिका से नई तकनीक के लिए रास्ते खुलेंगे, वहीं अमेरिका को भारत से बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पाद मिलना आसान हो जाएगा। मेक इन इंडिया के लिए अमेरिका बड़ा निवेशक है। देश को अपशिष्ट प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, स्मार्ट सिटी और अनुसंधान एवं विकास जैसे क्षेत्रों में निवेश की बड़ी जरूरत है। ऐसे में अमेरिका इन सारी जरूरतों के लिए बड़े निवेश के तौर पर उभर कर आ सकता है। इसके अलावा कार्डियक स्टेंट जैसे मेडिकल डिवाइस की कीमत पर भारत सरकार ने जो नियंत्रण लगा रखा है, हो सकता है कि अप्रैल से भारत सभी मेडिकल डिवाइस को दवाओं की तरह ही माने।

- वर्ष 2018 में दोनों देशों के बीच 143 अरब डॉलर यानी 10 लाख करोड़ रुपय का व्यापार हुआ। इसमें अमेरिका को 25 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ। इसकी भरपाई वह दुग्ध और पोल्ट्री उत्पादों का भारत में निर्यात करके करना चाहता है। उसकी कोशिश है कि इन वस्तुओं और अन्य कृषि उत्पादों पर भारत आयात शुल्क घटाने के साथ दुग्ध उत्पादों को बेचने की छूट दे। किंतु इस पर अंतिम सहमति दोनों देशों के बीच नहीं हो पायी है।
- दरअसल अमेरिका में इस समय दुग्ध का उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन इस अनुपात में कीमतें नहीं बढ़ रही हैं। इस बीच अमेरिकी लोगों में दूध की जगह अन्य तरल पेय-पीने का चलन बढ़ने से दूध की खपत घट गई है। इस कारण किसान आर्थिक बदहाली के शिकार हो रहे हैं। यह स्थिति तब है जब अमेरिका अपने किसानों को व्यापक सब्सिडी देता है। इसके उलट भारत में इस मद में बहुत ही कम सब्सिडी दी जाती है। ऐसे में यदि अमेरिकी हितों को ध्यान में रखते हुए डेयरी उत्पादों के निर्यात की छूट दी गई तो भारतीय डेयरी उत्पादक अमेरिकी किसानों से किसी भी स्थिति में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे।
- वर्ष 2018 में अमेरिका ने भारत को रणनीतिक व्यापार प्राधिकरण-1 (STA-1) का दर्जा प्रदान किया। गौरतलब है कि भारत, जापान और दक्षिण कोरिया के बाद तीसरा ऐसा एशियाई देश बना जिसे अमेरिका ने ऐसा दर्ज दिया है। इससे उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों (खासकर अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्रों) को भारत को बेचने का मार्ग प्रशस्त होगा, जो भारत की रणनीतिक क्षमता को मजबूती प्रदान करेगा।

क्षेत्रीय सहयोग

भारत और अमेरिका की रणनीतिक भागीदारी के निर्माण में अंतिम स्तंभ है- स्थायित्व और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए "क्षेत्रीय सहयोग"। इनमें से सहयोग वाले कुछ क्षेत्रों का विवरण निम्नलिखित है-

- अफगानिस्तान, जहाँ शांति, सुरक्षा और समृद्धि को प्रोत्साहन देने में भारत और अमेरिका दोनों के गहरे हित हैं। दोनों देश अफगानिस्तान यें लोकतांत्रिक संस्थानों के निर्माण में सहायता करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। दोनों देश अफगानिस्तान के पुनर्निमाण और भविष्य के लिए, पर्यापत संसाधनों का निवेश कर रहे हैं। यह प्रयत्न न केवल क्षेत्रीय विकास और स्थिरता को बढ़ावा देगा बल्कि आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों को समाप्त करने में भी सहायता करेगा।
- दूसरा सहयोग का क्षेत्र- इस क्षेत्र में अन्य समान विचार वाले देशों के साथ बहुपक्षीय गतिविधियों को बढ़ाना, जिनमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं। भारत अमेरिका और जापान तीनों देश मिलकर मालाबार नौसेनिक अभ्यास कर रहे हैं, इससे इन तीनों के बीच त्रिपक्षीय डॉयलॉग की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। हिन्द प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती समृद्धि और सुरक्षा के लिए साथ ही विविध दृष्टिकोणों पर बातचीत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ चतुर्पक्षीय बातचीत आयोजित की गई है। अमेरिका और भारत को बहुपक्षीय समूहों का विकास जारी रखना चाहिए, और सभी लोकतांत्रिक भागीदारों के साथ सहयोग के अवसर तलाश करते रहना चाहिए। इसी तरह से भारत और अमेरिका को दक्षिण एशिया के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों से संपर्क को प्रोत्साहन देने का प्रयास करते रहने चाहिए, जो आर्थिक रूप से दुनिया में एकीकृत क्षेत्रों में एक है। हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में मानवीय सहायता और आपदा राहत किसी भी आपदा के लिए प्रभावी राहत कार्य नागरिक-सैनिक सहयोग की जरूरत होती है जिसकी योजनाएं बनायी गई हैं तथा उसका अभ्यास और उपाय भी किए गए हैं। अमेरिका और भारत इस कार्य में अलग-अलग क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं और आपदा के समय मिलकर कार्य करने से लाभान्वित हो सकते हैं।

वैश्विक नेतृत्व के लिए साझेदारी

- भारत और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सुदृढ़ करने एवं इनमें सुधार लागू करने और इनकी अखण्डता सुनिश्चित करने के लिए आपस में मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की पुनर्गठित सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन देने की फिर से पुष्टि की है। यही नहीं अमेरिका ने बिना किसी देरी के परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह में भारत के प्रवेश के समर्थन की भी पुष्टि की है।
- भारत और अमेरिका ने यह माना कि विकासशील एवं कम आय वाले देशों में संप्रभु ऋण को बढ़ने से रोकने हेतु कर्जदारों एवं कर्जदाताओं के लिए उत्तरदायी पारदर्शी एवं टिकाऊ वित्तपोषण के तौर-तरीकों को सुनिश्चित करना आवश्यक है। भारत और अमेरिका ने एक बहु-हितधारक पहल "ब्लू डॉट नेटवर्क" की अवधारणा में रूचि दिखाई, जो वैश्विक अवसंरचना के विकास हेतु उच्च गुणवत्ता वाले विश्वसनीय मानकों को बढ़ावा देने के लिए सरकारों, निजी क्षेत्र और सिविल सोसायटी को एकजुट करेगा।
- भारत और अमेरिका ने वित्त, प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन संबंधी पहलों के जरिए महिलाओं एवं बालिकाओं की शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के महत्त्व को रेखांकित किया है। दोनों देशों ने इसके तहत अमेरिका की 'महिलाओं का वैश्विक विकास एवं समृद्धि (डब्ल्यू-जीडीपी) पहल' और भारत सरकार के 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम की तर्ज पर अर्थव्यवस्था में महिलाओं एवं बालिकाओं की पूर्ण और मुक्त सहभागिता को बढ़ावा देने के उपायों पर भी अमल करने पर विशेष बल दिया।
- भारत और अमेरिका एक ऐसे मुक्त विश्वसनीय एवं सुरक्षित इंटरनेट के लिए प्रतिबद्ध हैं जिससे व्यापार एवं संचार में काफी आसानी होगी। भारत और अमेरिका ने एक ऐसा अभिनव डिजिटल परिवेश सुनिश्चित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया जो सुरक्षित एवं विश्वसनीय हो और जिससे सूचनाओं एवं डाटा का प्रवाह सुगम हो।
- दोनों देशों ने रणनीतिक सामग्री एवं महत्वपूर्ण अवसंरचना की मुक्त, सुरक्षित एवं सुदृढ़ आपूर्ति करने और उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग से जुड़े जोखिमों का स्वतंत्रतापूर्वक आकलन करने के लिए दोनों देशों के उद्योग जगत एवं शिक्षाविद्ों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

भारत-अमेरिका संबंधों में चुनौतियाँ

- अमेरिका ने जून 2019 में सामान्य प्राथमिकता

प्रणाली (जीएसपी) के तहत भारतीय उत्पादों को शुल्क में मिलने वाली छूट को समाप्त करने का निर्णय किया था। इस प्रकार जीएसपी भी भारत और अमेरिकी व्यापार संबंधों में बड़ा मुद्दा है। गौरतलब है कि हाल ही में अमेरिका ने भारत को विकासशील देशों की श्रेणी से भी हटा दिया है जो कि जीएसपी विवाद को एक नया आयाम प्रदान करता है क्योंकि जीएसपी का लाभ केवल विकासशील देशों को प्रदान किया जाता है। हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल का उदाहरण देते हुए अमेरिका सदैव यह शिकायत करता रहा है कि भारत एक टैक्स किंग है जो अत्यधिक मात्रा में वस्तुओं के आयात पर टैरिफ लगता है। अत: भारत-अमेरिका के बीच व्यापार में भारत द्वारा टैरिफ में वृद्धि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

- भारत-अमेरिका व्यापार सौदे पर बातचीत वर्ष 2018 से चल रही है, लेकिन टैरिफ, सब्सिडी, बौद्धिक संपदा, डेटा संरक्षण और कृषि एवं डेयरी उत्पादों तक पहुँच इत्यादि बिन्दुओं पर असहमति के कारण यह अभी तक सफल नहीं हो सका है।
- काट्सा एक्ट (CAATSA) के माध्यम से रूस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं, इन प्रतिबंधों के कारण भारत द्वारा रूस से रक्षा प्रणाली खरीदने पर असर पड़ सकता है, इसके अलावा एक समस्या यह भी है कि अगर भारत रूस से दूरियां बनाता है, तो रूस विकसित रक्षा प्रणाली की आपूर्ति पाकिस्तान को कर सकता है, जबकि चीन के पास ऐसी प्रणाली पहले से ही है। इससे क्षेत्रीय स्थिरता और शांति पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसी प्रकार ईरान और वेनेजुएला के साथ अमेरिका के बढ़ते तनाव ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को दांव पर लगा दिया है।
- भारत 80 प्रतिशत से अधिक ऊर्जा जरूरत के लिए तेल और गैस के आयात पर निर्भर है। साथ ही अमेरिका द्वारा बार-बार अफगानिस्तान में अपनी नीति को बदलना भारत की चिंता को बढ़ाता है।

आगे की राह

भारत और अमेरिका को अपने कूटनीतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने की आवश्यकता है तथा दोनों देशों के बीच उत्पन्न व्यापार मुद्दों को आपसी बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। भारत को अमेरिका एवं अन्य देशों के साथ द्वि पक्षीय संबंधों में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को "सच्चा दोस्त" कहा है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री बाजपेयी के कथन को दोहराया कि दोनों देशों "स्वभाविक मित्र" हैं। अब यह दोनों देशों पर निर्भर है कि आगे इस शब्दावली को यथार्थ रूप प्रदान करें। दोनों देशों को एक मजबूत और सतत होने के साथ लचीली और अनुकूल भागीदारी का निर्माण करना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

06 प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन 2020: एक अवलोकन

चर्चा का कारण

हाल ही में कॉप-13 (CoP-13) सम्मेलन भारत के गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का संक्षिप्त नाम CMS-CoP-13 (13th Conference of Parties Cop of the convention on Conservation of Migratory Species of wild Animals) है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय (Theme) "पृथ्वी को जोड़कर रखने में इन प्रजातियों की भूमिका और उनका अपने घरों में स्वागत करना" था।

सम्मेलन के मुख्य बिंदु

- भारत को अगले तीन वर्ष के लिए इस कांफ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया है। इस सम्मेलन के लिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (गोदावण) को शुभंकर बनाया गया है।
- प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के रास्तों पर

विचार-विमर्श के लिए इस सम्मेलन में 130 देशों के लगभग 1200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- गौरतलब है कि मौजूदा समय में विश्वभर की लगभग 10 लाख प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पर हैं।
- सम्मेलन के दौरान सात प्रजातियों को सख्त संरक्षण प्रदान किए जाने की बात की गई। इनमें शामिल हैं- एशियाई हाथी, जगुआर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन, लिटिल बस्टर्ड, ऐतीपोडियन अल्बाट्रोस और सामुद्रिक सफेद शार्क। इनको परिशिष्ट I के तहत सूचीबद्ध किया गया है।
- शेष तीन द यूराल, स्मूथ हैमरहेड शार्क और टोपे शार्क को परिशिष्ट II के तहत संरक्षण के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
- इस सम्मेलन के दौरान 12 लुप्तप्राय प्रजातियों को दर्शाती विशेष यूएन डाक टिकटें जारी की गईं।
- भारत ने इस आयोजन की मेजबानी की तथा बैठक के बाद भारत को प्रांतीय अवधि के दौरान प्रेसीडेंसी के रूप में नामित किया गया।
- COP13 के तहत समुद्री ध्वनि प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण, कीटों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि से उत्पन्न मुद्दे आदि पर भी चर्चा की गयी है।

- बैठक में प्रतिनिधियों ने बात पर भी विचार किया कि प्रवासी प्रजातियों पर सड़क, रेल और अन्य प्रकार के बुनियादी ढांचों के निर्माण से होने वाले प्रभाव को किस तरह कम किया जा सकता है।
- इसके अलावा गैरकानूनी ढंग से वन्यजीवों की हत्या करने व प्रवासी पक्षियों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए मजबूत प्रयासों का खाका तैयार करने और जंगली-समुद्री मीट के लिए लक्षित कार्रवाई पर चर्चा की गई। इस सम्मेलन में गांधीनगर घोषणा-पत्र को अपनाया गया।

गांधीनगर घोषणापत्र

- पारिस्थितिकीय तंत्रों के आपसी संबंध को बनाए रखना और उन्हें बहाल करना सीएमएस की सर्वोच्च प्राथमिकता है-विशेषकर प्रवासी प्रजातियों के पर्यावास के प्रबंधन में। यही आयाम गांधीनगर घोषणापत्र में मजबूती से दर्शाया गया है जिस पर 130 देशों ने मुहर लगाई है।
- इस घोषणापत्र में प्रवासी प्रजातीय और पारिस्थितिकीय तंत्रों के आपसी संबंध को 'पोस्ट-2020 ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क' में एकीकृत करने और प्राथमिकता देने की बात की गई है। इस फ्रेमवर्क के अक्टूबर 2020 में होने वाली संयुक्त राष्ट्र जैवविविधता सम्मेलन में पारित होने की उम्मीद है।
- इस सम्मेलन में प्रवासी प्रजातियों की स्थिति पर पहली "Status of Migratory Species" रिपोर्ट जारी की गयी। रिपोर्ट दर्शाती है कि सीएमएस संधि में शामिल अधिकांश प्रजातियों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है जिनके कारणों को समझने और हर प्रजाति के सामने मौजूद विशिष्ट खतरों की शिनाख्त को अहम माना गया है।
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने वर्ष 2020 को प्रकृति के लिए सुपर-साल (Super year) करार दिया है।
- इस साल होने वाले आयोजनों में जून 2020 में महासागरों पर होने वाला 'महासागर सम्मेलन', सितंबर में प्रकृति पर 'प्रकृति सम्मेलन' और साल के अंत में संयुक्त राष्ट्र जैवविविधता सम्मेलन प्रमुख हैं।

तीन प्रजातियों पर विशेष ध्यान

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के प्रमुख जॉयस म्यूसा ने बताया, एक ऐसे समय जब हम प्रजातियों के खोने के अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहे हैं। वर्ष 2020 प्रजातियों के संरक्षण के लिए कार्रवाई का स्तर बढ़ाने और सतत् विकास लक्ष्यों की दिशा में अर्थपूर्ण प्रगति के लिए एक महत्त्वपूर्ण वर्ष है। इस सम्मेलन में जिन तीन प्रजातियों पर विशेष ध्यान देने की बात की गई है वो निम्न हैं-

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड: ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक प्रसिद्ध, गंभीर रूप से लुप्तप्राय और संरक्षण पर निर्भर पक्षी प्रजाति है, जो प्रवास के लिए भारतीय उपमहाद्वीप की सीमाओं को पार करती है। इसकी आबादी लगभग 100-150 के बीच रह गई है। यह मुख्य रूप से राजस्थान के थार रेगिस्तान तक सीमित है। पिछले 50 वर्षों के दौरान इस पक्षी की आबादी 90% घटी है और भविष्य में आबादी और घटने की आशंका है। इसका मुख्य कारण पाकिस्तान-भारत और सीमावर्ती क्षेत्र में शिकार और भारत में बिजली-लाइन से टकराव है।

एशियाई हाथी: भारत सरकार ने भारतीय हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया है। भारतीय हाथी को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध करके उच्चतम कानूनी सुरक्षा भी प्रदान की गई है। मुख्यभूमि के एशियाई हाथी/भारतीय हाथी भोजन और आश्रय की तलाश में राज्यों और देश के अनेक हिस्सों में लंबी दूरी तय करते हैं। कुछ हाथी निवासी हैं और अन्य हाथी वार्षिक प्रवास चक्रों में नियमित रूप से प्रवास करते हैं।

सीएमएस समझौते की अनुसूची-I में भारतीय हाथी को शामिल करने से भारत की सीमाओं से बाहर भारतीय हाथी के प्रवास की प्राकृतिक जरूरत पूरी होने के साथ-साथ सुरक्षित वापसी भी सुनिश्चित होगी।

नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार की छोटी उप-प्रजाति के साथ अन्तर्मिश्रण से इन हाथियों के आबादी को व्यापक 'जीन' आधार उपलब्ध होगा। इससे इनके प्रवासी मार्गों के कई हिस्सों में मानव हाथी संघर्ष को कम करने में भी मदद मिलेगी।

बंगाल फ्लोरिकन: बंगाल फ्लोरिकन एक प्रसिद्ध, गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति है, जो सीमा पार करके प्रवास करती है। यह प्रवासन में भूमि उपयोग परिवर्तन, भारत-नेपाल सीमा पर बिजली लाइनों से टकराव जैसी चुनौतियों का सामना करती है।

आवास कम होने और अवैध शिकार होने के कारण इनकी आबादी कम हो रही है। यह प्रजाति असम के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर भारतीय उपमहाद्वीप में संरक्षित क्षेत्रों से बाहर प्रजनन नहीं करती हैं।

वर्तमान स्थिति

हाल के दशकों में पक्षी पहले से अधिक पलायन कर रहे हैं, जो भोजन और घोंसले के निर्माण चक्र को बाधित कर सकता है। शोधकर्ताओं का दावा है कि इसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन है। पक्षियों का यह पलायन संभवतः उच्च तापमान के कारण है, जो पिछले कई दशकों से तेज गति से बढ़ रहा है।

पिछले 50 वर्षों से दक्षिण यूरोप से उत्तरी यूरोप की ओर पलायन करने वाली 117 प्रवासी पक्षियों की प्रजातियों पर मिलन विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन किया गया। इस शोध में इन्होंने पाया कि वसंत ऋतु के आगमन में परिवर्तन हो रहा है, जिस कारण पक्षी कभी अपने मूल स्थान पर जल्दी वापस आ जाते हैं, जिससे इन्हें प्रतिकूल मौसम और खराब खाद्य आपूर्ति का सामना करना पड़ता है, परिणामतः इनकी स्थिति संवेदनशील बन रही है। इसके विपरित यदि वे देर से वापस आते हैं तो उन्हें अपने साथियों और क्षेत्रों के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ जाती है।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत में पक्षियों पर संकट गहराता जा रहा है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 79 प्रतिशत पक्षियों की संख्या घटी है, जिनमें से कइयों के विलुप्त होने का खतरा पैदा हो गया है। प्रवासी पक्षिओं पर हो रहे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, सीओपी-13 में 'स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्टः 2020' के जरिए पक्षियों के ताजा आंकड़े सामने आए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, आम धारणा के विपरीत 25 साल से अधिक समय में गौरैया की संख्या लगभग स्थिर है। मोर की संख्या बढ़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार गिद्धों की संख्या लगातार घट रही है। बहुत लंबे समय से जिन पक्षियों की संख्या सबसे तेजी से घट रही है, उनमें व्हाइट रम्प्ड वल्चर, रिचर्ड पिपिट, इंडियन वल्चर, लार्ज-बिल्ड लीफ वार्बलर, पैसिफिक गोल्डन प्लोवर और कर्ल सैंडपाइपर।

हालांकि, गौरैया की संख्या में दिल्ली, मुंबई समेत छह मेट्रो शहरों में थोड़ी गिरावट आई है। जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध पश्चिमी घाटों में साल 2000 से पक्षियों की तादाद में 75 प्रतिशत तक

कम हुई है। इस रिपोर्ट में 867 प्रकार के पक्षियों का अध्ययन कर उनके दीर्घावधि (25 साल) एवं लघु अवधि (पाँच साल) के आंकड़े जुटाए गए। रिपोर्ट में जिन 261 प्रजातियों के दीर्घावधि आंकड़े सामने आए हैं, उनमें से 52 प्रतिशत की संख्या साल 2000 से घट रही है। वहीं, 22 प्रतिशत की संख्या में तेजी से गिरावट आई है।

रिपोर्ट में जिन 146 प्रजातियों के लघु अवधि के आंकड़ों का विश्लेषण हुआ, उनमें से 80 प्रतिशत की संख्या कम हुई है और 50 प्रतिशत की संख्या तो तेजी से गिरी है। इस रिपोर्ट में 101 प्रजातियों के संरक्षण पर अत्यधिक चिंता जताई गई है। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि पक्षियों की 48 प्रतिशत प्रजातियों की संख्या स्थिर रही है अथवा दीर्घावधि में बढ़ी है। लेकिन पिछले पाँच साल में 79 प्रतिशत पक्षियों की संख्या में गिरावट आना चिंताजनक है। रिपोर्ट के अनुसार तेजी से गिरावट वाले पक्षियों में शिकारी पक्षी, प्रवासी समुद्री पक्षी पिछले दशकों में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।

प्रवासी वन्य जीवों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए सम्मेलन (CMS)

यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इसे बॉन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। CMS का उद्देश्य थलीय, समुद्री तथा उड़ने वाले अप्रवासी जीव जंतुओं का संरक्षण करना है। इस कन्वेंशन के द्वारा अप्रवासी वन्यजीवों तथा उनके प्राकृतिक आवास पर विचार विमर्श के लिए एक वैश्विक प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाता है।

इस संधि पर 1979 में जर्मनी के बॉन में हस्ताक्षर किये गये थे। यह संधि 1983 में लागू हुई थी। इसमें अफ्रीका, मध्य तथा दक्षिण अमेरिका, एशिया, यूरोप तथा ओशनिया के 120 हितधारक (स्टेकहोल्डर) शामिल हैं।

भारत और जैव विविधता

भारत दुनिया के सर्वाधिक विविधताओं से भरे देशों में से एक है। दुनिया के 2.4 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र के साथ, भारत ज्ञात वैश्विक जैव विविधता में लगभग 8 प्रतिशत का योगदान करता है। भारत जैव विविधता संरक्षण को लेकर सदैव जागरूक रहा है। वह वन्यजीवों के संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर सदैव सचेत रहता है। इसी का परिणाम है कि भारत ने 2022 की समयसीमा से दो साल पहले ही बाघों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। देश में बाघों की संख्या 1411 से बढ़कर 2967 हो चुकी है।

भारत में जैव विविधता के चार हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं-पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, भारत म्यांमार क्षेत्र तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो विश्व से आने वाले प्रवासी पक्षियों की 500 प्रजातियों का वास है। भारत जिन अनेक प्रवासी प्रजातियों का घर हैं उनमें शामिल हैं हिम तेंदुआ, अमूर बाज, हंस, काली गर्दन वाले सारस, समुद्री कछुआ, ड्यूगोंग एवं कूबड़ा व्हेल।

जहाँ तक पक्षियों का सवाल है तो भारत आने वाले पक्षियों में साइबेरिया से पिनटेल डक, शौवलर डक, कॉमनटील, डेल चिक, मेलर्ड, पेचर्ड, कॉमन सैंड पाइपर के साथ-साथ कलेलिंग जैसे कई पक्षी आते हैं। जबकि भारतीय पक्षियों में शिकरा हरियाल कबूतर, दार्जेन चिड़िया, पिट्टा तथा स्टॉप बिल डक आदि प्रमुख हैं।

विदित हो कि भारत का समुद्री तट 7500 किलोमीटर का है जो जैव विविधताओं संपन्न है और इसमें असंख्य प्रजातियाँ हैं। भारत, आसियान तथा पूर्वी एशिया सम्मेलन के देशों के साथ मिलकर इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। भारत 2020 तक समुद्री कछुआ नीति और समुद्री प्रबंधन नीति लॉन्च करने का मन बना रहा है। इससे माइक्रो प्लास्टिक से उत्पन्न प्रदूषण की समस्या से भी निपटा जा सकता है। ज्ञातव्य है कि एकल उपयोग प्लास्टिक पर्यावरण संरक्षण के लिए चुनौती है और भारत इसके उपयोग में कमी लाने के लिए मिशन मोड में है।

उल्लेखनीय है कि सन् 1983 से ही भारत CMS का सदस्य है। विश्व के प्रमुख पक्षी फ्लाईवे नेटवर्क में भारतीय उपमहाद्वीप भी शामिल है। है। इसे मध्य एशियाई फ्लाईवे (The Contral Asian Flayway-CAF) भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आर्कटिक एवं हिंद महासागर के मध्य का क्षेत्र आता है। विदित हो कि इस क्षेत्र में जलीय पक्षियों की लगभग 190 प्रजातियों में से 30 प्रजातियाँ वैश्विक रूप से संकटापन्न स्थिति में हैं।

कौन हैं प्रवासी पक्षी

प्रवासी पक्षी वे होते हैं, जो अपने इलाके में जीवन जीने की कठिनाई को देखकर भोजन-पानी की तलाश में थोड़े समय के लिये दूसरी जगह कूच कर जाते हैं। वे परिस्थितियाँ अनुकूल होने पर अपनी पुरानी जगह लौट भी आते हैं। चिड़ियों के पैरों में छल्ले पहना कर उनके आने-जाने की मॉनीटरिंग की जाती है।

चुनौतियाँ

- प्रवासी पक्षियों के संरक्षण में सबसे बड़ी चुनौती विभिन्न देशों के मध्य समन्वय का अभाव है। संरक्षण के लिए जो कानून बने हैं उनका भी सही से पालन नहीं किया जाता है।
- चूँकि प्रवासी पक्षी जिस रास्ते से देश के अंदर आते हैं वे रास्ते भी निश्चित नहीं होते है। परिणामस्वरूप इनकी निगरानी करना काफी मुश्किल होता है।
- यहीं नहीं इन रास्तों के बीच में कई अवैध तस्करी भी होती है अर्थात इन रास्तों पर प्रवासी पक्षियों का अवैध शिकार किया जाता है। इन अवैध शिकार एवं तस्करी को रोकना भी एक बड़ी चुनौती है।
- साइबेरियन पक्षी साइबेरिया से जब भारत में आते हैं तो इन दूरियों के बीच स्थित देशों द्वारा इन पक्षियों का शिकार किया जाता हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के तहत सभी देश इनके संरक्षण की बात करते हैं लेकिन पैसों के लालच में इनका शिकार धड़ल्ले से होता है।
- जलवायु परिवर्तन पर सभी देश बड़ी बड़ी बाते करते हैं लेकिन विकास की अंधी दौड़ में कार्बनडाई ऑक्साइड एवं ग्रीन हाउस गैसों का अधिकतम उत्सर्जन हो रहा है। इससे वैश्विक तापमान में तीव्र वृद्धि हो रही है और इसका प्रभाव अन्य प्रवासी पक्षियों तथा वन्यजीवों पर पड़ रहा है।
- संरक्षणवादियों का कहना है कि सीएमएस की सूची वाले जीवों की घटती आबादी के लिए इंसान के हाथों शिकार या फिर प्राकृतिक आवास को नष्ट किया जाना जिम्मेदार है। पशु कल्याण विशेषज्ञों का कहना है कि जैगुआर पिछले एक सदी में अपने आवास का 40 फीसदी हिस्सा खो

चुके हैं। वहीं समुदी व्हाइट टिप शार्क भी शिकार की वजह से लुप्तप्राय शार्क बन गयी हैं। विदित हो कि उनके पंख का सूप एशिया में खूब पसंद किया जाता है।

आगे की राह

- विश्व के सभी देशों को चाहिए कि प्रकृति के द्वारा मानव को जीव जंतु तथा पशु पक्षी के रूप में जो उपहार दिया गया है उसकी सुरक्षा करें।
- मानव का अस्तित्व भी कहीं न कहीं उनके ऊपर निर्भर करता है इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाय। इससे इनकी संख्या में वृद्धि होगी और यह मानव के सहचर्य के लिए लाभदायक होगा।
- विश्व के सभी देशों को चाहिए कि जैव विविधता संरक्षण के लिए जो भी समझौते हुए हैं उनका पालन हो। इससे इन समझौतों की विश्वसनियता बनी रहेगी तथा जैव विविधता को भी बनाये रखा जा सकता है।
- सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वैश्वीतापीकरण को कम किया जाय अर्थात बढ़ते तापमान को नियंत्रित किया जाय जिससे कि इन पशु-पक्षियों के निवासों को सुरक्षित रखा जा सके।
- भारत जैव विविधता संरक्षण की दिशा में बेहतर काम कर रहा है लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। भारत विश्व के सभी देशों के साथ समन्वय स्थापित कर रहा है जिससे कि वन्यजीवों तथा पक्षियों का संरक्षण किया जा सके।
- COP सम्मेलन इस दिशा में एक बेहतर प्रयास है लेकिन ऐसे सम्मेलनों में किये गये समझौतों पर अमल करना अति आवश्यक है, नहीं तो यह सम्मेलन भी सिर्फ एक खानापूर्ति बनकर रह जाएगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच-उनकी संरचना, अधिदेश।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

07 कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में पश्चिमी घाट की भूमिका

संदर्भ

पेरिस में हुए जलवायु परिवर्तन समझौते में भारत ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 33-35 प्रतिशत कमी करने का वादा किया था जिसके लिए जरूरी है कि परती भूमि पर स्थानीय प्रजातियों के पेड़-पौधे लगाकर कार्बन फुटप्रिंट को तत्काल कम किया जाए, भूमि के आच्छादन का विनियमन किया जाए। जिससे कि डीकार्बनाइजेशन यानी कार्बनमुक्त करने की प्रक्रिया को शुरू किया जा सके। गौरतलब है कि भारत के पश्चिमी घाट में यह समस्या बहुत ही विकराल हो रही है इसलिए वैज्ञानिकों तथा पर्यावरणविदों का ध्यान इस ओर गया है।

कार्बन फुटप्रिंट क्या है

कार्बन फुटप्रिंट (Carbon Footprint) का अर्थ किसी एक संस्था, व्यक्ति या उत्पाद द्वारा किया गया कुल कार्बन उत्सर्जन से है। यह उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीनहाउस गैसों के रूप में होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य की सभी आदतें, जिनमें खानपान से लेकर पहने जाने वाले कपड़े तक शामिल हैं, कार्बन फुटप्रिंट का कारण बनते हैं।

दूसरे शब्दों में हर काम के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) गैस निकलती है, जो धरती को गर्म करने वाली सबसे अहम गैस है। हम दिन, महीने या साल में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित (CO_2) करते हैं, वह हमारा कार्बन फुटप्रिंट है। इसे कम-से-कम रख कर ही पृथ्वी को जलवायु परिवर्तन के प्रकोप से बचाया जा सकता है।

पश्चिमी घाट का परिचय

पश्चिमी घाट जैव विविधता के 36 वैश्विक केन्द्रों में से एक है और इस क्षेत्र के वन वायुमंडलीय कार्बन का अवशोषण करते हैं जिससे दुनिया की जलवायु को सामान्य बनाए रखने में मदद मिलती है।

इस क्षेत्र में 4,600 प्रजातियों के फूल वाले पौधे पाये जाते हैं, 330 प्रकार की तितलियाँ, 156 सरीसृप, 500 पक्षी, 120 स्तनपायी, 289 प्रकार की मछलियाँ और 35 उभयचर पाये जाते हैं। यह क्षेत्र 1,60,000 वर्ग कि.मी. में फैला हुआ है और इसे भारत का वाटर टावर माना जाता है क्योंकि अनेक धाराएं यहाँ से निकलती हैं और लाखों हेक्टेयर भूमि से जल की निकासी करती हैं। पश्चिमी घाट की नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों के 24.5 करोड़ लोगों को पानी और भोजन की सुरक्षा उपलब्ध कराती हैं। इस क्षेत्र में ऊष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के साथ-साथ आर्द्र पर्णपाती वन, झाड़ीदार वन, वनखंड और सामान्य व अत्यधिक वर्षा वाले सवाना वन पाये जाते हैं।

पश्चिमी घाट में कार्बन अवशोषण

पश्चिमी घाट की कार्बन अवशोषण क्षमता का मात्रात्मक आकलन कर लिया गया है जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि इस क्षेत्र के वन बायोमास के अनोखे भंडार हैं। यह आकलन वायुमंडलीय कार्बन (मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न) और ग्लोबल वार्मिंग के असर को कम

करने में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित करता है। पश्चिमी घाट के दक्षिणी और मध्यवर्ती भागों में घने स्थानीय वन हैं और यहां की भूमि कार्बन से समृद्ध है (0. 42 एमजीजी)। इसी तरह का रुझान मिट्टी में वृद्धिशील कार्बन अवशोषण में भी देखा गया है जिसमें इसकी मात्रा 520 जीजी (ग्रीन हाउस गैस इमिसन CO_2 इक्यूवैलेन्ट)और पश्चिमी घाट के कर्नाटक तथा मध्यवर्ती केरल वाले इलाकों में वार्षिक कार्बन वृद्धिशीलता के ऊंचे स्तर पर हैं। अगर उत्पादकता के जरिए होने वाली कार्बन क्षति को छोड़ दिया जाए तो कुल वृद्धिशील कार्बन की मात्रा 37507.3 जीजी बैठती है। पश्चिमी घाट से कार्बन अवशोषण क्षमता में होने वाले बदलाव का आकलन भूमि उपयोग संरक्षण परिदृश्य रोजमर्रा की गतिविधियों के परिदृश्य में भूमि संभावित उपयोग के आँकड़ों के आधार पर किया जाता है।

पश्चिमी घाट का महत्त्व

पारिस्थितिकीय दृष्टि से नाजुक पश्चिमी घाट कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इनमें दक्षिण भारतीय शहरों से होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता है। यही नहीं ये भारत के कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का 1.62 प्रतिशत अवशोषित कर सकते हैं। पश्चिमी घाट के राज्यों से कुल उत्सर्जन 352922.3 जीजी है और इनके जंगलों में 11 प्रतिशत उत्सर्जन अवशोषित करने की क्षमता है जो कार्बन कम करके जलवायु को सामान्य बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। भारत ने पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता वार्ता में 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 33-35 प्रतिशत कमी करने की वचनबद्धता व्यक्त की थी। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि कार्बन उत्सर्जन पर तत्काल अमल किया जाए। इसके लिए उजड़े हुए जंगलों के स्थान पर स्थानीय प्रजातियों के पेड़ लगाये जाने चाहिए।

विशेषज्ञों का कहना है कि इसके लिए पारिस्थितिकी दृष्टि से नाजुक क्षेत्रों की हिफाजत की जानी चाहिए; 'प्रदूषण फैलाने वाला भुगतान करे सिद्धांत के अनुसार लगातार ज्यादा उत्सर्जन करने वालों को हतोत्साहित किया जाएं; क्लस्टर आधारित विकेन्द्रित विकास दृष्टिकोण लागू किया जाए; और उत्सर्जन में कमी के लिए प्रोत्साहन दिये जाएं। विदित हो कि कार्बन ट्रेडिंग की अवधारणा ने कार्बन को अवशोषित करने की भारतीय वनों की क्षमता के महत्त्व को मौद्रिक रूप में साबित कर दिया है। पश्चिमी घाट के वनों की पारिस्थितिकीय प्रणाली 30 डालर प्रति टन की दर से 100 अरब रुपये मूल्य (1.4 अरब डालर) की है। कार्बन क्रेडिट प्रणाली और सहभागियों की भागीदारी को सुचारु बनाने से वनों का दुरुपयोग काफी हद तक कम हो जाएगा और किसानों को पेड़ लगाने तथा दूसरे बेहतरीन उपयोग के लिए जमीन का इस्तेमाल करने की प्रेरणा मिलेगी।

यही नहीं पश्चिमी घाट अपनी बारहमासी नदी-नालों से प्रायद्वीपीय भारत की पानी की आवश्यकता और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जलग्रहण क्षेत्रों में भूदृश्य संबंधी बदलाव का असर पानी की सम्पूर्ण व्यवस्था पर पड़ता है जिससे परिस्थितियों में परिवर्तन होते हैं जैसा कि बारहमासी और मौसमी नदी-नालों से स्पष्ट हो जाता है। पश्चिमी घाट के वनाच्छादित जलग्रहण क्षेत्रों में बारहमासी नदी-नाले पाये जाते हैं जबकि उजड़े हुए वनों वाले इलाकों में मौसमी नदी-नाले ही पाये जाते हैं। नदी-नाले बारहमासी तब होते हैं जब क्षेत्रों के 60 प्रतिशत से ज्यादा इलाके में देशीय प्रजातियों के पेड़-पौधे हों।

बारहमासी नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों की मिट्टी में सबसे अधिक आर्द्रता पायी जाती और इसमें पोषक तृत्व (कार्बन, नाइट्रोजन और पोटैशियम) पाये जाते हैं तथा इसका सामूहिक घनत्व भी कम होता है। दूसरी ओर मौसमी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र की मिट्टी का सामूहिक घनत्व अधिक होता है और इसमें पोषक तत्वों की मात्रा भी कम पायी जाती है। इस विश्लेषण से देशीय प्रजातियों वाले वनों की स्थानीय लोगों की जरूरत पूरा करने के साथ ही जलवैज्ञानिक व्यवस्था को बनाए रखने में भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। यह संबंधित सरकारी एजेंसियों द्वारा जलग्रहण क्षेत्र (जलसंभर/नाले) के प्रबंधन के लिए भी बहुत जरूरी है।

विशेषज्ञों का कहना है कि सूखे मौसम में मौसमी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में देशीय प्रजातियों के पेड़-पौधों की अधिकता होने से (60 प्रतिशत से अधिक) मिट्टी में नमी और भूमिगत जल का स्तर अधिक हो जाता है। सभी मौसमों में पानी उपलब्ध रहने से मिटटी में नमी की मात्रा बढ़ जाने से किसान अधिक आर्थिक फायदा देने वाली वाणिज्यिक फसलों की खेती कर सकते हैं जबकि दूसरे किसानों को कम वर्षा वाले मौसम में जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। इससे जलग्रहण क्षेत्र में स्थानीय प्रजातियों के पेड़-पौधे लगाने की आवश्यकता स्पष्ट हो जाती है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर देशीय पेड़-पौधों के संरक्षण के प्रयासों (जैसे सुपारी, नारियल, केला, पान के पत्ते और काली मिर्च) पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

उल्लेखनीय है कि नदियों में पानी का बने रहने से क्षेत्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है जो जलग्रहण क्षेत्र में भूमि उपयोग के तौर-तरीकों (वनाच्छादित आवरण) पर निर्भर है। इस तरह जलग्रहण क्षेत्र के सही रहने से सामाजिक और पारिस्थितिकीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पानी की उपलब्धता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह बात बारहमासी नदी-नालों के जलग्रहण क्षेत्र में देशीय पेड़-पौधों और वनस्पतियों के पाये जाने से स्पष्ट हो जाती है। इस तरह जलग्रहण क्षेत्रों में देशीय प्रजातियों के पेड़-पौधों और वनस्पतियों का होना जलवैज्ञानिक, पारिस्थितिकीय, सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अहमियत रखता है क्योंकि नदी में स्थायी रूप से पानी की उपलब्धता का सीधा संबंध पर्यावरण से है।

20वीं सदी के नीति निर्धारकों के तौर तरीकों को वर्तमान में अपनाने से जलग्रहण क्षेत्रों की पानी को सहेज कर रखने की क्षमता में कमी

आयी है। इससे पानी का भीषण संकट उत्पन्न हुआ है जो कि पिछले तीन साल से देश के 180 से 279 जिलों के लगातार सूखे की चपेट में आने से देखा जा सकता है। औसत तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी और पश्चिमी घाटों में बरसात के मौसम के दिनों के कम होने से ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु के लिए आसन्न संकट का पता चलता है। इसका कारण जंगलों का काटा जाना या डीकार्बनाइजेशन यानी कार्बनमुक्त करने की प्रणाली में कमी आने से कार्बन फुटप्रिंट में हुई बढ़ोत्तरी है।

इसलिए पश्चिमी घाट जैसे पारिस्थितिकी की दृष्टि से नाजुक क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर संरक्षित करना जरूरी है ताकि प्रायद्वीपीय भारत में कृषि और बागवानी को बनाए रखा जा सके।

चुनौतियाँ

पश्चिमी घाट को संरक्षित तथा कार्बन फ्रुटप्रिंट को कम करने के लिए कई स्तर पर कार्य किये जा रहे हैं बावजूद इसके कई चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं, जिन्हें निम्नलिखित बिन्दुओं के तहत देखा जा सकता है-

- विदित हो कि पश्चिमी घाट संरक्षण के लिए गाडगिल (वर्ष 2010) तथा कस्तूरीरंगन समिति (वर्ष 2011) का गठन किया गया था। लेकिन सरकार ने इन दोनों समितियों के द्वारा दिये गये अनुशंशाओं पर अमल नहीं किया चाहे वह केन्द्र सरकार हो या फिर राज्य सरकारें।
- गाडगिल समिति ने वृक्षारोपित भूमि, खेती योग्य भूमि और बड़ी बस्तियों को सम्मिलित करते हुए लगभग तीन-चौथाई पहाड़ियों को प्रतिबंधित क्षेत्र के अंतर्गत लाने की अनुशंसा की थी जिसका राज्य सरकारों ने विरोध किया था। जबकि कस्तूरीरंगन समिति पश्चिमी घाट के केवल 37 प्रतिशत हिस्से को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की बात की जो गाडगिल समिति द्वारा सुझाएं गये आँकड़ों से काफी कम है। फिर भी राज्यों ने इसका विरोध किया और यह लागू नहीं हो पाया। परिणामस्वरूप पश्चिमी घाट की स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब होती चली गई और वह प्रदूषण का मार झेल रहा है।
- पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए बनी समितियों ने इस बात पर जोर दिया कि यह क्षेत्र अति संवेदनशील है अतः इस क्षेत्र में वैसी परियोजनाओं पर रोक लगे जो इस क्षेत्र के प्राकृतिक रूप को प्रभावित करते हों। उन्होंने खनन गतिविधियों, जलविद्युत परियोजनाओं तथा अन्य परियोजनाओं पर तुरंत रोक लगाने की मांग की थी लेकिन ये कार्य अभी भी जारी है।
- पश्चिमी घाट में कई स्थलों को पर्यटक स्थल घोषित किये गये हैं जिससे कि वहाँ पर मानवीय गतिविधियाँ तेज हो गई हैं। परिणामस्वरूप प्रदूषण चाहे वह भूमि प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण बढ़ गया है, इसके अलावा प्लास्टिक प्रदूषण का खतरा भी अत्यधिक बढ़ गया है।
- नदियाँ जो इस क्षेत्र की पहचान हैं। सरकार द्वारा उनपर बाँध बनाकर नदियों के प्रवाह को रोका गया जिससे कि इस क्षेत्र में पानी की समस्या उत्पन्न हो गई तथा इससे कई स्थानीय पेड़-पौधे, जीव-जन्तु तथा शैवालों के खतरा उत्पन्न हो गया है।
- जलवायु परिवर्तन तथा वैश्विकतापीकरण के कारण पश्चिमी घाटों की जैवविविधता प्रभावित हो रही है। लोगों की बढ़ती महत्वाकांक्षा ने इसे और बढ़ा दिया है। इसे रोक पाना एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है सरकार इसके लिए कई योजनाओं के तहत कार्य तो कर रहा है लेकिन इच्छाशक्ति की कमी और जनभागीदारी का अभाव इस समस्या के समाधान में एक बड़ी बाधा है।

आगे की राह

- विशेषज्ञों का यह कहना एकदम सही है कि भारत ने कार्बन फ्रुटप्रिंट को लेकर जो वादा किया था उस पर वह खरा नहीं उतरा है। अतः सरकार को चाहिए कि पश्चिमी घाट जो जैवविविधता का भंडार है, उसे संरक्षित किया जाय।
- पश्चिमी घाट के लिए बनी समितियों के रिपोर्टों पर पर्याप्त ध्यान देना होगा तथा उसे सही तरीके से लागू करना होगा जिससे कि स्थानीय पेड़-पौधों, जीव-जंतुओं को बचाया जा सके।
- विशेषज्ञों की सर्वाधिक चिंता यहाँ की नदियों को लेकर है जो अब कम पानी प्रवाह के कारण सिकुड़ती जा रही है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह नदियों के ऊपर बन रहे बाधों पर रोक लगाये जिससे नदी प्रवाह बना रहे और इससे वहाँ की स्थानीय जनता लाभान्वित होती रहें।
- ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए कार्बन उत्सजर्न को कम किया जाय। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पेड़-पौधे लगाये जाये तथा कल-कारखानों को यहाँ से काफी दूर लगाया जाय। इसके साथ ही जो अवैध तरीके से कार्बन उत्सर्जन में संलिप्त हैं उन्हें दण्डित किया जाय।
- यहाँ पर हो रहे कृषि के पैटर्न में भी परिवर्तन की आवश्यकता है जिससे कि पानी तथा भूमिक्षरण को बचाया जा सके।
- आधुनिक विधि से खेती कर कम पानी से अधिक उत्पादन किया जा सकता है तथा उर्वरकों की मात्रा को कम कर भूमि प्रदूषण को रोका जा सकता है। अतः अब समय आ गया है कि पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए बढ़ चढ़ कर कार्य करना होगा जिससे कि यहाँ की विविधता और सुंदरता दोनों बनी रहे।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

7 विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

01 कोरोना वायरसः वैश्विक जगत के लिए बड़ा सबक

प्र. क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि अगर कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के रूप लेता है तो समूचा विश्व आर्थिक मंदी की स्थिति में जा सकता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान (Wuhan)से शुरू होने वाला कोरोना वायरस धीरे-धीरे पूरी दुनिया में फैल गया है। अमेरिकन रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुसार, अगर कोरोना वायरस एक महामारी का रूप लेता है तो समूचा विश्व आर्थिक मंदी की स्थिति में जा सकता है।

कोरोना वायरस क्या है

- डब्ल्यूएचओ (WHO) के अनुसार कोरोना वायरस सी-फूड से जुड़ा एक विशिष्ट वायरस फैमिली से संबंधित है। कोरोना वायरस की सतह पर क्राउन (Crown) जैसे कई उभार होते हैं, इन्हें माइक्रोस्कोप में देखने पर सौर कोरोना जैसे दिखते हैं। इसलिये इसका नाम 'कोरोना वायरस' है। यह वायरस ऊंट, बिल्ली और चमगादड़ सहित कई पशुओं में भी पाया जाता है।

कोरोना वायरस का विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव

- **अर्थव्यवस्था पर प्रभावः** चीन से फैले कोरोना वायरस की चपेट में दुनिया भर के कई देशों के आने से वैश्विक कारोबार में गिरावट देखी गई है। कोरोना की वजह से दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन और अमेरिका के कारोबार में सुस्ती देखी जा रही है।
- **स्वास्थ्य पर प्रभावः** चीन में कोरोना वायरस से लोगों की मौत का सिलसिला जारी है, इस बीमारी से अब तक चीन में लगभग 3000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।
- **वैश्विक खेलों पर प्रभावः** भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (NRAI) के अनुसार, कोरोना वायरस के डर से इस बीमारी के केन्द्र सहित छह देशों ने चीन में होने वाले निशानेबाजी विश्वकप से हटने का फैसला किया है। ज्ञातव्य है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 पर भी कोरोना वायरस का साया मंडरा रहा है।

भारत पर कोरोना वायरस का प्रभाव

- अर्थशास्त्रियों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोरोना का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव पड़ सकता है। आपूर्ति चेनशृंखला प्रभावित होने से कई चीजों के लिए कच्चे माल की कमी हो सकती है तो कई चीजें सस्ती भी हो सकती है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशंस के अनुसार- कच्चे माल की कमी और उत्पादन लागत बढ़ने की सूरत में आयात बिल भी बढ़ सकता है।

आगे की राह

- भारत जैसे- देश के लिए आवश्यक है कि वह स्वास्थ्य व्यय जो जीडीपी का 1.5% से कम है, को बढ़ाए क्योंकि यह मध्यम आय वाले देशों के लिए पर्याप्त नहीं है।
- इसके अलावा भारत में त्वरित निदान के लिए उपकरणों की उपलब्धता, बीमारियों को फैलने से रोकने के उपाय, और सार्वजनिक सूचना अभियान को आधुनिक और तीव्र बनाए जाने की आवश्यकता है।

02 सामुदायिक रेडियोः ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना का सशक्त माध्यम

प्र. सामुदायिक रेडियो क्या है? इस रेडियो के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र (खासकर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र) को किस प्रकार सशक्त किया जा सकता है? चर्चा करें।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पूरे देश में 120 सामुदायिक रेडियो को खोजने की स्वीकृति प्रदान की है। विदित हो कि केन्द्र सरकार की योजना देश भर में 700 जिलों में सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोलने की है।

सामुदायिक रेडियो महत्वपूर्ण क्यों

- स्थानीय लोगों द्वारा आसानी से समझे जाने वाले शब्द और जुमलों का प्रयोग कर समुदायों से स्थानीय भाषाओं में बात करने में, यह सक्षम बनाता है।
- श्रवण (लिसनिंग) क्लब, कॉल-इन-शो तथा विचारों के अन्य प्रकार के आदान-प्रदान के जरिये दोतरफा संवाद के साथ सामाजिक शिक्षण-प्रदान करता है।
- जिन समुदायों के पास जानकारी एवं ज्ञान के प्रसार के अन्य तरीकें नहीं हैं, उनके लिए इकलौता माध्यम उपलब्ध कराता है।

भारत में सामुदायिक रेडियो

- गौरतलब है कि इस समय भारत में 276 सामुदायिक रेडियो स्टेशन सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इन 276 स्टेशनों में 129 को शिक्षण संस्थान, 132 को समुदाय आधारित संगठन और 15 को कृषि विज्ञान केन्द्र अथवा राज्य कृषि संस्थाएँ चलाती हैं।

चुनौतियाँ

- सामुदायिक रेडियों संबंधित एक चुनौती पत्रकारिता और तकनीकी कौशल में कमी तथा इससे संबंधित प्रशिक्षण का अभाव है।
- उचित कौशल प्रबंधन के साथ-साथ वित्तीय प्रबंधन का कुशलतम रूप से न होना भी एक चुनौती है।
- एक दशक बीत जाने के बावजूद हम 500 सामुदायिक रेडियो स्टेशन का आंकड़ा नहीं पार कर पाये हैं, दरअसल इसकी वजह एक स्पष्ट नियामक ढांचे की अनुपस्थिति जिसमें सामुदायिक रेडियो संचालित होता है।

आगे की राह

- कम्युनिटी रेडियो फैसिलिटेशन सेंटर को जागरूकता कार्यशाला चलाना चाहिए ताकि लोग सामुदायिक रेडियो के महत्व को समझ सकें।
- सूचना और तकनीकी के इस युग में सामुदायिक रेडियो के बारे में जागरूकता के लिए कुछ नए तरीको को भी अपनाया जाना चाहिए जिससे अच्छे परिणाम सामने आ सकें।

03 बच्चों के स्वस्थ जीवन और भविष्य पर लांसेट की रिपोर्ट

प्र. हाल ही में बच्चों के स्वास्थ्य पर डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ तथा लांसेट की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट के प्रमुख बिन्दुओं का वर्णन करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization), यूनिसेफ (United Nations Children's Education Fund) और लांसेट मेडिकल जर्नल द्वारा "द फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड चिल्ड्रेन" नामक रिपोर्ट जारी की गयी।

परिचय

- संवहनीयता सूचकांक प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन से जुड़ा है जबकि खुशहाली सूचकांक का संबंध पालन-पोषण माता एवं पांच साल से कम आयु के बच्चों की उत्तर जीविता, आत्महत्या दर, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुविधा, बुनियादी साफ-सफाई और भीषण गरीबी से मुक्ति तथा बच्चे का फलना-फूलना आदि से है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

- इस रिपोर्ट के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि विश्व के नीति निर्माण कर्त्ता भी बच्चों व युवाओं के स्वास्थ्य को सुरक्षित करने, उनके अधिकारों को सुरक्षित करने तथा हमारी पृथ्वी, हमारे पर्यावरण की रक्षा करने में असफल रहे हैं।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि यह सभी देशों के लिए एक 'वैकअप कॉल' (चुनौती) है, इसके लिए वे अपने बच्चों व युवाओं के स्वास्थ्य व भविष्य पर निवेश करें, साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि प्रत्येक बच्चों की आवाज सुनी जाए, उनके अधिकार सुरक्षित किये जायें तथा एक सुरक्षित व बेहतर भविष्य की तरफ उनका मार्ग प्रशस्त हो।

भारत की स्थिति

- डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ तथा लांसेट द्वारा प्रदर्शित रिपोर्ट में भारत को सतत् स्थिरता सूचकांक में 180 देशों में से 77वां रैंक दी गयी है।
- इसके अलावा अस्तित्व व कल्याण के सर्वोत्तम अवसर पर्याप्त उत्कर्ष सूचकांक में 180 देशों में से 131वीं रैंक दी गयी।

भारत सरकार के प्रयास

- केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना समेकित बाल विकास योजना (Integrated Child development Scheme) जो कि महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा निष्पादित की जा रही है का मुख्य उद्देश्य बच्चों के विकास व उनके पोषण को बढ़ावा देना है।

चुनौतियाँ

- सर्वे के मुताबिक एक साल के अन्दर एक देश में टेलीविजन पर 30,000 से अधिक शराब व तंबाकू के विज्ञापन प्रसारित किये जाते हैं। इन विज्ञापनों से बच्चों के मस्तिष्क तथा स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है।
- इसके अलावा वैश्विक स्तर पर मोटापे के शिकार बच्चों व युवाओं की संख्या में 11 गुणा इजाफा हुआ है। 1975 में मोटापे से ग्रसित बच्चों की संख्या 11 मिलियन थी जो 2016 में बढ़कर 124 मिलियन तक हो गयी है।

आगे की राह

- बेहतर भविष्य के लिए कार्बन का उत्सर्जन कम करना होगा तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों को इस धरती पर बेहतर भविष्य प्राप्त हो सके।

04 शहरों की बुनियादी ढाँचों में आधुनिकीकरण की आवश्यकता

प्र. भारत में शहरों के आधुनिकीकरण तथा मरम्मत के लिए सरकार द्वारा किये गये कार्यों का उल्लेख करें, साथ ही बताएँ कि इन प्रयासों के बाद भी कौन-कौन सी चुनौतियाँ विद्यमान हैं?

उत्तर:

संदर्भ

- भारत 21वीं सदी के तीसरे दशक में प्रवेश कर चुका है। दूसरे दशक के दौरान शहरी भारत के लिए कई कार्यक्रमों और योजनाओं की शुरूआत हुई तथा उन्हें लागू किया गया।

शहरों का स्थिति

- संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा समय में दुनिया की आधी आबादी शहरों में रह रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2050 तक भारत की आधी आबादी महानगरों और शहरों में रहने लगेगी और तब तक विश्व की आबादी का सत्तर फीसद हिस्सा शहरों में रह रहा होगा।

भारतीय शहरों में बुनियादी सुविधाओं का अवलोकन

- वर्तमान में शहर के सीवेज और सेप्टिक टैंक कवरेज का फायदा केवल 63 प्रतिशत शहरी जनसंख्या को मिल रहा है। शहर में बने सीवेज में संसाधित सीवेज केवल तीस प्रतिशत हैं, जबकि 100 प्रतिशत की जरूरत है। संपूर्ण जमा अपशिष्ट कचरे में केवल 72 प्रतिशत ठोस अपशिष्ट जमा किया जाता है। साथ ही बारिश या बाढ़ इत्यादि से शहर में घुसे पानी को हटाने के लिए सड़कों पर केवल 20 फीसद नालियाँ ही काम कर रही हैं।
- माना जा रहा है कि 2030 में शहरी जनसंख्या की अनुमानित वृद्धि के हिसाब से जलापूर्ति की मांग 2.3 गुना बढ़कर189 मिलियन लीटर प्रतिदिन हो जाएगी। सीवेज का पानी भी 2.3 गुना बढ़ जाएगा यानी प्रतिदिन 151 मिलियन लीटर हो जाएगा।

सरकारी प्रयास

- **जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन योजना:** इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि भारत में शहरों की उन्नति की गति को तीव्रता प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत भारत के शहरों व नगरों में सुविधाओं के विकास हेतु लक्ष्यों को लागू करने एवं उन्हें पूरा करने का प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत पिछड़े इलाकों एवं गरीब लोगों तक सुविधाओं को पहुँचाना है।
- **अमृत मिशन:** अमृत मिशन को जून 2015 में लॉन्च किया गया था। अमृत मिशन का उद्देश्य देश के सभी शहरों में जलापूर्ति, साफ-सफाई और सीवेज कनेक्शन प्रदान करना है।
- **प्रधानमंत्री आवास योजना:** प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) एक सरकारी होम लोन योजना है, जिसे जून 2015 में, भारत सरकार ने सस्ते घर प्रदान करने उद्देश्य से शुरू किया था। इसका उद्देश्य 31 मार्च, 2022 तक योग्य परिवारों / लाभार्थियों को पानी के कनेक्शन, शौचालय की सुविधा और 24 घंटे बिजली की आपूर्ति के साथ 2 करोड़ से अधिक पक्के मकान प्रदान करना है।

- **स्मार्ट सिटी मिशन:** स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रस्तावित परियोजनाओं में से 81 प्रतिशत को मंजूरी दे दी गई है, जबकि 25 प्रतिशत परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं।
- **हृदय योजना:** शहरों की विरासत को संभालने और उसको संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने 21 जनवरी 2015 को हृदय अर्थात् धरोहर शहर विकास और संवर्द्धन योजना (Heritage city development and Augmentation Yojana) योजना की शुरुआत की। हृदय योजना के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपये का बजट तय किया है।
- **स्वच्छ भारत अभियान:** स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ-सुथरा करना है। यह अभियान 02 अक्टूबर, 2014 को आरंभ किया गया।

चुनौतियाँ

- शहरीकरण की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण है। शहर में प्रदूषित हवाओं से लोगों को सिलोकोसिस और फेफड़ों के कैंसर जैसी बीमारियाँ हो रही हैं। भारत में प्रदूषण का स्तर विश्व सेहत संगठन से समझा जा सकता है। वर्ष 2016 में इस रिपोर्ट ने विश्व के 15 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों की लिस्ट पेश की थी जिसमें अकेले भारत के 14 शहरों के नाम शामिल थे।
- शहरों में बढ़ते अपराध राज्य सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। वर्ष 2019 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के मुताबिक दस लाख की आबादी से अधिक के 63 बड़े शहरों में अपराध बढ़े हैं।
- शहरों की आबादी का लगभग एक तिहाई गरीबी रेखा से नीचे रहता है। एक अनुमान के अनुसार भारत की जनसंख्या का पांचवा भाग झुग्गी-झोंपड़ी में रहता है।

आगे की राह

- शहरों की समस्यायें अभी भी विद्यमान हैं तथा उनके निवारण के लिए जो सही उपाय हो सकता है वह नहीं हो पा रहा है, इसलिए सरकार को चाहिए कि शहरों के विकास तथा मरम्मत के लिए जो योजनायें चलाई जा रहीं हैं उसका सही से क्रियान्वयन किया जाय।
- शहरों के बुनियादी ढ़ाँचें में सुधार के लिए एक बेहतर उपाय यह है कि जो पुराने शहर हैं, उन्हें नये तरीके से विकसित किया जाय अर्थात सड़कों का चौड़ीकरण, फ्लाईओवर का निर्माण, लाइटिंग की व्यवस्था अपशिष्ट प्रबंधन, ड्रेनेज प्रणाली आदि पर विशेष ध्यान दिया जाय।

05 भारत और अमेरिका के संबंधों में नयी ऊर्जा का संचार

प्र. भारत-अमेरिका संबंधों में सकारात्मक बदलावों को रेखांकित करें, साथ ही दोनों देशों के मध्य व्यापारिक विवादों की भी चर्चा करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की यात्रा की। यह उनकी, भारत की पहली यात्रा थी। भारत का दौरा करने वाले ट्रंप सातवें अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं।

परिचय

- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के मायने हर किसी के लिए काफी खास रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच इस दौरे में सुरक्षा के क्षेत्र में अहम समझौते हुए हैं। इसके अलावा दोनों ही देशों ने व्यापारिक विवादों के बावजूद कई मुद्दों पर आगे बढ़ने की अपनी बात दोहराई है। ट्रंप के दौरे से दोनों देशों के बीच सामरिक-साझेदारी और अधिक मजबूत हुयी है।

समझौते का अवलोकन

- दोनों देशों के बीच कुल ऊर्जा व्यापार 20 बिलियन डॉलर रहा है। तीन वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में दोगुना बढ़ोत्तरी हुयी है। भारत, अमेरिका का बड़ा डिफेंस पार्टनर है। भारत और अमेरिका में जो हेलीकॉप्टरों की डील हुयी है उससे इंडो-पैसिफिक और दक्षिण-एशिया में स्थायित्व-शांति बनाए रखने में मदद मिलेगी। वहीं रोमियों हेलीकॉप्टरों से भारतीय फौजों की एंटी-सरफेस और एंटी-सबमरीन सुरक्षा क्षमता में इजाफा होगा।

क्षेत्रीय सहयोग

- अफगानिस्तान, जहाँ शांति, सुरक्षा और समृद्धि को प्रोत्साहन देने में भारत और अमेरिका दोनों के गहरे हित हैं। दोनों देश अफगानिस्तान यें लोकतांत्रिक संस्थानों के निर्माण में सहायता करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। दोनों देश अफगानिस्तान के पुनर्निमाण और भविष्य के लिए, पर्यापत संसाधनों का निवेश कर रहे हैं। यह प्रयत्न न केवल क्षेत्रीय विकास और स्थिरता को बढ़ावा देगा बल्कि आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों को समाप्त करने में भी सहायता करेगा।

वैश्विक नेतृत्व के लिए साझेदारी

- भारत और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सुदृढ़ करने एवं इनमें सुधार लागू करने और इनकी अखण्डता सुनिश्चित करने के लिए आपस में मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की पुनर्गठित सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन देने की फिर से पुष्टि की है। यही नहीं अमेरिका ने बिना किसी देरी के परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह में भारत के प्रवेश के समर्थन की भी पुष्टि की है।

भारत-अमेरिका संबंधों में चुनौतियाँ

- काट्सा एक्ट (CAATSA) के माध्यम से रूस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं, इन प्रतिबंधों के कारण भारत द्वारा रूस से रक्षा प्रणाली खरीदने पर असर पड़ सकता है, इसके अलावा एक समस्या यह भी है कि अगर भारत रूस से दूरियां बनाता है, तो रूस विकसित रक्षा प्रणाली की आपूर्ति पाकिस्तान को कर सकता है, जबकि चीन के पास ऐसी प्रणाली पहले से ही है। इससे क्षेत्रीय स्थिरता और शांति पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसी प्रकार ईरान और वेनेजुएला के साथ अमेरिका के बढ़ते तनाव ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को दांव पर लगा दिया है।

आगे की राह

- भारत और अमेरिका को अपने कूटनीतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने की आवश्यकता है तथा दोनों देशों के बीच उत्पन्न व्यापार मुद्दों को आपसी बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। भारत को अमेरिका एवं अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

06 प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन 2020: एक अवलोकन

प्र. हाल ही संपन्न 'COP-13' शिखर सम्मेलन प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार सहायक है? यह विश्व के देशों के लिए एक बड़ी सीख है या फिर सिर्फ खानापूर्ति। चर्चा करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में कॉप-13 (CoP-13) सम्मेलन भारत के गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर में आयोजित किया गया।

सम्मेलन के मुख्य बिंदु

- भारत को अगले तीन वर्ष के लिए इस कांफ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया

है। इस सम्मेलन के लिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (गोदावण) को शुभंकर बनाया गया है।

- प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के रास्तों पर विचार-विमर्श के लिए इस सम्मेलन में 130 देशों के लगभग 1200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- गौरतलब है कि मौजूदा समय में विश्वभर की लगभग 10 लाख प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पर हैं।

गांधीनगर घोषणापत्र

- इस घोषणापत्र में प्रवासी प्रजातीय और पारिस्थितिकीय तंत्रों के आपसी संबंध को 'पोस्ट-2020 ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क' में एकीकृत करने और प्राथमिकता देने की बात की गई है। इस फ्रेमवर्क के अक्टूबर 2020 में होने वाली संयुक्त राष्ट्र जैवविविधता सम्मेलन में पारित होने की उम्मीद है।

वर्तमान स्थिति

- हाल के दशकों में पक्षी पहले से अधिक पलायन कर रहे हैं, जो भोजन और घोंसले के निर्माण चक्र को बाधित कर सकता है। शोधकर्ताओं का दावा है कि इसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन है। पक्षियों का यह पलायन संभवत: उच्च तापमान के कारण है, जो पिछले कई दशकों से तेज गति से बढ़ रहा है।
- पिछले 50 वर्षों से दक्षिण यूरोप से उत्तरी यूरोप की ओर पलायन करने वाली 117 प्रवासी पक्षियों की प्रजातियों पर मिलन विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन किया गया। इस शोध में इन्होंने पाया कि वसंत ऋतु के आगमन में परिवर्तन हो रहा है, जिस कारण पक्षी कभी अपने मूल स्थान पर जल्दी वापस आ जाते हैं, जिससे इन्हें प्रतिकूल मौसम और खराब खाद्य आपूर्ति का सामना करना पड़ता है, परिणामत: इनकी स्थिति संवेदनशील बन रही है। इसके विपरित यदि वे देर से वापस आते हैं तो उन्हें अपने साथियों और क्षेत्रों के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ जाती है।

भारत और जैव विविधता

- भारत दुनिया के सर्वाधिक विविधताओं से भरे देशों में से एक है। दुनिया के 2.4 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र के साथ, भारत ज्ञात वैश्विक जैव विविधता में लगभग 8 प्रतिशत का योगदान करता है। भारत जैव विविधता संरक्षण को लेकर सदैव जागरूक रहा है। वह वन्यजीवों के संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर सदैव सचेत रहता है। इसी का परिणाम है कि भारत ने 2022 की समयसीमा से दो साल पहले ही बाघों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। देश में बाघों की संख्या 1411 से बढ़कर 2967 हो चुकी है।
- भारत में जैव विविधता के चार हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं-पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, भारत म्यांमार क्षेत्र तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो विश्व से आने वाले प्रवासी पक्षियों की 500 प्रजातियों का वास है। भारत जिन अनेक प्रवासी प्रजातियों का घर हैं उनमें शामिल हैं हिम तेंदुआ, अमूर बाज, हंस, काली गर्दन वाले सारस, समुद्री कछुआ, ड्यूगोंग एवं कूबड़ा व्हेल।

चुनौतियाँ

- प्रवासी पक्षियों के संरक्षण में सबसे बड़ी चुनौती विभिन्न देशों के मध्य समन्वय का अभाव है। संरक्षण के लिए जो कानून बने हैं उनका भी सही से पालन नहीं किया जाता है।
- चूँकि प्रवासी पक्षी जिस रास्ते से देश के अंदर आते हैं वे रास्ते भी निश्चित नहीं होते है। परिणामस्वरूप इनकी निगरानी करना काफी मुश्किल होता है।
- यहीं नहीं इन रास्तों के बीच में कई अवैध तस्करी भी होती है अर्थात इन रास्तों पर प्रवासी पक्षियों का अवैध शिकार किया जाता है। इन अवैध शिकार एवं तस्करी को रोकना भी एक बड़ी चुनौती है।

आगे की राह

- विश्व के सभी देशों को चाहिए कि प्रकृति के द्वारा मानव को जीव जंतु तथा पशु पक्षी के रूप में जो उपहार दिया गया है उसकी सुरक्षा करें।
- मानव का अस्तित्व भी कहीं न कहीं उनके ऊपर निर्भर करता है इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाय। इससे इनकी संख्या में वृद्धि होगी और यह मानव के सहचर्य के लिए लाभदायक होगा।

07 कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में पश्चिमी घाट की भूमिका

प्र. पश्चिमी घाट कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की दिशा में किस प्रकार सहायक साबित हो सकता है? चर्चा कीजिए।

उत्तर:

संदर्भ

- पेरिस में हुए जलवायु परिवर्तन समझौते में भारत ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 33-35 प्रतिशत कमी करने का वादा किया था जिसके लिए जरूरी है कि परती भूमि पर स्थानीय प्रजातियों के पेड़-पौधे लगाकर कार्बन फुटप्रिंट को तत्काल कम किया जाए, भूमि के आच्छादन का विनियमन किया जाए। जिससे कि डीकार्बनाइजेशन यानी कार्बनमुक्त करने की प्रक्रिया को शुरू किया जा सके।

कार्बन फुटप्रिंट क्या है

- कार्बन फुटप्रिंट (Carbon Footprint) का अर्थ किसी एक संस्था, व्यक्ति या उत्पाद द्वारा किया गया कुल कार्बन उत्सर्जन से है। यह उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीनहाउस गैसों के रूप में होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य की सभी आदतें, जिनमें खानपान से लेकर पहने जाने वाले कपड़े तक शामिल हैं, कार्बन फुटप्रिंट का कारण बनते हैं।

पश्चिमी घाट का महत्त्व

- पारिस्थितिकीय दृष्टि से नाजुक पश्चिमी घाट कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इनमें दक्षिण भारतीय शहरों से होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता है। यही नहीं ये भारत के कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का 1.62 प्रतिशत अवशोषित कर सकते हैं। पश्चिमी घाट के राज्यों से कुल उत्सर्जन 352922.3 जीजी है और इनके जंगलों में 11 प्रतिशत उत्सर्जन अवशोषित करने की क्षमता है जो कार्बन कम करके जलवायु को सामान्य बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। भारत ने पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता वार्ता में 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 33-35 प्रतिशत कमी करने की वचनबद्धता व्यक्त की थी। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि कार्बन उत्सर्जन पर तत्काल अमल किया जाए। इसके लिए उजड़े हुए जंगलों के स्थान पर स्थानीय प्रजातियों के पेड़ लगाये जाने चाहिए।

चुनौतियाँ

- गाडगिल समिति ने वृक्षारोपित भूमि, खेती योग्य भूमि और बड़ी बस्तियों को सम्मिलित करते हुए लगभग तीन-चौथाई पहाड़ियों को प्रतिबंधित क्षेत्र के अंतर्गत लाने की अनुशंसा की थी जिसका राज्य सरकारों ने विरोध किया था। जबकि कस्तूरीरंगन समिति पश्चिमी घाट के केवल 37 प्रतिशत हिस्से को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की बात की जो गाडगिल समिति द्वारा सुझाएं गये आँकड़ों से काफी कम है। फिर भी राज्यों ने इसका विरोध किया और यह लागू नहीं हो पाया। परिणामस्वरूप पश्चिमी घाट की स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब होती चली गई और वह प्रदूषण का मार झेल रहा है।

आगे की राह

- विशेषज्ञों का यह कहना एकदम सही है कि भारत ने कार्बन फ्रुटप्रिंट को लेकर जो वादा किया था उस पर वह खरा नहीं उतरा है। अत: सरकार को चाहिए कि पश्चिमी घाट जो जैवविविधता का भंडार है, उसे संरक्षित किया जाय।
- पश्चिमी घाट के लिए बनी समितियों के रिपोर्टों पर पर्याप्त ध्यान देना होगा तथा उसे सही तरीके से लागू करना होगा जिससे कि स्थानीय पेड़-पौधों, जीव-जंतुओं को बचाया जा सके।

7 सात ब्रेन बूस्टर्स

विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019

चर्चा का कारण

1.1
हाल ही मे विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, 2019 को प्रदूषण ट्रैकर आईक्यू और ग्रीनपीस द्वारा जारी किया गया है।

1.2 इसकी रैंकिंग पीएम 2.5 के स्तर की तुलना पर आधारित है।

प्रमुख बिन्दु

2.1
विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 के अनुसार, वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिये सबसे गंभीर खतरों में से एक है और विश्व की 90 प्रतिशत से अधिक आबादी असुरक्षित वायु में साँस लेने के लिये विवश है।

2.2
विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार आबादी के हिसाब से बांग्लादेश पीएम 2.5 प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित है।

2.3
रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश विश्व का सबसे प्रदुषित देश है। उसके बाद पाकिस्तान दूसरे स्थान पर आता है। तीसरे स्थान पर मंगोलिया, चौथे स्थान पर अफगानिस्तान और पांचवे स्थान पर भारत है।

2.4
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने समय पूर्व हुई 70 लाख लोगों की मौत में से अधिकतर की वजह वायु प्रदूषण को बताया है।

2.5
चीन को इस रैंकिंग में 98 देशों में 11वाँ स्थान प्राप्त हुआ है। हालाँकि अभी भी चीन के 98 प्रतिशत शहरों में PM2.5 का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा निर्धारित मापदंडों से अधिक है।

2.6
2.6 भारत के अन्य पड़ोसी देशों में नेपाल 8वें स्थान पर और म्यांमार 20वें स्थान पर है।

2.7
98 देशों की इस रैंकिंग में बहामास (Bahamas) को वायु प्रदूषण के मामले में सबसे स्वच्छ देश का दर्जा प्राप्त हुआ है।

पीएम 2.5 क्या है

3.1
PM2.5 का आशय उन कणों से होता है जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर (0.000001 मीटर) या उससे कम होता है और इसीलिये इसे PM2.5 के नाम से भी जाना जाता है।

3.2
पीएम 2.5 में सल्फेट, नाइट्रेट और ब्लैक कार्बन जैसे प्रदूषक शामिल हैं।

3.3
पीएम 2.5 को विशेष रूप से हानिकारक माना जाता है क्योंकि वे फेफड़ों और हृदय प्रणाली की गहराई में प्रवेश करने हेतु काफी छोटे होते हैं।

3.4
इस तरह के कण आसानी से शरीर में पहुंचकर फेफड़ों तथा हृदय की परेशानियों को बढ़ा सकते हैं।

भारत के संदर्भ में

4.1
सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले विश्व के 30 शहरों में 21 भारत के हैं।

4.2
इस सूची में दिल्ली एनसीआर का गाजियाबाद विश्व के सबसे प्रदूषित शहर के रूप में सामने आया है।

4.3
हालाँकि भारत के समग्र वायु प्रदूषण में वर्ष 2018 के मुकाबले वर्ष 2019 में कमी देखने को मिली है।

प्रभाव

5.1
वर्ष 2019 के वायु गुणवत्ता संबंधी आँकड़े स्पष्ट संकेत देते हैं कि जलवायु परिवर्तन प्रत्यक्ष तौर पर वनाग्नि और सैंडस्टॉर्म आदि के माध्यम से वायु प्रदूषण के जोखिम को बढ़ा सकता है।

5.2
हवा में अवांछित गैसों की उपस्थिति से मनुष्य, पशुओं तथा पक्षियों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे दमा, सर्दी, अंधापन, श्रवण शक्ति कमजोर होना, त्वचा रोग आदि बीमारियाँ पैदा होती हैं।

5.1
वायु प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा का खतरा बढ़ गया है, जिसके कारण बारिश के पानी में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि जहरीली गैसों के घुलने की संभावना बढ़ी है। इससे पेड़-पौधे, भवनों व ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुँचता है।

आगे की राह

6.1
मानव सभ्यता व समाज को प्रकृति एवं औद्योगीकरण के बीच सामंजस्य स्थापित करना अति आवश्यक है।

6.2
अत: हमें वायु प्रदूषण को कम करने के लिये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज व आम आदमी की भागीदारी को प्रोत्साहित करना होगा।

राष्ट्रीय तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण

चर्चा का कारण

1.1

1.1 हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) द्वारा आयोजित पहले 'राष्ट्रीय तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लचीलापन (सीडीआरआर एंड आर)- सम्मेलन 2020' का समापन हुआ।

उद्देश्य

2.1

इस सम्मेलन का उद्देश्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लचीलेपन के विभिन्न पहलुओं के बारे में मुद्दों और समाधानों की समझ को बढ़ाने के लिए हाल में हुई प्रगति का पता लगाना और उसके बारे में चर्चा करना था।

2.2

इस सम्मेलन में तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लचीलेपन के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय रणनीतियों से संबंधित जानकारी का प्रचार करना तथा संस्थानों, अनुसंधानकर्ताओं और विशेषज्ञों को जोड़कर पहचाने गए अंतराल से निपटने के लिए एक नेटवर्क मोड रोडमैप विकसित करने पर जोर दिया गया।

आपदा प्रबंधन पर भारत का एजेंडा

3.1

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण (एएमसीडीआरआर) 2016 में एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण के दौरान इस एजेंडा को सूचीबद्ध किया था।

3.2

इसमें शामिल हैं: सभी विकास क्षेत्रों को आपदा जोखिम प्रबंधन के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।

3.3

गरीब घरों, एसएमई, बहु-राष्ट्रीय निगमों से राष्ट्र राज्यों तक सभी के लिए जोखिम कवरेज की दिशा में काम करना।

3.4

आपदा जोखिम प्रबंधन में महिलाओं की अधिक भागीदारी और नेतृत्व को प्रोत्साहित करना।

3.5

विश्व स्तर पर जोखिम मानचित्रण में निवेश करना भूकंप जैसे खतरों से संबंधित मानचित्रण के लिए मानकों और मापदंडों को स्वीकार करना।

3.6

हमारे आपदा जोखिम प्रबंधन प्रयासों की दक्षता बढ़ाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना।

3.7

आपदा मुद्दों पर काम करने के लिए विश्वविद्यालयों का एक नेटवर्क विकसित करना।

3.8

सोशल मीडिया और मोबाइल प्रौद्योगिकियों द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का उपयोग करना व स्थानीय क्षमताओं और पहलों को सुदृढ़ बनाना।

3.9

आपदा से सीखने का अवसर बर्बाद नहीं होना चाहिए। उससे हमेशा सीखना की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा आपदाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया में अधिक सामंजस्य लाना होगा।

सेंदाई फ्रेमवर्क

4.1

इसे 18 मार्च, 2015 को जापान के सेंदाई में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था।

4.2

यह ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन (2005-2015) खत्म होने के बाद लागू हुआ समझोता है, जो कि आपदा जोखिम में कमी पर अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समझौता था।

सेंदाई फ्रेमवर्क का उद्देश्य

5.1

आपदा जोखिम प्रबंधन को मजबूत करना , आपदा जोखिम का प्रबंधन करना; लचीलापन के लिए आपदा में कमी और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए आपदा तैयारी को बढ़ाना, और पुनर्प्राप्ति, पुनर्वास और पुनर्निर्माण में बेहतर निर्माण करना।

आदिवासी कल्याण के लिए पहल

चर्चा का कारण

1.1
हाल ही में महान स्वतंत्रता सेनानी, बिरसा मुंडा की 142 वीं जयंती भारत के कई हिस्सों में मनाई गई। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार आदिवासियों के कल्याण के लिए प्रयासरत है।

आदिवासी कल्याण के लिए पहल

2.1
जनजातीय कल्याण मंत्रालय देश में जनजातीय समुदायों के विकास के लिए समर्पित है। मंत्रालय के पास जनजातीय अनुसंधान संस्थान जैसी विभिन्न योजनाएँ हैं जो पूरे देश में फैली हुई हैं।

2.2
केंद्र सरकार आदिवासी समुदायों की संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण के लिए देशभर में आदिवासी विद्यालय, आदिवासी संग्रहालय तथा आदिवासी अनुसंधान संस्थान स्थापित कर चुकी है।

2.2
ट्राइफेड (TRIFED) 1987 में स्थापित किया गया था जबकि इसने अप्रैल 1988 से अपना काम शुरू किया था। ट्राइफेड का मूल उद्देश्य आदिवासी लोगों द्वारा जंगल से एकत्र किये गए या इनके द्वारा बनाये गए उत्पादों को बाजार में सही दामों पर बिकवाने की व्यवस्था करना है।

न्यूनतम वन उपज

3.1
न्यूनतम वन उपज (Minor Forest Produce-MFP) देश में आदिवासियों की आजीविका का प्रमुख स्रोत है, हाल ही में सरकार ने एमएफपी का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की पहल की है।

3.2
केंद्र सरकार की यह प्रतिष्ठित योजना महुआ बीज, साल के पत्ते और इमली और जंगली शहद जैसे पूरी तरह से 24 वस्तुओं के लिए पारिश्रमिक मूल्य को वहन करने के लिए है।

3.3
एक राष्ट्रीय स्तर की समिति है, जो बाजार के रुझानों को ध्यान में रखते हुए उत्पादन के विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए कीमत तय करती है।

3.4
खरीद के लिए 75% धनराशि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के जनजातीय कल्याण विभाग को प्रदान की जाएगी और यह विभाग खरीद के लिए 25% धनराशि कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रदान करेगा।

वन अधिकार अधिनियम और पेसा अधिनियम

4.1
वन अधिकार अधिनियम, 2006 ने आदिवासियों के लिए पर्याप्त स्वामित्व अधिकार दिए हैं। इसने न केवल पारंपरिक वनवासियों को वन भूमि के वैध मालिकों के रूप में मान्यता दी, बल्कि पहली बार वन संरक्षण के लिए जवाबदेह बनाया।

4.2
इसके अतिरिक्त PESA (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायतीराज विस्तार) अधिनियम 1996, वन उपज और आदिवासियों के मुद्दों से निपटने के लिए ग्राम पंचायत को स्वामित्व और अधिकार प्रदान करता है।

आदिवासियों की शिक्षा

5.1
कई गर्ल्स हॉस्टल और आश्रम आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए आदिवासी बहुल ब्लॉक में स्थापित किए गए हैं। आवासीय विद्यालयों के एकलव्य मॉडल स्थापित किए गए हैं।

वनबंधु कल्याण योजना

6.1
भारत की आदिवासी आबादी के समग्र विकास और कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा वनबंधु कल्याण योजना शुरू की गई है।

6.2
इस योजना का उद्देश्य अन्य सामाजिक समूहों के साथ देश की जनजातीय आबादी को सममूल्य पर लाना और उन्हें राष्ट्र की समग्र प्रगति में शामिल करना है।

चुनौतियाँ

7.1
58 लाख से अधिक लोगों ने वन पट्टों (वन उपज के स्वामित्व के लिए) के लिए आवेदन किया है, लेकिन केवल 14 लाख पट्टों को व्यक्तिगत रूप से जारी किया गया है और कुछ और सामुदायिक स्तरों पर जारी किए गए हैं।

7.2
सिकल सेल एनीमिया (sickle cell anaemia) देश में आदिवासी समुदाय के प्रमुख रोगों में से एक है और समुदाय के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए बहुत प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।

7.3
अधिकांश आदिवासी एकल कमरे के घरों में रहते हैं और पीने के पानी, स्वच्छता और बिजली के उपयोग तक पहुँचने में कई चुनौतियों का सामना करते हैं।

आगे की राह

8.1
स्वास्थ्य सेवाओं की त्वरित पहुंच, बेहतर शिक्षा और सामाजिक सेवा के मामले में, सड़क संपर्क जैसी बुनियादी सुविधाओं से जनजातीय क्षेत्रों में आदिवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। इसके अलावा जनजातीय क्षेत्रों में मौजूदा सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के लिए भी सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन

चर्चा का कारण

1.1
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन को मंजूरी दे दी। इस पर 1,480 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को पेश बजट में राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के गठन का प्रस्ताव किया था।

तकनीकी वस्त्र क्या हैं

2.1
तकनीकी वस्त्र ऐसे कपड़ा सामग्री और उत्पाद हैं जो सौंदर्य विशेषताओं की बजाय मुख्य रूप से तकनीकी प्रदर्शन और कार्यात्मक गुणों के लिए निर्मित होते हैं।

2.2
तकनीकी वस्त्रों का उपयोग कृषि, वैज्ञानिक शोध, चिकित्सा, सैन्य क्षेत्र, उद्योग तथा खेलकूद के क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर होता है। तकनीकी वस्त्रों के उपयोग से कृषि, मछली पालन तथा बागवानी की उत्पादकता में वृद्धि होती है।

2.2
2.3 ट्राइफेड (TRIFED) 1987 में स्थापित किया गया था जबकि इसने अप्रैल 1988 से अपना काम शुरू किया था। ट्राइफेड का मूल उद्देश्य आदिवासी लोगों द्वारा जंगल से एकत्र किये गए या इनके द्वारा बनाये गए उत्पादों को बाजार में सही दामों पर बिकवाने की व्यवस्था करना है।

मिशन से संबंधित प्रमुख बिंदु

3.1
इसे 2020-21 से 2023-24 के दौरान क्रियान्वित किया जाना है। इस मिशन के 4 घटक हैं।

3.2
इस मिशन का मकसद चिकित्सा, सैन्य जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले तकनीकी कपड़े तैयार करने के मामले में भारत को अगुवा बनाना है।

अनुसंधान, नवाचार और विकास

4.1
4.1 1000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पहला घटक अनुसंधान, नवाचार और विकास पर केन्द्रित होगा।

4.2
यह भू-टेक्सटाइल, कृषि-टेक्सटाइल, चिकित्साक-टेक्सटाइल, मोबाइल-टेक्सटाइल और खेल-टेक्सटाइल एवं जैवनिम्नीकरण तकनीकी टेक्सटाइल के विकास पर आधारित अनुसंधान अनुप्रयोग दोनों को प्रोत्साहन देगा।

संवर्द्धन और विपणन विकास

5.1
भारतीय तकनीकी कपड़ा श्रेणी का अनुमानित आकार 16 अरब डॉलर है जो 250 अरब डॉलर के वैश्विक तकनीकी कपड़ा बाजार का लगभग 6 प्रतिशत है।

5.2
भारत में तकनीकी कपड़ा की पहुँच काफी कम है जो 5 से 10 प्रतिशत के दायरे में है जबकि विकसित देशों में यह आँकड़ा 30 से 70 प्रतिशत है। इस मिशन का उद्देश्य बाजार विकास, बाजार संवर्द्धन, अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग, निवेश प्रोत्साहन और 'मेक इन इंडिया' पहल के माध्यम से सालाना 15 से 20 प्रतिशत की औसत वृद्धि के साथ घरेलू बाजार के आकार को 2024 तक 40 से 50 अरब डॉलर करना है।

निर्यात संवर्द्धन

6.1
इसका उद्देश्य तकनीकी कपड़ा के निर्यात को बढ़ाकर वर्ष 2021-22 तक 20,000 करोड़ रुपये करना है जो वर्तमान में लगभग 14,000 करोड़ रुपये है। साथ ही वर्ष 2023-24 तक प्रति वर्ष निर्यात में 10 प्रतिशत औसत वृद्धि सुनिश्चित करना है।

शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास

7.1
देश में शिक्षा, कौशल विकास और मानव संसाधन तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण और तेजी से उभरते तकनीकी कपड़ा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

7.2
यह मिशन उच्चतर इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी स्तर पर तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देगा और इसके अनुप्रयोग का दायरा इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कृषि, जलीय कृषि और डेयरी जैसे क्षेत्रों तक बढ़ाएगा।

7.3
कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाएगा और अत्यधिक कुशल मानव संसाधनों का पर्याप्त भंडार तैयार करेगा ताकि अपेक्षाकृत परिष्कृत तकनीकी कपड़ा विनिर्माण इकाईयों की आवश्यकता पूरी की जा सके।

तकनीकी वस्त्र मिशन की आवश्यकता

8.1
250 अरब अमरीकी डॉलर के विश्व बाजार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 6 फीसदी है। हालांकि, 4 फीसदी वैश्विक औसत वृद्धि की तुलना में भारत की वार्षिक औसत वृद्धि 12 फीसदी है।

8.2
उन्नत देशों में 30-70 फीसदी के मुकाबले भारत में तकनीकी वस्त्रों का पैठ स्तर महज 5-10 फीसदी है। मिशन का उद्देश्य देश में तकनीकी वस्त्र की पैठ के स्तर में सुधार करना है।

भारतीय स्कूलों में छात्रों के लिए एआई आधारित मॉड्यूल

चर्चा का कारण

1.1
नीति आयोग (NITI AAYOG), अटल इनोवेशन मिशन (AIM), नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (NASSCOM) के सहयोग से भारतीय स्कूलों में छात्रों के लिए AI आधारित मॉड्यूल शुरू किया गया है।

1.2
एआईएम ने एटीएल की स्थापना के लिए 33 विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भारत भर में 14,916 स्कूलों का चयन किया है।

उद्देश्य

2.1
एआई मॉड्यूल का उद्देश्य अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) की पूरी क्षमता का लाभ उठाना है। यह बड़े पैमाने पर समाजों को लाभान्वित करने के लिए नए समाधान तैयार करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए भी कार्य करेगा।

एआई आधारित मॉड्यूल

3.1
नीति आयोग, को सभी 5000 अटल टिंकरिंग लैब्स में लर्न-इट-योर-सेल्फ (LEARN- IT-YOURSELF) मॉड्यूल को पेश करना है, जिसमें 2.5 मिलियन से अधिक छात्र हैं।

3.2
स्कूल में शैक्षणिक, सह-शैक्षिक और अन्य अटल टिंकरिग लैब कार्यक्रमों पर विचार करके एआई मॉड्यूल को डिजाइन किया गया था।छात्र हैं।

3.3
यह युवाओं के लिए नवीनतम तकनीकों का पता लगाने, उन्हें तैयार करने और सीखने के लिए एक उत्प्रेरक होगा और जमीनी स्तर पर नवाचारियों की एक पीढ़ी का निर्माण करेगा

3.4
मॉड्यूल में कई गतिविधियां, प्रयोग और वीडियो हैं, जो छात्रों को एआई की विभिन्न अवधारणाओं के माध्यम से काम करने और सीखने में सक्षम करेंगे।

3.6
युवा छात्रों को राष्ट्र-निर्माण की यात्रा में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मॉड्यूल तैयार किया गया था।

3.5
इसका लक्ष्य नवीनतम तकनीकों के साथ देश के सबसे युवा दिमाग को सशक्त बनाना है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

4.1
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है, जो मानव की तरह सोचने और कार्य करने वाली मशीनों के विकास पर जोर देती है।

4.2
उदाहरण के लिए, भाषा समझने वाली, समस्या को हल करने वाली, सीखने और योजना बनाने वाली।

महत्त्व

5.1
भारत से तपेदिक, कैंसर आदि जैसी बीमारियों का समाधान हो सकता है।

5.2
मशीनो के सीखने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के माध्यम से भारत, वार्षिक आधार पर अपने सकल घरेलू उत्पाद में 1.3% की बढ़ोतरी कर सकता है।

5.3
यह अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक, AI का वैश्विक बाजार 15 से 15.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच सकता है, जिसमें से भारत का हिस्सा +1 ट्रिलियन के करीब हो सकता है।

अटल इनोवेशन मिशन

6.1
अटल इनोवेशन मिशन भारत सरकार की प्रमुख पहल है। AIM का मुख्य उद्देश्य नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है।

6.2
AIM पूरे भारत में सभी जिलों में स्कूल स्तर पर अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना करता है।

महासागर आधारित उन्नत चेतावनी प्रणाली

चर्चा का कारण

1.1
हाल ही मे हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) ने तीन महासागर आधारित उन्नत चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है।

1.2
गौरतलब है कि आईएनसीओआईएस समुद्री क्षेत्र में उपयोगकर्ताओं के लिए कई निःशुल्क सेवाएं प्रदान करता है। ये संस्थान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है।

स्मॉल वेसल एडवाइजरी एंड फोरकास्ट सर्विसेज सिस्टम

2.1
इसे कई छोटे समुद्री जहाजों, विशेष रूप से मछली पकड़ने वाले जहाजों के परिचालन में सुधार के लिए लाया गया है जो भारत के तटीय जल में विचरण करते हैं।

2.2
लघु पोत एडवाइजरी और पूर्वानुमान सेवा प्रणाली दरअसल भारतीय तटीय जल में काम करने वाले छोटे जहाजों के लिए एक नवीन प्रभाव-आधारित सलाह और पूर्वानुमान सेवा प्रणाली है।

2.3
ये प्रणाली उपयोगकर्ताओं को दस दिन पहले ही उन संभावित क्षेत्रों के बारे में चेतावनी देती है जहाँ जहाज पलट सकता है।

स्वेल सर्ज फोरकास्ट सिस्टम

3.1
स्वेल सर्ज फोरकास्ट सिस्टम भारत की विशाल तटरेखा के पास बसी आबादी के लिए पूर्वानुमान प्रदान करेगा, जो उन लहरों के उफान के चलते कई तरह के नुकसान का सामना करती हैं। ये लहरें सुदुर दक्षिणी हिंद महासागर से उत्पन्न होती हैं।

3.2
स्वेल सर्ज फोरकास्ट सिस्टम एक नवीन प्रणाली है जो कल्लकाडल यानी महातरंग उमड़ने (स्वेल सर्ज) की भविष्यवाणी के लिए तैयार की गई है जो भारतीय तट और विशेष रूप से पश्चिमी तट के पास होती है।

3.3
कल्लकाडल / महातरंग उमड़ना दरअसल एकदम से बाढ़ आने की घटना होती है जो स्थानीय हवाओं या तटीय वातावरण में किसी उल्लेखनीय अग्रिम बदलाव के बिना या फिर तटीय वातावरण में किसी भी अन्य स्पष्ट संकेत के बिना होती हैं।

3.4
इसलिए स्थानीय आबादी इन बाढ़ की घटनाओं से तब तक पूरी तरह अनजान रहती है जब तक कि वे वास्तव में नहीं हो जाती हैं। इस तरह की घटनाएं पूरे साल रुक-रुक कर होती हैं। कल्लकाडल एक स्थानीय बोलचाल की भाषा है, जिसका इस्तेमाल केरल के मछुआरों ने भयंकर बाढ़ के प्रकरणों को संदर्भित करने के लिए किया था और 2012 में यूनेस्को ने औपचारिक रूप से इस शब्द को वैज्ञानिक उपयोग के लिए स्वीकार किया था।

3.5
कल्लकाडल की घटनाओं के दौरान समुद्र भूमि क्षेत्र में प्रवेश कर लेता है और विशाल क्षेत्रों को जलमग्न कर देता है। इन घटनाओं ने विशेष रूप से हिंद महासागर में 2004 में आई सुनामी के बाद ध्यान आकर्षित किया है

एलगल ब्लूम इनफॉर्मेशन सर्विस

4.1
एलगल ब्लूम इनफॉर्मेशन सर्विस ऐसी हानिकारक काई यानी शैवालों के खिलने के समय को लेकर जानकारी प्रदान करता है जो तटीय मत्स्य पालन के लिए हानिकारक है और समय-समय पर तटीय आबादी के बीच सांस संबंधी समस्याओं को जन्म देते हैं।

4.2
काई या शैवालों के खिलने की बढ़ती आवृत्ति मत्स्य, समुद्री जीवन और पानी की गुणवत्ता पर इसके दुष्प्रभाव के कारण एक प्रमुख चिंता का विषय है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने 'भारतीय समुद्र में शैवाल का पता लगाने और निगरानी' के लिए एक सेवा विकसित की है।

4.3
यह सेवा भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र की समुद्री मछली पकड़ने की सलाह यानि संभावित फिशिंग जोन की एडवाइजरी में इजाफा करती है। आईएनसीओआईएस-एबीआईएस उत्तरी हिंद महासागर के ऊपर पादक प्लवकों (फाइटोप्लांक्टन) के फैलाव और इस स्थानिक-लौकिक घटना को लेकर करीब करीब उसी समय में सीधे जानकारी प्रदान करेगा।

4.4
तदनुसार उपग्रहों से प्राप्त होने वाले प्रासंगिक आंकड़ों को रोजाना एबीआईएस के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा।

सूक्ष्मजीवों से जैव ईंधन

चर्चा का कारण

1.1
इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी (आईसीजीईबी) के शोध कर्तासिनेकोकोकस (विशेष नाम पीसीसी 7002) नामक एक समुद्री सूक्ष्मजीव की वृद्धि दर और उसमें शर्करा की मात्रा में सुधार के लिए एक विधि तैयार कर रहे हैं।

सूक्ष्मजीव क्या हैं

2.1
वे जीव जिन्हें मनुष्य नंगी आंखों से नहीं देख सकता तथा जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें सूक्ष्मजीव (माइक्रोऑर्गेनिज्म) कहते हैं। सूक्ष्मजैविकी (microbiology) में सूक्ष्मजीवों का अध्ययन किया जाता है।

2.2
सूक्ष्मजीवों के अन्तर्गत सभी जीवाणु (बैक्टीरिया) और आर्किया तथा लगभग सभी प्रोटोजोआ के अलावा कुछ कवक (फंगी), शैवाल (एल्गी) और चक्रधर (रॉटिफर) आदि जीव आते हैं।

2.3
2.3 यह मृदा, जल, वायु, हमारे शरीर के अंदर तथा बाहर और पादपों में पाए जाते हैं।

जैव ईंधन

3.1
बायोफ्यूल बायोमास से प्राप्त ईंधन है।

3.2
बायोमास को कार्बनिक पदार्थ- विशेष रूप से पादप पदार्थ- के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे ईंधन में परिवर्तित किया जा सकता है और इसे संभावित ऊर्जा स्रोत माना जाता है।

3.3
बायोमास के स्रोत हैं, जिनमें पेड़, ऊर्जा फसलें, कृषि अवशेष और खाद्य और अपशिष्ट अवशेष शामिल हैं।

3.4
इसमें कोई सल्फर नहीं होता है और यह कम कार्बन मोनोऑक्साइड और कम विषाक्त उत्सर्जन पैदा करता है।

3.5
जैव ईंधन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम कर सकता है और जीवाश्म ईंधन का विकल्प प्रदान करके ऊर्जा सुरक्षा बढ़ा सकता है।

सूक्ष्मजीव ही क्यों

4.1
जैव-ईंधन उत्पादन सहित अधिकतर जैव-प्रौद्योगिकीय प्रक्रियाएँ कम लागत और शर्करा एवं नाइट्रोजन स्रोत से निर्बाध आपूर्ति की उपलब्धता पर निर्भर हैं।

4.2
शर्करा आमतौर पर पौधों से आती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को शर्करा, प्रोटीन और लिपिड जैसे जैविक घटकों में परिवर्तित करने के लिए प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं।

4.3
हालांकि कुछ बैक्टीरिया, जैसे साइनोबैक्टीरिया (जिसे नीले-हरे शैवाल के रूप में भी जाना जाता है), भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को ठीक करके शर्करा का उत्पादन कर सकते हैं।

4.4
साइनोबैक्टीरिया से शर्करा की उपज संभावित रूप से भूमि आधारित फसलों की तुलना में बहुत अधिक हो सकती है।

4.5
इसके अलावा, पौधे-आधारित शर्करा के विपरीत साइनोबैक्टीरियल बायोमास प्रोटीन के रूप में एक नाइट्रोजन स्रोत प्रदान करता है।

साइनोबैक्टीरिया

5.1
साइनोबैक्टीरिया ताजा और समुद्री पानी दोनों में पाए जाते हैं। हैं। ये लहरें सुदुर दक्षिणी हिंद महासागर से उत्पन्न होती हैं।

5.2
समुद्री साइनोबैक्टीरिया का उपयोग करना बेहतर हो सकता है क्योंकि ताजा पानी तेजी से कम हो रहा है।

5.3
हालांकि, समुद्री साइनोबैक्टीरिया आधारित शर्करा उत्पादन की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार के लिए उनकी विकास दर और शर्करा सामग्री में उल्लेखनीय सुधार करने की आवश्यकता है।

अनुसंधान परिणाम

6.1
इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी की एक टीम ने इसे हासिल किया है।

6.2
उन्होंने एक समुद्री साइनोबैक्टीरियम सिनेकोकोकस विशेष नाम पीसीसी 7002 को सफलतापूर्वक तैयार किया।

6.3
पीसीसी 7002 में उच्च विकास दर और शर्करा (ग्लाइकोजेन) की मात्रा दिखी।

6.4
इसे जब हवा में उगाया गया तो उसका विकास दोगुना हो गया और कोशिकाओं के ग्लाइकोजेन मात्रा में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर

(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

01 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट-2019

प्र. विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट-2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया है।
2. रैंकिंग पीएम 2.5 और पीएम 10 के स्तर की तुलना पर आधारित है।
3. इस सूची में दिल्ली एनसीआर का गाजियाबाद विश्व के सबसे प्रदूषित शहर के रूप में सामने आया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (c)

व्याख्या: हाल ही में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, 2019 को प्रदूषण ट्रेकर आईक्यू और ग्रीनपीस द्वारा जारी किया गया। इसकी रैंकिंग पीएम 2.5 के स्तर की तुलना पर आधारित है। सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले विश्व के 30 शहरों में 21 भारत के हैं। इस सूची में दिल्ली एनसीआर का गाजियाबाद विश्व के सबसे प्रदूषित शहर के रूप में सामने आया है। हालांकि भारत के समग्र वायु प्रदूषण में वर्ष 2018 के मुकाबले वर्ष 2019 में कमी देखने को मिली है। इस प्रकार कथन 3 सही है जबकि अन्य कथन गलत हैं।

02 राष्ट्रीय तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण

प्र. हाल ही में राष्ट्रीय तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लचीलापन (सीडीआरआर एण्ड आर)-सम्मेलन 2020 कहाँ सम्पन्न हुआ?

(a) राजस्थान (b) मुंबई
(c) हैदराबाद (d) नई दिल्ली

उत्तर: (d)

व्याख्या: नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) द्वारा आयोजित पहले "राष्ट्रीय तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण-सम्मेलन 2020" का समापन हुआ। इस सम्मेलन का उद्देश्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लचीलेपन के विभिन्न पहलुओं के बारे में मुद्दों और समाधानों की समझ को बढ़ाने के लिए हाल में हुई प्रगति का पता लगाना और उसके बारे में चर्चा करना था।

03 आदिवासी कल्याण के लिए पहल

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. ट्राइफेड (TRIFED) का मूल उद्देश्य आदिवासी लोगों द्वारा जंगल से एकत्र किए गए उत्पादों को बाजार में सही दामों पर बिकवाने की व्यवस्था करना है।
2. सरकार न्यूनतम वन उपज (एमएफपी) का समर्थन मूल्य तय करती रही है।
3. वन अधिकार अधिनियम, 2006 ने आदिवासियों के लिए पर्याप्त स्वामित्व अधिकार दिए हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (d)

व्याख्या: केन्द्र सरकार, आदिवासी समुदाओं की संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण के लिए देशभर में आदिवासी विद्यालय, आदिवासी संग्रहालय तथा आदिवासी अनुसंधान संस्थान स्थापित कर चुकी है। न्यूनतम वन उपज (एमएफपी) देश में आदिवासियों की आजीविका का प्रमुख स्रोत है। केन्द्र सरकार की यह प्रतिष्ठित योजना महुआ बीज, साल के पत्ते, इमली और शहद जैसे 24 वस्तुओं के लिए पारिश्रमिक मूल्य को वहन करने के लिए है। इस प्रकार तीनों कथन सही हैं।

04 राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन

प्र. राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस साल के बजट में राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के गठन का प्रस्ताव किया गया था।
2. इसे 2020-21 से 2023-24 के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा।
3. भारतीय तकनीकी कपड़ा बाजार 250 अरब डॉलर के वैश्विक तकनीकी बाजार का लगभग 30 प्रतिशत है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (b)

व्याख्या: हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन को मंजूरी दे दी है। तकनीकी वस्त्र ऐसे कपड़ा सामग्री और उत्पाद हैं, जो सौंदर्य विशेषताओं की बजाय मुख्य रूप से तकनीकी प्रदर्शन और कार्यात्मक गुणों के लिए निर्मित होते हैं। भारतीय तकनीकी कपड़ा श्रेणी का अनुमानित आकार 16 अरब डॉलर है, जो 250 अरब डॉलर के वैश्विक तकनीकी कपड़ा बाजार का लगभग 6 प्रतिशत है। इस प्रकार कथन 3 गलत है, जबकि अन्य कथन सही हैं।

05 भारतीय स्कूलों में छात्रों के लिए एआई आधारित मॉड्यूल

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के सहयोग से भारतीय स्कूलों में छात्रों के लिए एआई आधारित मॉड्यूल शुरू किया गया है।
2. नीति आयोग, को सभी 5000 अटल टिंकरिंग लैब में लर्न- इट- योर- सेल्फ (LEARN-IT-YOUR-SELF) मॉड्यूल को पेश करना है।
3. एआई आधारित मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य अटल टिंकरिंग लैब की पूरी क्षमता का लाभ उठाना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (b)

व्याख्या: नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एण्ड सर्विसेज कम्पनी (NASSCOM) के सहयोग से भारतीय स्कूलों में छात्रों के लिए एआई आधारित मॉड्यूल शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य एआईएम (AIM) की अटल टिंकरिंग लैब की पूरी क्षमता का लाभ उठाना है। यह बड़े पैमाने पर समाजों को लाभान्वित करने के लिए नए समाधान तैयार करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए भी कार्य करेगा। इस प्रकार कथन 1 गलत है जबकि अन्य कथन सही हैं।

06 महासागर आधारित उन्नत चेतावनी प्रणाली

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र (INCOIS) ने तीन महासागर आधारित उन्नत चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है।
2. भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र (INCOIS) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है।
3. यह संस्थान कोच्चि में स्थित है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (a)

व्याख्या: भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र (INCOIS) पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। यह संस्थान हैदराबाद में स्थित है। गौरतलब है कि INCOIS समुद्री क्षेत्र में उपयोगकर्ताओं के लिए कई नि:शुल्क सेवाएं प्रदान करता है। इस प्रकार कथन 1 सही है जबकि अन्य कथन गलत हैं।

07 सूक्ष्मजीवों से जैव ईंधन

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एण्ड बायोटेक्नोलॉजी की एक टीम ने एक समुद्री साइनौबैक्टीरिया सिनकोकोकस विशेष नाम पीसीसी-7002 को सफलतापूर्वक तैयार किया है।
2. साइनोबैक्टीरिया केवल समुद्री पानी में पाए जाते हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 1 और 2 (d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: (a)

व्याख्या: इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी के शोधकर्ता सिनकोकोकस विशेष नाम पीसीसी-7002 नामक एक समुद्री सूक्ष्मजीव की वृद्धि पर और उसमें शर्करा की मात्रा में सुधार के लिए विधि तैयार कर रहे हैं। इससे जैव ईंधन क्षेत्र को बढ़ावा मिल सकता है। साइनोवैक्टीरिया ताजा और समुद्री पानी दोनों में पाए जाते हैं। इस प्रकार कथन 1 सही है, जबकि कथन 2 गलत है।

7 महत्वपूर्ण तथ्य

प्रारम्भिक परीक्षा हेतु

01

02

04

01 हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले पॉल बिया किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति हैं?

-कैमरून

02 हाल ही में किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है?

-बिहार

03 'राष्ट्रीय विज्ञान दिवस' 2020 की थीम क्या है?

-विज्ञान में महिलाएँ

04 हाल ही में किस भुगतान बैंक ने दो करोड़ ग्राहकों का आंकड़ा पार किया है?

-इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक

05 हाल ही में होस्नी मुबारक का निधन हुआ, वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे?

-मिस्र

06 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों की निशानेबाजी और तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किस शहर में किया जाएगा?

-चंडीगढ़

07 हाल ही में गठित संजीव पुरी विशेषज्ञ समूह किस क्षेत्र से सम्बंधित है?

-कृषि निर्यात

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न

मुख्य परीक्षा हेतु

03

04

06

01 भारत सरकार द्वारा आदिवासियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही प्रमुख योजनाओं का वर्णन करें।

02 राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के उद्देश्यों को रेखांकित करें।

03 आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का संक्षिप्त परिचय देते हुए बताएं कि यह तकनीक भारतीय स्कूल व कॉलेजों में छात्रों के लिए किस प्रकार उपयोगी है?

04 अमेरिका-तालिबान शांति समझौते के मायनों को रेखांकित करें, साथ ही भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों की चर्चा करें।

05 भारत में ग्रामीण बैंकिंग की समस्याओं एवं चुनौतियों का वर्णन करें, साथ ही उपयुक्त सुझाव भी प्रस्तुत करें।

06 क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी बदल दी है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

07 महिलाओं के विरुद्ध अपराध की घटनाओं को तब तक नियंत्रित नहीं किया जा सकता जब तक कि सामान्यतया लोगों की सोच में परिवर्तन नहीं होगा। चर्चा कीजिए

7 महत्वपूर्ण खबरें

01 आयुष शब्दावली के मानकीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

आयुर्वेद, यूनानी और सिद्धा मेडिसिन के निदान-शास्त्र तथा उसकी शब्दावली के मानकीकरण पर दो-दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में 'पारंपरिक चिकित्सा (टीएम) निदान-शास्त्र संबंधी डेटा के संग्रह और वर्गीकरण पर नई दिल्ली घोषणा' को लागू करने के साथ संपन्न हुआ।

- इस सम्मेलन में पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को लेकर 16 भागीदार देशों में शामिल हैं- श्रीलंका, मॉरीशस, सर्बिया, कुराकाओ, क्यूबा, म्यांमार, इक्वेटोरियल गिनी, कतर, घाना, भूटान, उज्बेकिस्तान, भारत, स्विट्जरलैंड, ईरान, जमैका और जापान।
- यह सम्मेलन पारंपरिक चिकित्सा के निदान और शब्दावली के मानकीकरण के लिए समर्पित व्यापक स्तर की भागीदारी के संदर्भ में सभी महाद्वीपों को शामिल करने वाला अब तक का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय आयोजन है।
- इस सम्मेलन में 21वीं सदी की सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों के समाधान में पारंपरिक चिकित्सा की शक्ति और उसके महत्त्व को रेखांकित किया गया।

दिल्ली घोषणा

- पारंपरिक चिकित्सा के लिए आईसीडी को अपनाना और उनका कार्यान्वयन करना।
- स्वास्थ्य प्रणालियों में पारंपरिक चिकित्सा की प्रासंगिकता और विनियमन।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य में पारंपरिक चकित्सा को अपनाने पर मुख्य रूप से जोर दिया गया और विभिन्न प्रतिभागियों द्वारा अपने देश के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया गया।
- इस बात पर भी सहमति व्यक्त की गई कि आईसीडी के पारंपरिक चिकित्सा अध्याय के दूसरे मॉड्यूल पर काम तेज किया जाना चाहिए और इसके लिए हिस्सेदारी रखने वाले देशों के सहयोगात्मक प्रयासों की जरूरत है।
- घोषणा में स्वास्थ्य देखभाल के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पारंपरिक चिकित्सा के लिए देशों की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। इसने आगे चलकर डब्ल्यूएचओ के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण में आयुर्वेद, यूनानी और सिद्धा जैसे पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को शामिल करने का अवसर मांगा, जो दुनिया भर में स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए मानक नैदानिक उपकरण हैं।

02 वाराणसी में 4000 वर्ष पुराने शिल्प गाँव की खोज

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शोधकर्ताओं की एक टीम ने वाराणसी में 4000 साल पुराने शिल्प ग्राम की खोज की है। विशेषज्ञों के अनुसार यह प्राचीन ग्रंथों में दर्ज शिल्प ग्रामों में से एक है।

- वाराणसी से 13 किलोमीटर दूर बभनिया गाँव में प्रारंभिक सर्वेक्षण करने वाले विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के अनुसार उन्हें एक ऐसी बस्ती के निशान मिले हैं, जिसका वाराणसी से संबंधित साहित्य में जिक्र मिलता है।
- बीएचयू के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के अनुसार बभनिया गाँव में प्रारंभिक सर्वेक्षण में 8वीं शताब्दी ईस्वी से 5वीं शताब्दी ई० के बीच का एक मंदिर, 4,000 साल पुराने मिट्टी के बर्तन और 2 हजार साल पुरानी दीवारें मिली हैं।
- शोधकर्ताओं के अनुसार 'स्थल पर मिली मिट्टी की सामग्री के आधार पर कह सकते हैं कि संरचना 3500 से 4000 साल पुरानी है। वाराणसी से निकटता के कारण इसका खास महत्व है।
- पौराणिक कथाओं के अनुसार वाराणसी को 5,000 साल पहले हिंदू देवता भगवान शिव ने स्थापित किया था, हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि यह लगभग 3,000 साल पुराना है। शोधकर्ताओं के अनुसार "बभनिया स्थल" वाराणसी का एक छोटा उप-केंद्र हो सकता है।
- ज्ञातव्य है कि इस प्रकार के शिल्प गाँव इससे पहले भी खोजे गए हैं जैसे- सारनाथ, तिलमापुर, रामनगर तथा बनारस के अन्य क्षेत्र आदि।

- शोधकर्ताओं ने एक स्तंभ की भी खोज की है जिस पर कुषाण-ब्राह्मी लिपी में दो लेख खुदे हुए हैं। इससे भी ज्ञात होता है कि ये शिल्प गाँव 3500-4000 वर्ष पुराने हैं।

03 अमेरिका-तालिबान शांति समझौता

अफगानिस्तान में शांति के लिए अमेरिका और तालिबान के बीच कतर में ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। अमेरिका ने घोषणा किया है कि अगर तालिबान शांति समझौते का पालन करता है तो वह और उसके सहयोगी 14 महीने के भीतर अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों को वापस बुला लेंगे।

- माना जा रहा है कि अमेरिकी फौज के अफगानिस्तान से हटने के बाद तालिबान सशस्त्र संघर्ष छोड़ देगा। इस समझौते पर सहमति भी इसी उद्देश्य के लिए बनी है।
- दरअसल, तालिबान को देश में विदेशी सैनिकों के होने पर गहरी आपत्ति थी। तालिबान के साथ समझौता सफल रहता है तो यह भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान में 18 साल से चल रहे सशस्त्र संघर्ष का समापन होगा।
- तालिबान के साथ हुए समझौते के मुताबिक अमेरिका अफगानिस्तान में अपने सैनिकों की संख्या घटाकर 8,600 करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि अगर तालिबान किसी समझौते पर पहुँचने में नाकाम रहता है तो अमेरिका अपने सैनिकों की वापसी के लिए बाध्य नहीं है।
- अफगानिस्तान में अभी करीब 13,000 अमेरिकी सैनिक हैं। यह वह स्तर है जिसे अफगानिस्तान में अमेरिकी और नाटो बलों के कमांडर, जनरल स्कॉट्स मिलर ने उनके मिशन को पूरा करने के लिए आवश्यक बताया था।
- गौरतलब है कि कतर के दोहा में हस्ताक्षर का गवाह बनने के लिए लगभग 30 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि पहुंचे हुए थे।

शांति समझौते से भारत पर प्रभाव

- रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, अफगानिस्तान की जनता चाहती है कि भारत उनके देश में बड़ी भूमिका निभाए लेकिन शांति समझौते के बाद भारत की मुश्किलें कई गुना बढ़ने वाली है।
- तालिबान के साथ पाकिस्तान के अच्छे संबंध हैं। इस डील के बाद पाकिस्तान अपने आतंकी शिविर अपने देश से हटाकर अफगानिस्तान भेज सकता है।
- साथ ही दुनिया को दिखा सकता है कि वह आतंकियों का पोषण नहीं कर रहा है। इससे वह आसानी से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएगा।

04 स्ट्राबेरी फिंच पक्षी केरल में देखा गया

हाल ही में स्ट्राबेरी फिंच पक्षी को केरल के अक्कूलम झील के आस-पास के क्षेत्र में देखा गया है। स्थानीय रूप से इस पक्षी को कुमकुम कुर्वी के नाम से जाना जाता है।

- 'एस्ट्रीलडीडेई परिवार की गौरेया के आकार की इस पक्षी को स्वास्थी (Swasthi) फाउंडेशन के दो पक्षी विद्वान अनूप पालेडे और सूरज चूडाल ने देखा था।
- विदित हो कि संरक्षणवादियों और प्रकृति फोटोग्राफरों की टीम ने इन दुर्लभ पक्षियों के घोंसले का भी पता लगाया है।
- विदित हो कि अक्कूलम झील के आस-पास 30 से अधिक पक्षियों को देखा गया था। विशेषज्ञों के अनुसार अककूलम झील इन पक्षियों के प्राकृतिक आवास की तरह है। क्षेत्र में अनियंत्रित शहरीकरण और प्रदूषण इस झील के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। IUCN स्ट्राबेरी फिंच जिसे अवदावत (Avdavat) या लाल मुनिया भी कहा जाता है, के साथ-साथ अक्कूलम झील के संरक्षण की तत्काल आवश्यकता पर बल देता है।
- इसे IUCN द्वारा लीस्ट कंसर्न सूची में सूची-बद्ध किया गया है। ये पक्षी आमतौर पर उष्णकटिबंधीय एशियाई देशों के खुले खेतों और घास के मैदानों में पायी जाती हैं। ये अपने प्रजनन के मौसम में एक पिंजरे के पंक्षी के रूप में लोकप्रिय हैं।
- अमंडल या अवदावत प्रजाति की इस पक्षी का नाम अहमदाबाद शहर से लिया गया है जहाँ से प्राचीन समय में इन पक्षियों को पालतू पक्षी के रूप में निर्यात किया जाता था।
- **अक्कुलम झील:** अक्कुलम झील केरल के तिरुअनंतपुरम शहर से लगभग 10 किमी की दूरी पर स्थित है। वास्तव में अक्कुलम झील वेली झील का ही एक हिस्सा है, जहाँ यह समुद्र के साथ जुड़ जाती है। ज्ञातव्य है कि अक्कुलम पर्यटक गाँव इसी झील के तट पर स्थित है।

05 G20 का मंत्रिस्तरीय सम्मेलन सऊदी अरब में संपन्न

जी20 देशों के वित्त मंत्री और इनके केंद्रीय बैंकों के गवर्नर वैश्विक अर्थव्यवस्था के ताजा हालात तथा कोरोनावायरस के संक्रमण से उत्पन्न जोखिमों पर दो दिन तक मंथन करने के लिए सऊदी अरब के रियाद में एकत्रित हुए।

- इस दो दिन की चर्चा में वैश्विक अर्थव्यवस्था के परिदृश्य तथा वृद्धि की राह के खतरों से बचाव तथा वृद्धि के प्रोत्साहन के लिए संभावित नीतिगत उपायों पर चर्चा की गई।

- साथ ही विभिन्न देशों के मंत्रियों ने अर्थव्यवस्थाओं के डिजिटलीकरण के दौर में कराधान की चुनौतियों पर भी चर्चा किये।
- ज्ञातव्य है कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता सऊदी अरब ने किया। इस सम्मेलन का विषय '21वीं सदी के अवसरों की सभी के लिए पहचान' है। यह पहला मौका है, जब जी20 की अध्यक्षता किसी अरब देश के पास आयी है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टालिना जार्जीवा के अनुसार कोरोनावायरस का अर्थव्यवस्थाओं पर असर हो सकता है। जार्जीवा के अनुसार कोरोना वायरस के कारण अर्थव्यवस्थाओं पर असर अंग्रेजी के 'वी' अक्षर के आकार का हो सकता है। 'वी' आकार की अर्थव्यवस्थाओं से तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्थाओं से हैं जिनमें तेजी से गिरावट के बाद तेजी से सुधार भी होता है।
- ज्ञातव्य है कि जी20 की इस बैठक में चीन की तरफ से आधिकारिक भागीदारी नहीं दर्ज की गई बल्कि इस बैठक में सऊदी अरब में चीन के राजदूत अपने देश का प्रतिनिधित्व किए।

G-20

- **G-20** बीस देशों का एक समूह है जिसकी बैठक हर साल अलग-अलग देशों में आयोजित की जाती है। इस सम्मेलन में राज्यों के सरकार प्रमुखों के साथ उन देशों के केंद्रीय बैंक के गवर्नर भी शामिल होते हैं। इसकी स्थापना 26 सितंबर, 1999 की गई थी। इसका उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रणालीबद्ध महत्त्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एकसाथ लाने के लिए किया गया था।

06 ऑक्सीजन रहित जीव-हेन्नीगुया साल्मिनीकोला

हाल ही में वैज्ञानिकों ने जेलीफिश जैसा दिखने वाला ऐसा जीव (परजीवी) खोजा है जिसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। यह ऐसा पहला बहुकोशिकीय जीव है जिसमें माइट्रोकॉन्ड्रियल जीनोम नहीं है। यही वजह है कि जीव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है।

- लाल रुधिर कणिकाओं को छोड़कर इंसानों में मौजूद सभी कोशिशकाओं में काफी संख्या में माइट्रोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं जो सांस लेने की प्रक्रिया के लिए बेहद अहम हैं।
- इसे इजरायल की तेल-अवीव यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की टीम ने खोजा है। इसका वैज्ञानिक नाम हेन्नीगुया साल्मिनीकोला है। शोध के प्रमुख डयाना याहलोमी के मुताबिक, यह इंसानों और दूसरे जीवों के लिए नुकसानदायक नहीं है।
- शोधकर्ता डोरोथी ह्यूचन के मुताबिक, अब तक रहस्य है कि यह जीव कैसे विकसित हुआ। यह साल्मन फिश में एक परजीवी के तौर पर पाया जाता है।
- जीव पर रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों ने इसे फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप से देखा। इस दौरान हरे रंग के न्यूक्लिएस तो दिखे लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए नहीं दिखा।
- एक ऐसा ही मामला 2010 में सामने आया था। इटली की पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता रॉबर्टो डेनोवोरो इससे मिलता-जुलता जीव खोजा था। जब माइक्रोस्कोप से उसे देखा गया तो साफतौर पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिखाई दी लेकिन रिसर्च के दौरान पता चला कि वह गहरे समुद्र में सालों तक रह सकता है, उसकी ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन सल्फाइड है, जबकि नए मिले जीव को हाइड्रोजन सल्फाइड की भी जरूरत नहीं है।

07 केरल में कॉलेजों और स्कूलों में विरोध प्रदर्शनों पर रोक

दिल्ली में हालिया विरोध-प्रदर्शनों के दौरान हिंसा में हुई मौतों के बाद केरल उच्च न्यायालय ने राज्य में स्कूल और कॉलेज परिसरों में किसी भी प्रकार के विरोध-प्रदर्शनों पर रोक का आदेश दिया है। हाईकोर्ट का यह फैसला विभिन्न कॉलेजों और स्कूल प्रबंधनों की ओर से दाखिल की गई उस याचिका की सुनवाई के दौरान आया है, जिसमें कहा गया था कि छात्र समूहों के ये विरोध या प्रदर्शन शांतिपूर्ण माहौल को बाधित करने के लिए किए जाते हैं।

- केरल हाईकोर्ट ने अपने आदेश में विरोध-प्रदर्शनों से शैक्षणिक संस्थानों में सामान्य कामकाज के बाधित होने की बात कहते हुए उनके परिसरों में छात्र समूहों के सभी तरह के आंदोलनों पर प्रतिबंध लगा दिया।
- किसी प्रकार के आंदोलन जैसे घेराव और परिसर में धरने पर बैठना आदि पर रोक लगाते हुए उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसे विरोध-प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए किसी को भी उकसाकर राजी नहीं किया जा सकता है।
- न्यायालय ने यह भी कहा कि किसी को भी अन्य छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। शैक्षणिक संस्थान शिक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए हैं, विरोध-प्रदर्शनों के लिए नहीं। न्यायालय ने कहा कि शैक्षिक संस्थानों को शांतिपूर्ण चर्चा का एक स्थान बनाया जा सकता है।
- अदालत ने पहले भी शिक्षण संस्थानों में धरना और हड़ताल जैसी राजनीतिक गतिविधियों के प्रति नाराजगी जाहिर की थी। साल 2017 में अदालत ने कहा था कि अगर किसी छात्र को इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो वह संस्थान से बाहर निकाले जाने या उसका दाखिला रद्द किए जाने के लिए खुद उत्तरदायी होगा।

7 महत्वपूर्ण बिंदु

साभार पीआईबी

01 बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 29 फरवरी, 2020 को चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे की आधारशिला रखी।

- यह एक्सप्रेस-वे सरकार द्वारा घोषित उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे की सहमति के बिंदुओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
- उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कर रही है, जो चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और जालौन जिलों से गुजरेगा। यह एक्सप्रेस-वे बुंदेलखंड क्षेत्र को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे और यमुना एक्सप्रेस-वे के रास्ते से जोड़ेगा। साथ ही बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह एक्सप्रेस-वे 296 किलोमीटर लंबा है।
- भारत को भूमि प्रणाली, जहाज और पनडुब्बियों से लेकर लड़ाकू विमानों, हेलीकाप्टरों, हथियारों और सेंसरों जैसे रक्षा उपकरणों की भारी जरूरत है।
- इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार ने लखनऊ में निवेशकों के शिखर सम्मेलन के दौरान 21 फरवरी, 2018 को उत्तर प्रदेश में रक्षा औद्योगिक गलियारा स्थापित करने की घोषणा की थी। इसी का परिणाम है कि सरकार एक्सप्रेस-वे को लेकर तेज गति से कार्य कर रही है।
- केन्द्र सरकार ने आरंभ में 6 क्लस्टरों की पहचान करते हुए गलियारा स्थापित किया है। ये हैं- लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अलीगढ़, कानपुर, आगरा, जिनमें से बुंदेलखंड क्षेत्र-झांसी और चित्रकूट में 2 क्लस्टर तैयार किए जा रहे हैं। वास्तव में सबसे बड़ा क्लस्टर झांसी में तैयार किया जाएगा।
- ऐसी भूमि जिसपर खेती नहीं की गई है, उसे झांसी और चित्रकूट दोनों जगहों पर इस एक्सप्रेस-वे के लिए खरीद लिया गया है। इससे क्षेत्र के गरीब किसानों को लाभ मिलेगा।

02 पुनर्गठित कंपनी आदेश, 2020

केन्द्र सरकार ने 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के राष्ट्रीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कॉर्पोरेट प्रशासन ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से कंपनी आदेश, 2020 (सीएआरओ, 2020) को अधिसूचित किया है।

- सीएआरओ 2020, 1 अप्रैल, 2019 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्षों के लिए पात्र कंपनियों के वित्तीय विवरणों के ऑडिट के लिए लागू है।

- **सीएआरओ, 2020 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:**
  - सीएआरओ, 2020 में सीएआरओ, 2016 की तुलना में कुछ अतिरिक्त खण्ड शामिल हैं और सीएआरओ, 2016 के मौजूदा खण्ड को ऑडिटर्स से विस्तृत टिप्पणी प्राप्त करने के लिए फिर से तैयार किया गया है।
  - ऐसी अचल संपत्तियों का विवरण देने के लिए एक विशेष प्रारूप उपलब्ध कराया गया है जिनका मालिकाना हक कंपनी के नाम नहीं है लेकिन उनका वित्तीय विवरणों में उल्लेख किया गया है।
  - बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कार्यवाही के विवरण का खुलासा करना और पता लगाना है कि क्या कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में इसका उल्लेख किया है।
  - ऑडिटर को इस बारे में विशेष विवरण प्रदान करना है कि क्या कंपनी को उसकी मौजूदा सम्पत्तियों की गारंटी के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल 5 करोड़ से अधिक की कार्यकारी पूंजी सीमा की मंजूरी दी गई है और क्या ऐसे बैंकों या संस्थानों को कंपनी द्वारा त्रैमासिक रिटर्न और विवरण प्रस्तुत करना कंपनी की एकाउंट बुक के साथ हुए अनुबंध में शामिल है।
  - कंपनी द्वारा ऋणों या अन्य देनदारियों के पुनर्भुगतान या किसी अन्य ऋणदाता के ब्याज के भुगतान में अवधि और बकाया राशि के बारे में जानकारी देने के लिए एक विशेष प्रारुप निर्धारित किया गया है।
  - वित्तीय वर्ष और उसके पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में हुई नकद हानि की राशि के बारे में सूचना देनी होगी।
  - ऑडिटर से कंपनी के बारे में यह रिपोर्ट देना अपेक्षित है कि क्या कंपनी किसी बैंक वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता की जानबूझकर बकायादार घोषित हुई हैं।

- ऑडिटर को यह भी रिपोर्ट करनी होगी कि क्या टर्म ऋण उसी उद्देश्य में लगाए गए हैं जिनके लिए वे प्राप्त किए गए थे? ऐसा नहीं होने पर ऋण में इस प्रकार किए गए बदलाव और उसका कहां उपयोग किया गया है इस बारे में जानकारी देनी होगी।
- ऑडिटर को वर्ष के दौरान कंपनी के ऑडिट में प्राप्त गंभीर शिकायतों पर विचार करना है।
- ऑडिटर को यह रिपोर्ट करना है कि क्या कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाण-पत्र के बिना किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियों का संचालन किया है?

- सीएआरओ, 2020 से कंपनियों के वित्तीय विवरणों पर ऑडिटरों द्वारा रिपोर्टिंग की समग्र गुणवत्ता में काफी सुधार आने की उम्मीद की जा रही है। इससे कंपनियों के वित्तीय मामलों में अधिक पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ावा मिलेगा। इसके द्वारा भारतीय कंपनियों में और उनके द्वारा निवेश के अधिक प्रवाह आने की उम्मीद है।

03 एसिम्प्टोमैटिक मलेरिया के लिए निदान

जैव प्रौद्योगिकी विभाग के भुवनेश्वर स्थित संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज (आईएलएस) और बेंगलुरु के जिग्सा बायो सॉल्यूशंस के वैज्ञानिकों की एक संयुक्त टीम ने एक पद्धति की खोज की है जो मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को आसान कर सकती है।

- इस रोग की जांच के लिए सामूहिक जांच एवं उपचार कार्यक्रमों में और मलेरिया नियंत्रण के उपायों की निगरानी में माइक्रोस्कोपी तथा प्रोटीन प्रतिरक्षा आधारित रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) का उपयोग किया जाता है।
- हालांकि इसके तहत करीब 30 से 50 प्रतिशत कम घनत्व वाले संक्रमण छूट जाते हैं जिसमें आमतौर पर दो परजीवी प्रति माइक्रोलीटर होते हैं। इन्हें अकसर स्पर्शोन्मुख वाहक के रूप में देखे जाते हैं जो संक्रमण के मूक भंडार के रूप में कार्य करते हैं और वे मच्छरों के माध्यम से रोग को संक्रमित करने में समर्थ होते हैं।
- स्थानिक क्षेत्रों में स्पर्शोन्मुख वाहक की पहचान मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रमों की एक प्रमुख बाधा मानी जाती है। इसके लिए अधिक संवेदनशीलता के साथ नैदानिक तरीकों की आवश्यकता है।
- भारत के मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों से एकत्र किए गए क्लीनिकल नमूनों के सत्यापन से पता चलता है कि यह जांच पारंपरिक तरीकों से लगभग 20 से 100 गुना अधिक संवेदनशील थी। इसके जरिये सबमाइक्रोस्कोपिक नमूनों का भी पता लगाया जा सकता है।
- अत्यधिक संवेदनशील अन्य तरीकों की तुलना में यह चार से आठ गुना बेहतर दिखी। साथ ही यह प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम के लिए बेहद खास दिखी जो मलेरिया परजीवी की सबसे घातक प्रजाति है। जबकि प्लास्मोडियम विवैक्स प्रजाति के साथ क्रॉस-रिएक्शन नहीं किया जो अपेक्षाकृत कम घातक मलेरिया की पुनरावृत्ति का सबसे प्रमुख कारण है।
- भारत ने वर्ष 2030 तक मलेरिया का उन्मूलन करने और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा विकसित किया है जो प्रभावित क्षेत्रें में स्पर्शोन्मुख वाहक की पहचान करता है और उसके संक्रमण को साफ करता है। यह नई खोज इसमें मदद कर सकती है। डीबीटी के जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद ने इस परियोजना का वित्त पोषित किया है।

04 बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल

केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डा. हर्षवर्धन ने कहा है कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

- डॉ. हर्षवर्धन ने दिल्ली में सघन मिशन इन्द्रधनुष (आईएमआई 2.0) पर एक विशेष सामुदायिक कार्यक्रम की शुरुआत करने के अवसर पर यह बात कही।
- आईएमआई को 2017 में गुजरात के वडनगर से शुरु किया गया था और अब इसे ग्राम स्वराज अभियान और विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से और सशक्त बनाया जा रहा है। दिसंबर 2019 से आईएमआई 2.0, 27 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 272 जिलों में चलाया जा रहा है।
- 'ऐसे में जब हमारे पास 90 प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य है, हम सभी को यह सुनिश्चित करना है कि हर बच्चे को बीमारियों से बचाव का टीका लगाया जाए।
- यह तब और भी जरूरी हो जाता है जब हमारे पास सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) के तहत इस तरह के तमाम

टीके मौजूद हैं।'

- सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 की शुरूआत के साथ ही देश में पांच वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत्युदर में कमी लाने और 2030 तक बीमारियों से बचाव के जरिए बाल मृत्यु दर में कमी के सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने का मौका है।
- देश के 190 जिलों में टीकाकरण अभियान पर कराए गए सर्वेक्षण के नतीजों में पाया गया कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-चार की तुलना में पूर्ण टीकाकरण के मामलों में 18.5 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।
- दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 के बीच सघन टीकाकरण अभियान के तीन चरण पूरे हो चुके हैं। इसके तहत 29.74 लाख बच्चों और 5.90 लाख गर्भवती महिलाओं को टीके लगाए गए। इसका एक और चरण मार्च 2020 में शुरु किया जाएगा।

05 सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली

वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) प्रेरित प्रौद्योगिकी में क्रांति ला दी है, जिसने भारत को जवाबदेह, उत्तरदायी और पारदर्शी बनाने के लिए अधिकार संपन्न बना दिया है। वित्त मंत्रे ने रेखांकित किया कि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) अब विभिन्न बहुपक्षीय और वैश्विक मंचों पर सार्वजनिक वित्त प्रबंधन के क्षेत्र में एक विशिष्ट ब्रांड के रूप में पहचानी जाने लगी है।

- श्रीमती सीतारमण ने लेखा महानियंत्रक की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि न केवल यह देश को अधिक दक्ष और प्रभावी बना रहा है, बल्कि सार्वजनिक वित्त का उपयोग करने में अधिक प्रभावपूर्ण भी बना रहा है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सीजीए का काम सराहनीय है, क्योंकि अपने दृष्टिकोण में कुशल और प्रगतिशील होने के साथ-साथ प्रौद्योगिकी को बनाए रखना एक निरंतर चुनौती है जिससे कि सीजीए सफल रहा है।
- भारतीय सिविल लेखा सेवा संगठन ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए 8.46 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को सीधे अपने बैंक खातों में पीएम-किसान भुगतान को सक्षम करने के द्वारा अपनी आईटी ताकत साबित की है।

- **भारतीय सिविल लेखा सेवा (आईसीएएस) के बारे में:**
    - केंद्र सरकार ने 1976 में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में एक बड़ा सुधार आरंभ किया। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को केंद्र सरकार के खाते तैयार करने की जिम्मेदारी देकर लेखा परीक्षा और लेखा कार्यों को अलग कर दिया गया। लेखांकन कार्य को सीधे कार्यकारी के नियंत्रण में ले आया गया। इसके बाद भारतीय नागरिक लेखा सेवा (आईसीएएस) की स्थापना हुई।
    - आईसीएएस को प्रारंभ में सी एण्ड एजी (कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा की शर्तों) संशोधन अधिनियम, 1976 में संशोधन के अध्यादेश के माध्यम से भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा (आईए एवं एएस) से लिया गया था। इसके बाद विभागीयकरण केंद्रीय लेखा (कार्मिक स्थानांतरण) अधिनियम, 1976 को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और 8 अप्रैल, 1976 को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई।
    - इस अधिनियम को 1 मार्च, 1976 से प्रभावी माना गया था। आईसीएएस द्वारा हर साल 1 मार्च को षसिविल लेखा दिवसष के रूप में मनाता है।
    - भारतीय सिविल लेखा संगठन भारत सरकार के भुगतान, लेखा, आंतरिक लेखा परीक्षा और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणालियों की दक्षता बढ़ाने के लिए तथा आईटी का लाभ उठाने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। 2009 में आरंभ की गई सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) इस पहलू को प्रदर्शित करने वाली संगठन की प्रमुख परियोजना है।

06 पिगमेंटरी डिसऑर्डर पर शोध को बढ़ावा

पिगमेंटरी डिसऑर्डर यानी वर्णक विकारों की समस्या को समझने के लिए किए जा रहे अध्ययन को वेलकम ट्रस्ट/डीबीटी इंडिया गठबंधन के जरिये अधिक सफलता मिलने की उम्मीद है।

- यह गठबंधन जैव प्रौद्योगिकी के लिए फरीदाबाद स्थित क्षेत्रीय केंद्र के सहायक प्रोफेसर डॉ. राजेन्द्र के. मोतीयानी पर एक इंटरमीडिएट फेलोशिप पुरस्कार प्रदान करता है। इस पुरस्कार में पांच वर्षों की अवधि के लिए 3.60 करोड़ रुपये का अनुदान शामिल है।
- शारीरिक वर्णकता एक महत्वपूर्ण रक्षा तंत्र है जिसके द्वारा त्वचा को हानिकारक यूवी विकिरणों से बचाया जाता है। अकुशल वर्णकता त्वचा के कैंसर का कारण बनती है जो दुनिया भर में कैंसर से जुड़ी मौतों के प्रमुख कारणों में से एक है।
- इसके अलावा, वर्णक विकार (हाइपो और हाइपर पिगमेंटरी दोनों) एक सामाजिक कलंक माना जाता है और इसलिए वह लंबी अवधि के लिए मनोवैज्ञानिक आघात पहुंचाता है और रोगियों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।

- इस अनुसंधान परियोजना का उद्देश्य लक्ष्य करने योग्य उन नोवल मॉलिक्यूलर पदार्थों की पहचान करना होगा जो वर्णक प्रक्रिया को संचालित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- इसके अलावा, शोधकर्ता वर्णक विकारों के उपचार के लिए वाणिज्यिक तौर पर उपलब्ध दवाओं का नए सिरे से उपयोग करने की कोशिश भी करेंगे। आगे चलकर इस परियोजना से समाज को दोतरफा लाभ- यूवी-प्रेरित त्वचा के कैंसर से सुरक्षा और वर्णक विकारों के लिए संभावित उपचार का विकल्प- होने की उम्मीद है।
- वर्णकता जीवविज्ञान क्षेत्र में अब तक मुख्य तौर पर मेलेनिन संश्लेषण को विनियमित करने वाले एंजाइमों को समझने और उनके बायोजेनेसिस एवं परिपक्वता में शामिल मेलेनोसोम प्रोटीन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हालांकि, मेलेनोसोम बायोजेनेसिस और मेलेनिन संश्लेषण जटिल प्रक्रिया है और संभवतः अन्य कोशिकीय प्रक्रिया को संचालित करता है।
- डॉ. मोतियानी और उनकी टीम द्वारा अलग-अलग वर्णक मीलेनोसाइट पर इससे पहले किए गए अधययन से पता चला था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम (ईआर) और माइटोकॉन्ड्रिया वर्णकता के महत्वपूर्ण संचालक हैं।
- इस नई परियोजना का उद्देश्य वर्णकता में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया सिग्निलिंग पाथवे की भूमिका को चित्रित करना और प्रमुख एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉड्रियल प्रोटीन की पहचान करना है जो वर्णकता को नियंत्रित करते हैं।

07 प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना मंजूरी

केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रे श्रीमती हरसिमरत कौर बादल की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति (आईएमएसी) की बैठक में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की 'यूनिट' स्कीम के तहत 406 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना वाली 17 राज्यों की कुल 32 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

- ये परियोजनाएँ लगभग पंद्रह हजार व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के सृजन के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों पर केन्द्रित हैं।
- आधुनिक प्रसंस्करण तकनीकों से कृषि उपज को ज्यादा दिन सुरक्षित रखा जा सकता है, जिससे किसानों की लगातार आमदनी होती रहती है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय किसानों को उपभोक्ताओं से जोड़ने में खाद्य प्रसंस्करण की महत्वपूर्ण भूमिका है।

ये परियोजनाएँ लगभग पंद्रह हजार व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के सृजन के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों पर केन्द्रित हैं।

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अर्थव्यवस्था की दिशा में बेहतर योगदान के लिए किसानों, सरकार और बेरोजगार युवाओं के बीच कड़ी का काम कर सकता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार व्यवसाय में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सभी प्रयास कर रही है और इसके तहत इसने संयुक्त उपक्रम, विदेशी सहयोग, औद्योगिक लाइसेंस और 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाइयों के प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का आधुनिकीकरण विस्तार, और मूल्य वर्धन करना है तथा उनकी प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं को बढ़ाकर कृषि उपज की बर्बादी को रोकना है।
- अपनी असीम क्षमताओं के कारण खाद्य क्षेत्र में विकास की बड़ी संभावनाएँ हैं। पिछले पांच वर्षों से इसकी सकल वार्षिक विकास दर (सीएजीआर) करीब 8 प्रतिशत बनी हुई है। जिन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, वे देश के 100 कृषि जलवायु क्षेत्र में हैं।
- देश के खाद्य प्रसंस्करण बाजार के 14.6 प्रतिशत सीएजीआर की दर से 2020 तक बढ़कर 543 अरब डॉलर का हो जाने की संभावना है। 2016 में यह 322 अरब डॉलर था।
- खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने 2016-20 की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपये की लागत से पीएमकेएसवाई योजना शुरू की है। इसके तहत मेगाफूड पार्क लगाने, एकीकृत प्रशीतन गृहों कीशृंखला, मूल्यवर्धन अवसंरचना, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए अवसंरचना विकास तथा अन्य कई तरह की सुविधाएँ शुरू की गई हैं।

7 महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ (ग्राफिक्स के माध्यम से)

भारत में रामसर नामित आर्द्रभूमि

01 ब्यास संरक्षण रिजर्व

- हाल ही में रामसर कन्वेंशन के तहत भारत के 10 नये स्थलों को आर्द्रभूमि (Wetland) के रूप में मान्यता दी गई है। गौरतलब है कि कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर नगर (ईरान) में 1971 में एक सम्मेलन आर्द्रभूमि (Wetland) के संबंध में आयोजित किया गया था। इस कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य आर्द्रभूमि के पारितंत्रों का संरक्षण प्रदान करना था। यह कन्वेंशन संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता (Multilateral Environmental Agreement) के अंतर्गत आता है। भारत ने 1 फरवरी 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर किये।
- 'ब्यास संरक्षण रिजर्व' पंजाब राज्य के उत्तर-पश्चिम में स्थित है। यह मुख्यत: ब्यास नदी का ही विस्तार है, जिसकी लंबाई 185 किमी है।
- यह नदी हिमालय की तलहटी से निकलकर हरिके बैराज तक जाती है, जहाँ से इसकी धाराएँ अनेक जल प्रणालियों में बंट जाती हैं।
- इस नदी में कई छोटे-छोटे द्वीप, बालू के टिले स्थित हैं साथ ही लटकती हुई जल धाराएँ जैवविविधापूर्ण समृद्ध पर्यावरण का निर्माण करते हैं।
- इस रिजर्व में पक्षियों की लगभग 500 प्रजातियाँ पायी जाती हैं तथा इस रिजर्व के बहाव क्षेत्र में मछलियों की लगभग 90 प्रजातियाँ पायी जाती हैं।
- ज्ञातव्य है कि ब्यास संरक्षण रिजर्व ही एक मात्र ऐसा रिजर्व है जहाँ 'सिंधु डॉल्फिन' की संकटग्रस्त प्रजाति पाई जाती है। इसके अलावा अन्य विलुप्त प्राय प्रजातियों में मशीर (टोरपुटितोरा), हॉग हिरण (एक्सिस पोर्सिनस) और ओटर शामिल हैं।
- विदित हो कि घड़ियालों के विलुप्त होने के 30 साल बाद वर्ष 2017 में 47 घड़ियाल इस नदी में छोड़े गए। यह कार्यक्रम घड़ियालों की संख्या फिर से बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था।

02 नंदुर मध्यमेश्वर

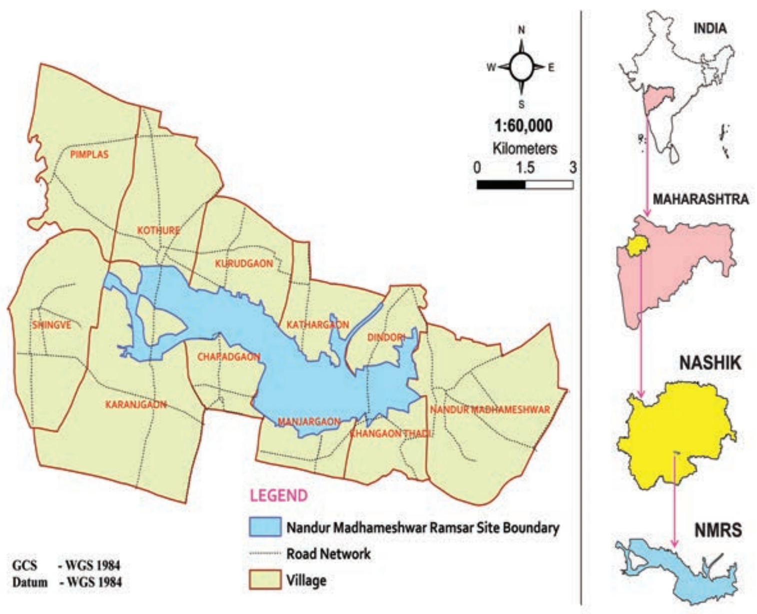

- नंदुर मध्यमेश्वर स्थल दक्कन के पठार पर स्थित है। यह स्थल झीलों, दलदलों और तटीय जंगलों का मिश्रित स्थल है।
- गोदावरी और कदवा नदियों के संगम पर बाँध के निर्माण ने एक संपन्न वेटलैण्ड नंदुर मध्यमेश्वर बनने में मदद की है। ज्ञातव्य है कि इस बाँध का निर्माण आस-पास के क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। वर्तमान समय में ये साइट जैव विविधता हॉट-स्पॉट के साथ-साथ बाढ़ के खिलाफ प्रतिरोध का भी काम करता है।
- पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की वर्षा छाया क्षेत्र के कारण आस-पास के अर्ध-शुष्क परिस्थितियों के विपरीत ये स्थल विविध जीवों का निवास स्थान है। इस स्थल पर विभिन्न जीवों के लगभग 536 प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- इस स्थल में भारत की कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियों जैसे- तेंदुओं और भारतीय चंदन का निवास स्थान है।
- इसके अलावा यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए आश्रय प्रदान करता है जैसे- देओली माइनोव, भारतीय गिद्ध तथा श्वेतवर्ण गिद्ध आदि।
- शहरी विकास, जल के अमूर्त प्रभाव के साथ आम जलकुंभी सहित कुछ आक्रमक प्रजातियों के कारण यह स्थल-असुरक्षित है।

03 पार्वती अरगा पक्षी अभयारण्य

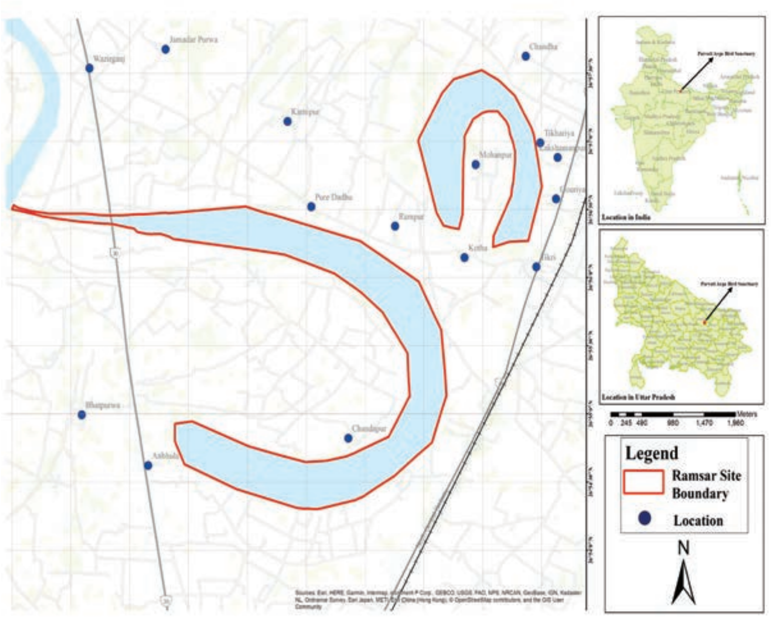

- पार्वती अरगा पक्षी अभयारण्य में दो ताजे पानी की झीलें हैं जो कि 'यू' आकार की हैं। इस पक्षी अभयारण्य में विविध प्रकार के पक्षी शामिल हैं जिनमें जलीय पक्षियों की अधिकता है।
- पार्वती अरगा अभयारण्य जलीय पक्षियों के लिए महत्वपूर्णआवास उपलब्ध कराता है।
- ज्ञातव्य है कि इस अभयारण्य में सालाना लगभग 100,000 पक्षी अपने अण्डे सेने (Roosting) और प्रजनन (Breeding) के लिए आते हैं।
- यह अभयारण्य भारत एवं विश्व की कुछ संकटग्रस्त गिद्ध प्रजातियों की शरण स्थली भी है।
- जैसे- गंभीर रूप से संकटापन्न सफेद धारीदार गिद्ध, भारतीय गिद्ध तथा संकटापन्न मिस्र के गिद्ध आदि इस अभयारण्य में देखे जा सकते हैं। इस पक्षी अभयारण्य के आस-पास प्राचीन मंदिरों के स्थित होने से पर्यटकों के आगमन में वृद्धि हुई है जिससे इस क्षेत्र में विभिन्न पर्यावरणीय समस्याएँ जैसे भू-जल स्तर का कम होना, प्लास्टिक प्रदूषण और अपशिष्ट प्रबंधन की समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं।

04 साण्डी पक्षी अभयारण्य

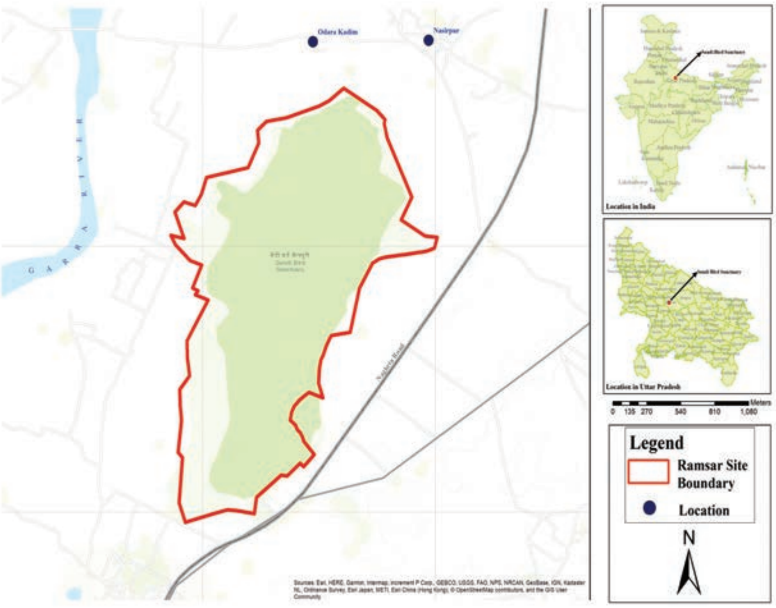

- साण्डी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित है।
- यह अभयारण्य लगभग तीन किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है।
- यहाँ पक्षियों की अनेक प्रजातियाँ देखी जा सकती हैं। यहां घूमने के लिए सबसे उचित समय दिसम्बर से फरवरी है।
- विश्व में पक्षियों की लगभग 10000 प्रजातियाँ हैं, उनमें से लगभग 1300 प्रजातियाँ भारत में पायी जाती हैं और उसमें से उत्तर प्रदेश में 550 प्रजातियाँ पायी जाती हैं।
- कुछ प्रजातियाँ केवल सर्दियों के मौसम में ही दिखलायी पड़ती हैं जैसे- पर्पल सनबर्ड इत्यादि। उल्लेखनीय है कि ये प्रवासी पक्षी साण्डी पक्षी विहार में दिसम्बर के दूसरे सप्ताह के आसपास दिखलाई पड़ती हैं।
- साण्डी पक्षी अभयारण्य दक्षिण एशियाई प्रजातियों की कुल आबादी की 1% से अधिक का निवास स्थान है।

05 केशोपुर-मियां कयुनिटी रिजर्व

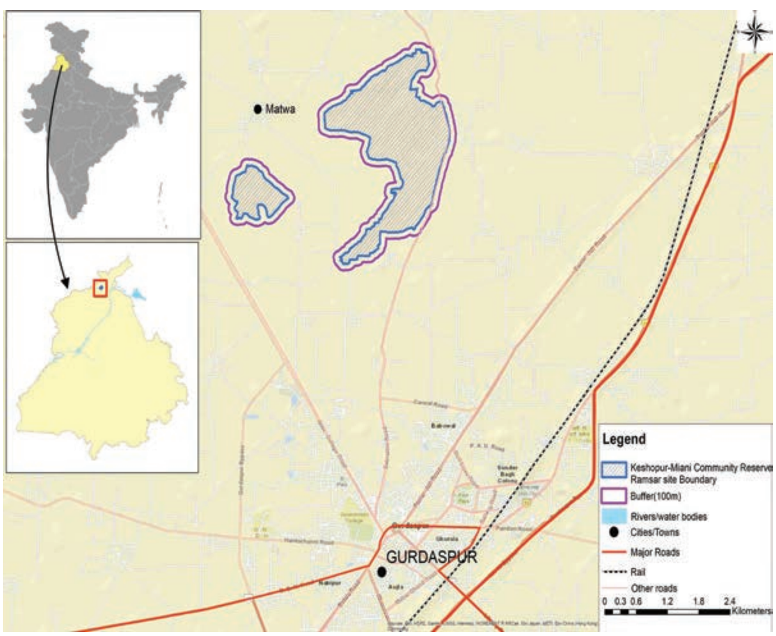

- केशोपुर-मियां कम्युनिटी रिजर्व पंजाब राज्य में स्थित है।
- यह रिजर्व वार्षिक वर्षा, दलदली भूमि तथा आर्द्रभूमि से आच्छादित है।
- यह रिजर्व मानवीय गतिविधियों के कारण बहुत प्रभावित हुआ है। यहाँ कमल बहुतायत में उगाये जाते हैं।
- इसमें वनस्पतियों की लगभग 344 प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- यह रिजर्व एक समुदाय का बेहतर उदाहरण है जिससे कि मानव से लेकर जीव-जंतुओं तक की आवश्यकता की पूर्ति होती है।
- मौजूदा समय में यह रिजर्व सामान्य पोचर्ड (अयथ्या फेरिना) और लुप्तप्राय चित्तीदार तालाब कछुआ (जियोक्लेमिस हैमिल्टन) को लेकर चर्चा में है।
- केशोपुर कम्युनिटी रिजर्व को इंटरनेशनल स्तर के वेटलेंड रामसर साइट घोषित किया गया है।

06 सुंदरवन

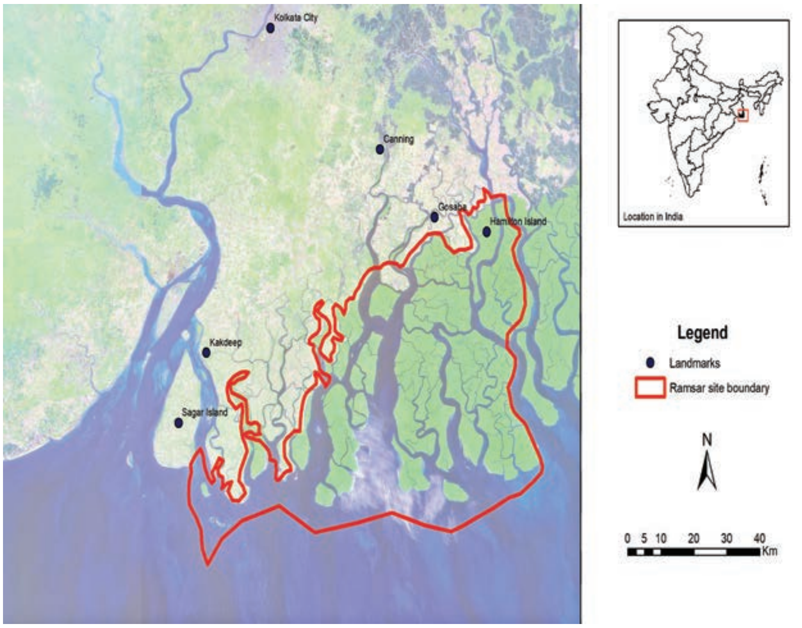

- हाल ही में रामसर कन्वेंशन के तहत भारतीय सुंदरवन को वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस का दर्जा दिया गया है। सुंदरवन भारत तथा बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र में विशाल और संगठित मैंग्रोव वन है।
- सुंदरवन में बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में सैकड़ों द्वीपों, नदियों, सहायक नदियों और सरिताओं का नेटवर्क शामिल है।
- डेल्टा के दक्षिण-पश्चिमी भाग में स्थित, भारतीय सुंदरवन देश के कुल मैंग्रोव वन क्षेत्र का 60% से अधिक है। यह भारत में 27वां रामसर स्थल है और 4,23,000 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ अब देश में सबसे बड़ा संरक्षित आर्द्रभूमि है। इसमें 2,000 वर्ग किमी के मैंग्रोव वन और क्रीक इसे आर्द्रभूमि हेतु आदर्श स्थल (site) बनाते हैं।
- भारत में पश्चिम बंगाल के पूर्वी कोलकाता वेटलैंड्स सहित 37 साइटों को वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर आर्द्रभूमि स्थलों के रूप में मान्यता प्राप्त है।

07 सरसई नावर

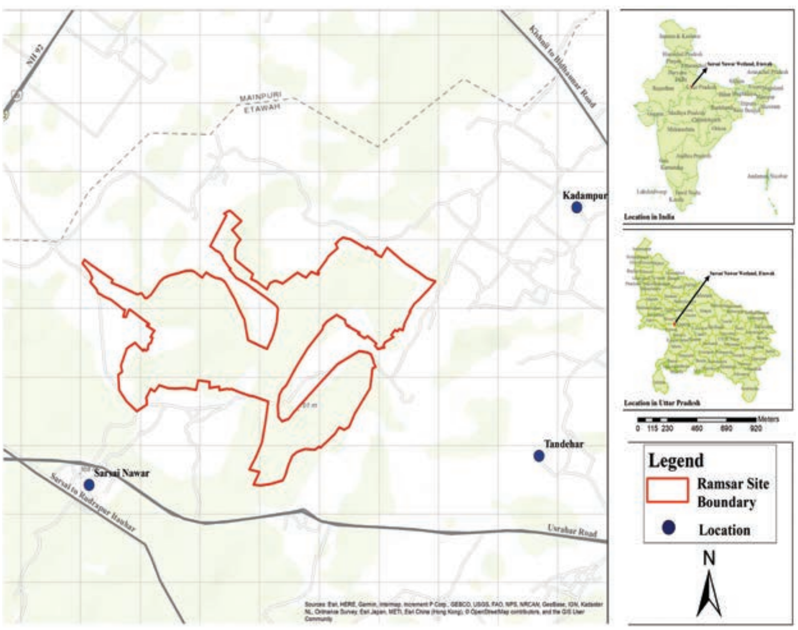

- उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में, सरसई नावर आर्द्रभूमि स्थित है।
- इसमें दो छोटी झीलें शामिल हैं जो बड़ी संख्या में सारस क्रेन, व्हाइट इब्स और अन्य जलीय पक्षियों को आकर्षित करती हैं।
- इसमें दुनिया की सबसे ऊंची उड़ान वाली पक्षियों, सारस क्रेन की खतरनाक प्रजातियों की एक बड़ी आबादी है। दस सारस क्रेन जोड़े नियमित रूप से यहाँ पैदा होते हैं, जो राजस्थान में भरतपुर के पक्षी अभयारण्य में प्रजनन जोड़े की संख्या से दोगुनी से अधिक है।
- यह आर्द्रभूमि मनुष्यों और वन्यजीवों के सह-निवास का एक उदाहरण है: अधिकांश भूमि पर खेती की प्रथाएं जलमार्ग के आवासों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- यह आर्द्रभूमि आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व का एक स्थल भी है, जहां हर साल हजारों तीर्थयात्रियों द्वारा दौरा किया जाता है।
- इसे बर्डलाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है।

उपलब्ध कार्यक्रम

कक्षा कार्यक्रम : प्रीमियम बैच, मेंस बैच, फोकस बैच, सीसैट बैच एवं वैकल्पिक विषय

अन्य कार्यक्रम : ऑल इंडिया टेस्ट सीरिज, क्रैश कोर्स, साक्षात्कार मार्गदर्शन कार्यक्रम (इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम), पीएमआई (PMI) एवं स्टूडेंट पोर्टल

उड़ान : उड़ान कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल (10+2) के ठीक बाद छात्रों के सामर्थ्य को संचार एवं परामर्श के माध्यम से समग्र रूप से सशक्त करना।

प्रवेश प्रारम्भ

नया सत्र: 2020-21

बैच आरम्भ: अप्रैल-मई 2010

अधिक जानकारी के लिए
सम्बंधित केंद्र पर संपर्क करें

or

Logon to : www.dhyeyaias.com

or

Call: 011-49274400

most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068 , **LUCKNOW (ALIGANJ)** 0522-4025825 | 9506256789, **LUCKNOW (GOMTINAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA** 0120 4254088 | 9205336037, 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR : BIHAR SHARIF – 9507021386, PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621| **GUJRAT** : AHMEDABAD - 9879113469| **HARYANA** : HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADYA PRADESH** : GWALIOR -9993135886, 9893481642 , JABALPUR - 8982082023, 8982082030, REWA – 9926207755, 7662408099| **MAHARASHTRA** : MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB** : PATIALA - 9041030070 , LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN** : JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND** : HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH** : ALIGARH – 9837877879, 9412175550 , AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, BIJNOR-8126670981, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962 , LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333, 7518373333, MORADABAD - 9927622221 , VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.in

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter (ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

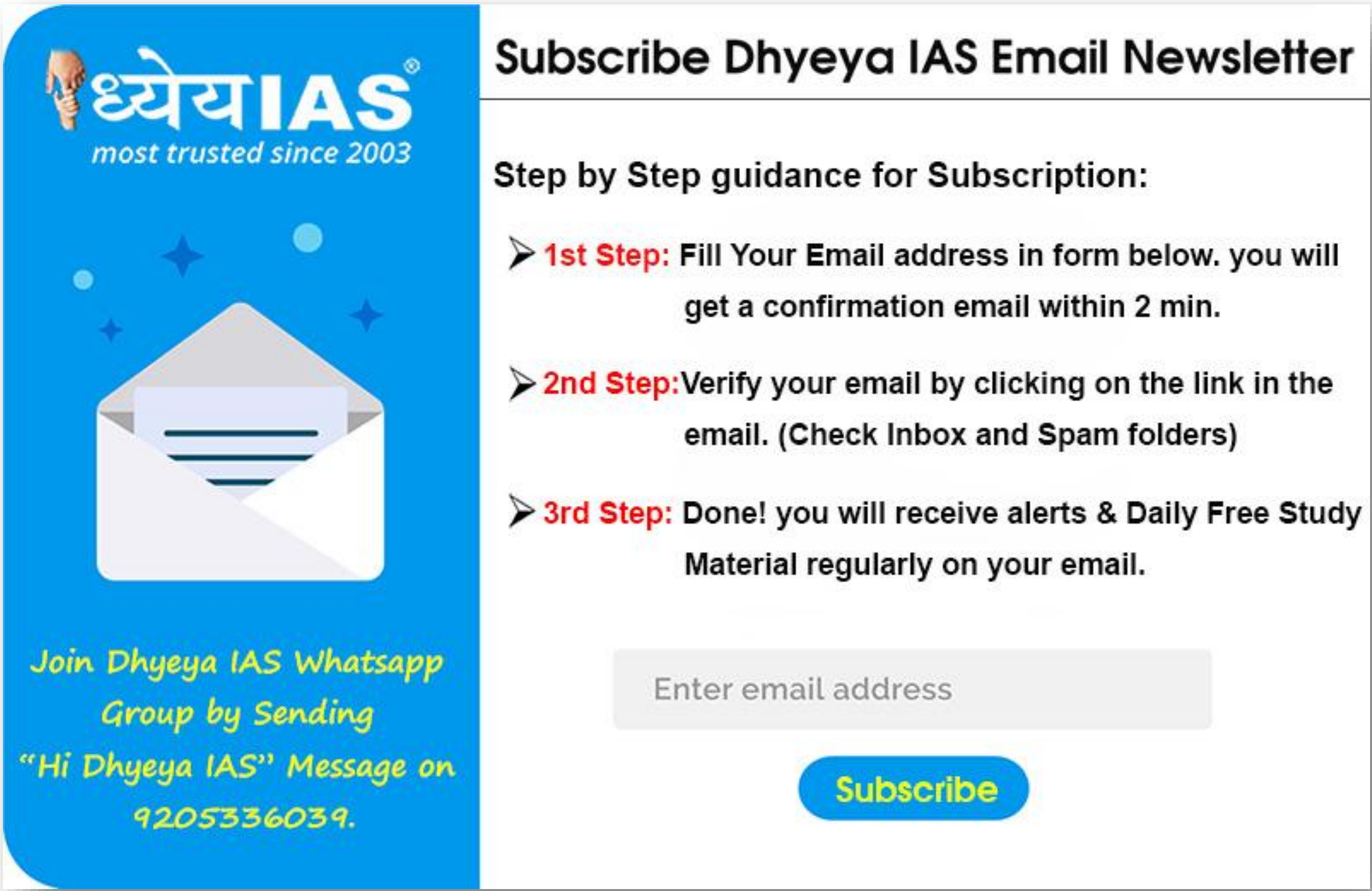

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400